साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Mob: +91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 16 | अंक 13 | प्रति सोमवार इंदौर, 25 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2/- रुपए

साढ़े 7 साल में जाहिल घोर लालची मोदी ने देश को हर तरह किया बर्बाद

बाप ने रेलवे स्टेशन का कबाड़ा बेटे ने पूरी रेलवे,तेल,भेल,गेल, सड़कें, बीमा, बैंक, एयर इंडिया बेंच लूटा

जाहिल मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए यह अच्छी तरीके से समझ लिया था की यह सब बिकाऊ है बस खरीददार चाहिए उसने आईएस की पूरी लॉबी का खरीदकर पहले गुजरात को लूटा और बर्बाद किया। फिर उसने पूरी आईएएस लॉबी को पूरे देश में खरीदकर ईवीएम के फ्रॉड से चुनाव जीत और पूरी भाजपा व आर एस एस के वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। 2014 में बैठते ही शांत कुबेर का खजाना हाथ लग गया तो देश दुनिया की यात्राओं पर निकल कर उसने रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों को लूटा और लाखों करोड़ बर्बाद किया। वहां अपने खास मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला का वहां पर व्यवसाय प्रतिनिधि बनकर राष्ट्र के हितों को त्याग उनके लिए मोटे कमीशन पर हथियार और कपड़ा खरीद कर लाया। जब उसकी विदेश यात्रा पर ज्यादा हल्ला मचा तो आते ही उसने देश के लोगों को झाड़ू पकड़ा कर देश के वित्तीय संस्थानों की और महंगाई यूट्यूब परमिशन के लिए जनता के जेबों की सफाई करवा डाली। स्वच्छ भारत की आड़ में भी उसने देश की नगर निगम पालिकाओं से लेकर पंचायतों के लिए हिंदुजा टाटा महिंद्रा के लाखों करोड़ के मोटे कमीशन पर वाहन खरीद डालें। देश के अंदर लाखों करोड़ के 6लाख गांवों से लेकर 660जिलों के 3000 से शहरों वह अर्धशहरीय क्षेत्रों तक शौचालय के नाम पर सरपंचों से लेकर अपने नेताओं विधायकों मंत्रियों सांसदों को मोटी कमाई करवाई। इस बीच वह अपने पूंजीपति मित्रों और खास तौर पर गुजरातियों का लाखों करोड़ का ना केवल स्टेट बैंक का वरन 29 राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा लगभग 50 लाख करोड़ से ज्यादा का दिया हुआ ॠण माफ करवा दिया। पूंजीपतियों के मोटे फायदे और छोटे व्यापार को खत्म करने के लिए उसकी जूस नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों वॉलमार्ट अमेजॉन आईटीसी युनिलीवर के साथ रिलायंस रिटेल किराना आदि के लिए जनता के खर्चो गवार खरीद-फरोख्त का डाटा इकट्ठा करने और उसकी मानसिकता को समझने के लिए कैशलेस इंडिया का नारा दिया और अपने ही गुजराती मित्रों की बनाई हुई पेटीएम फोनपे आदि के उपयोग के लिए जनता को विवश कर छोटे दुकानदारों छोटे व्यवसायियों को खत्म करने का षड्यंत्र किया जाता रहा जिसका सीधा फायदा अदानी अंबानी टाटा बिरला आईटीसी यूनिलीवर के साथ वॉलमार्ट अमेजॉन और चीनी कंपनियों से मोटा कमीशन लेकर उनके लाभ के लिए कार्य करता और मिलता रहा।

इस बीच वह दो तीन बार जो चीन होकर आया

उसके फायदे के लिए उसने ही लगातार मुंह में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, लोकल फार वोकल चिल्लाता रहा। पर यथार्थ में देश के 20 लाख से ज्यादा लघु और मध्यम उद्योगों को खत्म करने, करोड़ों का बेरोजगार करने का षड्यंत्र भी चलता रहा। जिसका फायदा भी चीन को मिलता रहा यह करते-करते सन 2016 में 8 नवंबर को उसने नोटबंदी की घोषणा कर दी। और मित्रों बस 50 दिन करते-करते 6 महीने तक नगदी के अभाव में देश के कृषि, ट्रांसपोर्ट, गारमेंट, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, खिलौना, खाद्य, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि सैकड़ों सेवा प्रदाता, उत्पादन कर्ता उद्योग को चौपट कर के रखा। जिससे लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे रहे। उसकी आड़ में लगभग 40 करोड़ जनधन खाते खुलवा कर जनता का 9 लाख करोड़ रू राष्ट्रीय कृत बैंकों में न्यूनतम शेष व अन्य शुल्कों के नाम पर हजम कर लिया। इसके बाद में भी जबकि बैंकों को संचालन लाभ करोड़ों में होता रहा परंतु बैंकों में जमा जनता के धन को हड़प कर में उसने 29 बैंकों को 12 बैंकों में बदल दिया। इसके साथ ही देश के आधारभूत सार्वजनिक सरकारी उद्योगों को को उन्हें पुणे में अपने पूंजीपति मित्रों को बेचकर मोटा लाल करवाने सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट करने का षड्यंत्र भी चलता रहा। अधिकांश उद्योगों में, सरकारी कर्मचारियों को कम करने के साथ अधिकांश सेवाएं मजदूर आदि आउटसोर्सिंग संविदा व ठेके पर रखे जाने लगे। स्वाभाविक था राज्यों में जहां लाखों कर्मचारियों कीसंविदा पर ठेके पर रखने पर 7000 से 10000 तक के वेतन के कारण क्रय शक्ति कम हो रही थी तो वहां वही पैसा धूर्त पूंजी पतियों के पास पहुंचा था जबकि यह षड्यंत्र यथार्थ में सरकारी उद्योगों संस्थानों विभागों को बेचने और पर नियंत्रण करने के षड्यंत्र का प्राथमिक हिस्सा है। ताकि अधिग्रहण करते समय उस में कार्यरत कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन खर्च करके अधिकतम लाभ कमाया जा सके।

(शेष पेज 5 पर)

डब्ल्यू एच ओ बनाम विश्व स्वास्थ्य के नाम डराओ लूटो संगठन

पिछले 19 महीने से विश्व में चल रहा कोरोना का पाखंड

विश्व स्वास्थ संगठन यथार्थ में अमेरिका और यूरोप की दवा, इंजेक्शन, विटामिन प्रोटीन और चिकित्सीय मशीन उत्पादक कंपनियों का षड्यंत्र कारी व्यवसाय संवर्धन संगठन है। जो पिछली एक शताब्दी से पूरी दुनिया में हर 10 साल में पहले कोई नई बीमारी फैलता है और उसकी आड़ में लाखों करोड़ की अपनी दवाइयां उपकरण सामग्री टीके बैचकर मोटी कमाई करता है। पिछले 40 सालों का इतिहास देखा जाए, तो 1980-90के दशक में उसने एड्स की बीमारी फेंकी। उसकी आड़ में उसने जांच किट, और तब से अभी तक लाखों करोड़ के कंडोम पूरे देश और दुनिया में बैचकर, भारत में परिवार और समाज की नैतिकता को खंड खंड बिखेर दिया। जबकि 40 साल गुजर जाने के बाद में भी आज तक ऐप्स करना तो कोई वायरस मिला न इलाज, क्योंकि ना कोई बीमारी थी और ना कोई इलाज। पर भयावह डर की कहानी ऐसी थी कि दुनिया के लोगों संभोग करने से पहले हमें कंडोम खरीद कर मोटी कमाई दो। फिर हेपेटाइटिस का डर भरा। उसकी आड़ में भी लोगों को कमजोर करने नपुंसक बनाने अरबों रुपए का टीका बेचा गया। 1988-89 से लेकर 93-94 तक और उसकी जांच की नई कहानी शुरू करके बीमारों को हर अस्पताल में लूटना शुरू कर दिया गया। फिर 2000 के आसपास शुरू किया गया। फिर उस चांडाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू कब ऐसा लाया पूरी दुनिया में वहां की सरकारों को खरीद कर वहां बैठे स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्णता एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और दवाइयों पर देश की जनता की चिकित्सा करके मोटी कमाई करते हैं और उन कंपनियों की करवाते हैं। ने अपनी फिर सलाह जारी कर दी और जानबूझकर मां की सरकारों को यात्रियों को उड़ानों को रोकने की नौटंकी शुरू कर आने जाने वाले यात्रियों की जांच के नाम पर फिर लूट मचाकर तांडव किया गया और जैसे ही उन हरामखोर चांडाल अमेरिकी कंपनियों का टीका पूरी देश दुनिया में बिकने लगा तो फिर बीमारी खत्म हो गई सन 2010 के दशक में फिर चिकनगुनिया आया या जानबूझकर अपने पैकेज्ड फूड में कीटनाशक और घातक प्रेजर्वेटिव मिलाकर अपनी मॉल चैन से बीमारी के रसायन खिलाकर जानबूझकर पहले बीमार बनाओ फिर अपना औषधियों मशीनों जांच किटों टीकों का हजारों गुना कीमत में माल बेंचो। और उसका 20-25% वहां की सरकारों, चिकित्सा मंत्रालयों मैं बैठे मंत्री, डॉक्टरों अधिकारियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों को, चिकित्सा संस्थानों को, निजी व सरकारी अस्पतालों को डॉक्टरों को, क्षेत्रीय मीडिया को खरीद कर चारों तरफ भय का वातावरण निर्मित कर, पहले करोड़ों की चिकित्सा के नाम पर हत्याओं और मौत का तांडव करवाओ। जबकि कोई बीमारी हो ना हो। पर उसकी आड़ में अपना मोटा लाखों-करोड़ों की जांच किट, दवाइयां चिकित्सा उपकरण और अंत में टीके को बेंचो। जैसा कि अभी करोना में हुआ और हो रहा है। अब चुंकि मोबाइल और इंटरनेट अस्तित्व में आ चुका है।

अमेरिकी और चीनी कंपनियों ने विश्व को बर्बाद करके कमाया लगभग $50 लाख करोड़

(शेष पेज 4 पर)

ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कं. की खरीदी का करें बहिष्कार

क्षेत्रीय दुकानदारों से करें खरीदी व लेनदेन का व्यवहार

ऑनलाइन के नाम पर चारों तरफ ना केवल ठगी बल्कि एक बार की खरीदी में भी आपके सारे मोबाइल का डाटा आपकी आदतें सब पर निगाह रखती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और ना केवल आपका आपके परिवार बच्चों और मूल्य जनरल वालों को भी शोषण करती हैं इस तथ्य को समझा जाना चाहिए। मोदी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रखेला और कठपुतली है ने हजारों करोड़ में मोटा कमीशन खाकर पूरे देश के उद्योगों व्यापार को नष्ट करने, पहले देश में कैशलेस का पाखंड किया बाद में नोटबंदी उसके बाद में जीएसटी और अभी 18 महीने से कोरोना की महामारी की आड़ में तालाबंदी था नाटक किया जा रहा है आपने देखा कि चारों तरफ पूरे देश में लगभग 30 करोड लोग न केवल बेरोजगार हुए बरन एक करोड़ से ज्यादा छोटी दुकानें व्यापार उद्योग नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी की मार झेल कर हमेशा के लिए खत्म हो गए। जिससे नुकसान हम सबका हमारे देश का ही हुआ। उनका मुंह देसी यही था कैशलेस, नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी में आखिर अदानी अंबानी टाटा बिरला अमेजॉन वॉलमार्ट की केवल मोटी कमाई हुई वरन उनकी संपत्ति अभी चौगुनी से 10 गुनी तक हो गई उसका भुगतान हम सब ने ही किया और जब तालाबंदी हुई तो हमें सहयोग करने में हमारी गली मोहल्ले के छोटे दुकानदारों से लेकर हमारे गलियों में सब्जी बेचने वाले एक ठेले वाले ही थे जिनको नगर निगम और पुलिस ने ना केवल मारा-पीटा उनकी तराजू बाट छीने, उनका पैसा लूटा, जेल में अंदर किया, के बावजूद भी बेचारे ठेले पर सब्जी भाजी व अन्य सामान बेचने वाले चोरी छुपे गलियों में घुसकर नगर सुधार में माल बेचकर ना केवल अपनी व परिवार की आजीविका चलाते रहे।

(शेष पेज 2 पर)

कोरोना महामारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पाखंड के विरुद्ध अकेला योद्धा जो पूरे विश्व में भय फैला लूटो संगठन व अमेरिका, चीन के विरुद्ध लगातार वीडियो लोड कर जागृत करता रहा जनता को, देखें

www.samaymaya.com

सीधे बिना किसी डाउनलोड, घंटी दबाने, सबस्क्राईब करने, दर्शक का डाटा चुराने संग्रहित करने की जालसाजी व सभी प्रकार की वसूली से मुक्त

facebook.com/samaymaya
twitter.com/samaymaya1
linkedin.com/samaymaya
vimeo.com/samaymaya

youtube.com/samaymaya
को 15 जून 20 को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

करोड़ों लोगों की मस्तिष्क की कुंठा और हाय राख न कर दे दुनिया को

पूरे विश्व की आबादी 780 करोड़ उसमें भारत की आबादी 140 करोड़ है पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन दो ऐसे राष्ट्र है जिनकी कंपनियां और वहां के शासक दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर अपनी तरह से निचोड़ कर कब्जा करना चाहते हैं। यह सारा पाखंड 6 महीने से चल रहा है। बेशक अमेरिकी कंपनियों वॉलमार्ट, अमेजॉन, युनि?लीवर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हथियार औषधि टीके निर्माता कंपनियां के साथ अमेरिका में बैठे हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संगठन यूनाइटेड नोटोरियस आर्गेनाइजेशन, जिसकी 50 से ज्यादा अन्य छोटी-छोटी शाखाएं जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन बनाम वर्ल्ड टेरिफिक ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिन्हें अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाती, हांकती और उस के माध्यम से दूसरे देशों की सरकारों, उनके मंत्रियों, अधिकारियों को खरीद कर उन देशों के प्राकृतिक स्त्रोतों, मानव निर्मित स्त्रोतों के साथ जनता को अपने बनाए धूर्तता और जालसाजी पूर्ण कानूनों में उलझा कर विश्व के अन्य देशों के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्त्रोतों पर अपनी मोटी कमाई के लिए कब्जा कर निचोड़ने का षड्यंत्र पिछले 50 साल से रच रही हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया में फैलाई महामारी के इस षड़यंत्र में यही उपरोक्त राक्षसी प्रवृत्ति की कहानी है। दुनिया में कोई करोना नाम की महामारी नहीं है। बस इन पाखंडी पूजी पतियों यथा वॉलमार्ट के वारेन बुफेट, अमेजॉन के जेन बेजोफ, फेसबुक और व्हाटसएप का जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट, जिसकी टीके बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल के सुंदर पिचई व अन्य अनेकों ने यही सारा पाखंड पूरी दुनिया में कोरोना है। महामारी के नाम पर भय फैला कर लाखों लोगों की जानबूझकर हत्या कर पाखंड को सही सत्य करने की नौटंकी की जा रही है। और भारत में तो इस महामारी के नाम पर हजारों लोगों की हत्या कर उनके शरीर से ह्रदय लीवर किडनी आंखें तक निकालकर बेची व कमाई की जा रही है। जिसका सच जो 3 महीने से ही अपने वीडियो के माध्यम से मैं देश दुनिया की जनता को बता रहा हूं। वह सामने आ चुका है। अभी जिस प्रकार से पूरे भारत में यहां के कलेक्टर कमिश्नर मुख्यमंत्री गृहमंत्री प्रदेश का और देश का जो लॉक डाउन करने का नाटक कर महीने से लगभग 35-40 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर 100 करोड़ को भूख से मार, 35 करोड़ बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट कर रहे हैं। चुनाव पूर्व ही 2014 से पहले का हीं पूर्व नियोजित षड्यंत्र है । वैसे तो इस षड्यंत्र की तैयारी सन 2000 से ही शुरू हुई थी जब रिलायंस ने हीं अपने रिलायंस फ्रेश स्टार्स की शॉपिंग मॉल की बुनियाद देश के 550 से ज्यादा शॉपिंग मॉल स्थापित करके नींव रख दी थी। उसके बाद में दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कांग्रेस और भाजपा ने लाखों करोड़ का चंदा लेकर हजम किया और 2005 से कानून खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की तैयारी कर सन 2006 में पास कर दिया गया जिसकी कोई खबर जनता को और मीडिया को नहीं दी गई उसमें एक अंगूठा टेक आम सांसद को भी हजार हजार करोड का कानून पर अंगूठा लगने का मोटा धन मिला। यही कारण है कि सारे सांसद विधायक और नेता इस महामारी के पाखंड पर मुंह में दही जमा कर बैठे हैं।हरामखोर चांडालों की फौज। इसके लिए देश को बंद कर सारे सारे छोटे व्यवसायियों को ठेले वालों छोटे दुकानदारों फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करने वालों फुटकर विक्रेताओं छोटी दुकानों उद्योगों मंडियों बाजारों को बर्बाद करके लोगों से रोजगार छीन कर उनको बेरोजगार बनाना है। अपने पूंजीपति बापों मुकेश अंबानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जिन्होंने उसे मोटा चुनावी चंदा दिया था। जिसे उसने अपने घोषणापत्र में ही शामिल कर दिया था। अब इसके बाद में भी मूर्खों ने वोट दिया तो भुगतना तो पड़ेगा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो आय नहीं होगी और जब आय नहीं होगी। तो आयकर नहीं देना पड़ेगा। अब स्वाभाविक सी बात है पिछले 140 दिन से 30 करोड लोग बेरोजगार बैठे हैं तो आय ही नहीं है। तो आयकर कैसा? घोषणापत्र को ही पूरा कर रहा है वो चांडाल, और अस्पतालों में मौत या हत्यायें भी पिछले अप्रैल से सबसे ज्यादा उन्हीं निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यम वर्गीय हिंदुओं की हो रही है। जिन्होंने ज्यादा जोश में ताली थाली बजाई थी। दिए जलाए थे। अब पूरे देश में अस्पतालों में मुसलमानों की मौत नहीं हो रही। क्योंकि पूरे देश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कोरोना के नाम पर स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम घुसने में सक्षम नहीं है। अन्यथा वो घेर कर वही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का इलाज कर देते हैं। सुनो और समझो अंधभक्तों, यह मत समझ लीजिए कि जनता जानवर है आप जैसा कहोगे वह जनता मजबूरी में करती व चलती रहेगी। यथार्थ में दुनिया के यूरोप और एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देशों के 600 करोड़ लोगों की बेरोजगारी और भूख से बेजार उन गरीबों की मस्तिष्क की कुंठा और हाय विश्व भर में रखे 10000 से ज्यादा परमाणु बमों को विनाश की तरफ ले जाकर इन सारे चांडाल पूंजी पतियों के साथ अमेरिका के ट्रंप, चीन के जिनपिंग, रूस के पुतीन, भारतीय चांडाल मोदी, भारतीय घोर जालसाज पूंजीपति मुकेश अंबानी के सारे दुनिया पर और सारी संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझ हड़पने के मंसूबों को खाक करते हुए दुनिया को भी राख न कर दे। आखिर 600 करोड़ गरीबों के मस्तिष्क से उठती बेरोजगारी और भूख से जन्मी कुंठा की तरंगों का असर परमाणु युद्ध की तरफ ले जाकर परमाणु युद्ध में परिवर्तित हो जायेगा। शायद यह सच सत्ता और दौलत के नशे में चूर पूंजीपतियों को व सत्ताधशों को समझ में नहीं आएगा। परंतु 600 करोड़ लोगों की कुंठा षी उठी तरंगें बर्बाद नहीं जाएगी। जो ब्रह्मांड में घूम रही है। और उसी कुंठा का असर अभी लेबनान में देख लिया। आपने। कोई भी घटना दुर्घटना अपने आप नहीं होती उसके पीछे वहां फंसे हुए लोगों की अद्रश्य मानसिक चेतना व कुंठाओं का असर होता है। यह सच अभी समझ में आ जाना चाहिए। यह पाखंड कि मेरे पास यह सत्ता है, इतनी दौलत है। सब यहीं से लिया है, और यहीं पर छोड़कर जाना है। यह मेरा है। सब माया का भ्रम है। करोडों सालों से धरती पर यह सब लाखों पीढ़ीयों ने देखा व समझा है। फिर भी ऐसे पाखंडी सत्ताधीशो और पूंजीपतियों राक्षसों का लालच भयंकर विनाश को जन्म देता रहा है। शायद हम फिर उसी विनाश के मुहाने पर खड़े हैं।

भारतीय वन लूटो खाओ सेवा अधिकारी बढ़ते गए, 50% मैदानी स्टाफ की आवश्यकता

मध्य प्रदेश वन विभाग के खाकी वर्दी के वनैलों की फौज, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर नई नई नौटंकी

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर इंदौर का डीएफओ पंडवा हर बार हर पत्र के जवाब में एक बिंदु की जानकारी देने के लिए लिखता है और उस पर संदर्भ देता है सूचना आयोग का जबकि उसके सामने जाकर समझा कर आने के बाद में की सूचना आयोग कोई कानून नहीं है आपको जितना भी आवेदक जवाब मांगता है उन सब के जवाब देना है अपने बाप की जागीर नहीं है जो आप अपने मन से कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहोगे पर वह हरामखोर जिसने आते ही अपने निवास स्थान में लाखों रुपए का तो तोड़ फोड़ करवा कर रिनोवेशन करवाया पिछले 2 सालों में हम जितने भी वन मंडल अधिकारियों ने निवास कि आप सब ने जनधन से लूटा हुआ लाखों रुपए और निवास स्थान की मरम्मत और नवीनीकरण के नाम पर खर्च किया गया सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर यह जालसाज अपने आप को बचाने के लिए नए-नए सुबह छोड़ा करते हैं जबकि संसद ने बनाए हुए इस कानून में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ परंतु सूचना आयोग में बैठे घोर भ्रष्ट और जालसाज आयुक्तों की फौज मनमाने तरीके से अपनी मोटी कमाई के लिए जो निर्णय देती है उसको यह हरामखोर की फौज अपना आधार मान लेती है और फिर आवेदक को परेशान करती है आखिर जनधन का दुरुपयोग करने पर यदि नागरिक सूचना के अधिकार में जानकारी मांगता है तो एक बिंदु की जानकारी क्यों दी जाएगी आपको 50 पैसे की फोटोकॉपी के ?2 दे रहा है अभी तक जितनी जानकारी चाही गई है उतनी देनी चाहिए की अपेक्षा अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आयोग का निर्णय जो है कानून बनाकर लागू कर लेते हैं आयोग ने तो यह भी निर्णय लिया था और कानून व्यवस्था थी सन 2005 में ही की आपको धारा 4 के अंतर्गत जितना भी जन धन का उपयोग किया जा रहा है उसकी सारी जानकारी आपको ब्लॉक के साथ अपनी साइट पर लोड करनी है पर एंजल सालों ने जो कदम कदम पर भ्रष्टाचार करते हैं 17 साल के बाद में भी जानकारी लोड नहीं की तब कानून भूल जाते हैं कानून को कैसे तोड़ना बरोड़ा और अपने पक्ष में अपने हित को देखना के साथ अपनी जानकारी सार्वजनिक ना हो जाए छुपाने का हर संभव प्रयास करते हैं वैसे भी जितने भी डीएफओ इंदौर में बैठा ये जाते हैं। सभी भ्रष्टाचार से लूटे हुए धन को खर्च करके ही इंदौर में पदस्थ होते हैं पिछले दो ढाई साल में लगभग इंदौर में 5 से ज्यादा डीएफ हो वन मंत्री की तानाशाही और लूट के चलते मोटी वसूली के बाद ही बैठाए गए सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर की कितनी जमीन वन विभाग की जिस भू माफियाओं ने कब्जा कर कॉलोनी काठी प्लॉट बेचे उद्योग लगाए और कृषि भूमि के लिए कब्जा कर के पट्टे में बांट दी गई। के संबंध में चोरल और मानपुर के एसडीओ ने 4 महीने के बाद अभी तक जानकारी नहीं दी क्योंकि वहां पर बैठे हुए जालसाज अपनी कारगुजारी यों के संबंध में कैसे किसी को बता सकते हैं एक तरफ करोना काल में जनता ऑक्सीजन क्या भाव में दम तोड़ रही थी दूसरी तरफ पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए स्वयं वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी खासतौर से भारतीय वन सेवा बनाम भारतीय वन लूटो खाओ सेवा के अधिकारी अपनी मौज मस्ती में व्यस्त थे बेशक यह भी सच है महू मानपुर चोरल के साथ पूरे मध्यप्रदेश की सभी रेंजों कि वन भूमि पर वोटों की राजनीति के चलते भेड़िया झुंड पार्टी के शिवराज और उसके गिरोह के प्रदेश भर में फैले डकैतों ने जनजाति के लोगों से कब्जे करवा कर पट्टों का आवंटन करवा अवैध उत्खनन कृषि उद्योग कॉलोनी काटने ढाबे रेस्टोरेंट बनाने का कार्य पूरे मध्यप्रदेश में अभयारण्यों से लेकर नदी के किनारों पर अपने बड़े बड़े इस आज खुलने तक में किया यह हाल न केवल ओमकारेश्वर महेश्वर मंडलेश्वर से लेकर कान्हा खजुराहो तक सब जगह हुआ भेड़ियों झुंड पार्टी का गिरोह अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहा। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बेबस होकर चुपचाप वन विभाग को लूटता हुआ देख रहे हैं। वैसे वन विभाग में वृक्षारोपण के नाम पर प्रदेश के सभी रंगों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है यह बात सच है की बीट गार्ड से लेकर रेंजर डिप्टी रेंजर एसडीओ के साथ लिपिक वर्ग की भी पूरे विभाग में पूरे प्रदेश में भारी कमी होने के कारण 1-1 बीट गार्ड के पास 2-2,3-3 बीट का चार्ज होता है। वही हाल और अंजू के मामले में भी है एक रेंजर के पास 2-2,3-3 रेंज का प्रभार होने के कारण वनों पर पर्याप्त निगरानी और विकास कार्य नहीं हो पाता है। स्वाभाविक सी बात है, पर्याप्त स्टॉफ, साधनों, वाहन और हथियार के अभाव में वनों की, भू माफियाओं, कॉलोनी माफिया, पट्टा, वृक्ष कटाई, खनन, वनोपज, कृषि भूमि आदि माफियाओं से रक्षा कर पाना और 1 संपत्ति की सुरक्षा कर पाना संभव नहीं हो रहा है। सच तो यह भी है कि जानबूझकर और राजनीतिज्ञ नेताओं और राजस्व मंडल के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर कमिश्नर तक इन सब के गिरोह में शामिल होकर पूर्ण सहयोग करके वन भूमि, वन संपत्तियों को हड़पने का षड्यंत्र करते रहते हैं। जानबूझकर वन भूमि को राजस्व के दिखा कर उस पर ग्रामीणों की बसाहट से लेकर शहरीय क्षेत्रों से लगी जो भूमि जैसा कि इंदौर में सुपर कॉरिडोर, गोमटगिरी, हींकार गिरी, देवगुराडिया, रालामंडल, महू, मानपुर उप संभागों की भूमि पर चारों तरफ चल रहा है। की हाल भोपाल के चारों तरफ कि वन भूमि पर ग्रामीणों भू माफियाओं को पीछे छोड़ सैकड़ों आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने भी वन भूमि पर जोकि केरवा डैम के साथ भोपाल के चारों तरफ अच्छे खासे वनाच्छादित क्षेत्रों में कब्जे करके अपने फार्म हाउस बंगले रिसॉर्ट बना रखे हैं। आखिर वनों को नोचने के लिए जब आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी ही सबसे आगे हों। तो आमजन की बात तो बहुत दूर हो जाती है। वैसे मई-जून में जब पूरे प्रदेश में लखनऊ लगा हुआ था तो जानबूझकर ना केवल इंदौर के मनीष सिंह ने वरन प्रदेश के अधिकांश जिलों के कलेक्टरों ने वन कर्मियों की ड्यूटी जानबूझ कर उनकी बीट और रेंजों से हटाकर करुणा में लगा दी थी और उसकी आड़ में भारी वनों की सागवान के वृक्ष से लेकर अन्य अनेकों वृक्षों की कटाई करवाई गई?। तो समझा जा सकता है कि वनों को तहस-नहस करने के लिए जनता के द्वारा चुने हुए नेता पंच सरपंचों से लेकर विधायक सांसदों तक, प्रशासनिक सेवाओं में बैठे राजस्व के पटवारी से लेकर मंत्रालयों के सचिवालय तक बैठे आईएएस अधिकारियों की गिध्द निगाहें कैसे हर तरह से वनों को नष्ट करने पर लगी है। इसके विपरीत जिन भारतीय वन लूटों खाओ सेवा के एसडीओ डीएफओ से लेकर पीसीसीएफ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी है वह जानबूझकर हरामखोर ना केवल अपने भ्रष्टाचार वरन दूसरों के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भी सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा कदम कदम पर सूकरों की फौज बहानो की कहानी करती है। इसके साथ ही मुख्यालय में बैठे हरामखोर जालसाजों ने अपील लगाने पर डीएफओ की अपील डीएफओ को सुनने के अधिकार दे रखे हैं तो स्वभाविक है कि वह भ्रष्ट निकम्मा अपने खिलाफ अपनी अपील में अपने ही आदेश को कैसे ओझल कर जानकारी देगा आवेदकों को जिसे तत्काल बदला जाना चाहिए जिला स्तर का अधिकारी जब लोक सूचना अधिकारी है और धारा 5 में स्पष्ट है कि उसका वरिष्ठ अधिकारी अर्थात सीसीएस ही उसके अपील सुन सकता है। तो आखिर उस आदेश को पुनः लागू क्यों नहीं किया जाता ताकि जनता को मालूम पड़े कि वनों की भूमिका किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी, सत्ताधीश, मंत्री आदि दुरुपयोग कर बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को त्रासदी के रूप में विकास के नाम पर कानपुर जंगल सौंपकर उनका भविष्य चौपट करने पर तुले हुए हैं।

ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कं. की खरीदी का करें बहिष्कार

(पेज 1 का शेष)

वरन आपका आपके परिवार गली मोहल्लों का पेट भी भरते रहे। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर खरीदी करें जबकि दूसरी तरफ ऑनलाइन व्यापार करने वाली सारी कंपनियां वॉलमार्ट अमेजॉन रिलायंस फ्रेश किराना व अन्य शॉपिंग मॉलस एक सब तू अपनी मनमानी कीमतों पर माल भेजते हैं दूसरी तरफ आपका मोबाइल नंबर जाने पर वह आपके सारे मोबाइल की कॉल डिटेल्स से लेकर सारे संपर्क को वीडियो फोटो बैंक अकाउंट आदि का सारा डाटा भी चुरा लेते हैं। इसके साथ ही सभी शॉपिंग मॉल वालों ने अमेजॉन वॉलमार्ट रिलायंस फ्रेश रिलायंस रिटेल व अन्य सैकड़ों ने अपने-अपने ऐप बना रखे हैं और वह ऐप गूगल के माध्यम से डाउनलोड होता है जो डाउनलोड करते समय आपसे सारी अज्ञान कि आप के कॉल डिटेल संपर्कों की सूची, चित्र चलचित्र बैंक खाते आधार कार्ड नंबर व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके मोबाइल में कंप्यूटर में एकत्रित है सबको देखने, संग्रहण करने चुराने और उसका व्यवसायिक दुरुपयोग करने में करते हैं जो उस आपके आपके बच्चों परिवार माता पिता सबके लिए घातक होता है इसलिए किसी भी हाल में कोई भी ऑनलाइन खरीदी करने का, कार्य न करें। केवल वे कंपनियां जिनके अपने आप डाउनलोड किए हैं वरुण गूगल और उसके साथ जुड़े दुनिया के करोड़ों हैकर आपकी सारी जानकारी चुराकर न केवल बैंक अकाउंट खाली करते हैं आपकी संपत्ति आपके लेन-देन आपकी, परिवार के बच्चों बुजुर्गों महिलाओं की आदतों, पसंद खरीदी के तरीके आय के स्त्रोत सब पर निगरानी कर बाद में भविष्य में परेशान करते हैं जिसका अनुभव देश के कम से कम 25 से 50 कोलोंको हो चुका है इसके साथ ही साथ साल भर में दो से तीन करोड़ खातों में डकैती या बैंक जालसजिया आदि की जाती है। जिसके मूल में ऑनलाइन खरीदी भुगतान आदि का ही खेल होता है जो आपके भविष्य को बर्बाद करने आप को गुलाम बनाने मैं उपयोग किया जाएगा। फिर ऑनलाइन के पाखंड में कंपनी भले ही अच्छा माल बेच भी दे तो भी रास्ते में आपूर्ति करने वाले घर तक पहुंचाने वाले जो वह होते हैं जो भी सामान को बदल देते हैं वह भी आपका मोबाइल नंबर आदि को एकत्रित कर बाद में परेशान करते हैं और जिस तरह का सामान आपको ऑनलाइन पर दिखाया जाता है उस तरीके का सामान्य होने पर उनकी मनमानी कीमत के भुगतान करने पर भी आपको व संतुष्टि नहीं मिल सकती जो आप क्षेत्रीय दुकानदारों से माल को देख परख और भावनाओं का केक खरीदी करने में महसूस करते हैं इसलिए बेहतर होगा की सभी प्रकार की खरीदी को आप छेत्री दुकानदारों के पास जाकर माल को देखभाल खरीद और भाव ताव कर खरीदने के साथ वालों की गुणवत्ता अच्छी ना होने पर सीधे विक्रेता दुकानदार से बातचीत गारंटी वारंटी आदि का लाभ भी ले सकते हैं। ज्यादा ऑनलाइन की आधुनिकता ना केवल आपको वरुण आने वाली पीढ़ी और पूरी समाज को अभिशाप बन चुकी है इसको भी समझें और भविष्य को सुरक्षित रखें।

भेडियो झुंड पार्टी देश के सरकारी संस्थान बाप की जागीर नहीं

सरकार के विद्युत क. के निजीकरण के विरोध में करो आंदोलन

घोर जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी करता है भारी लूट पाखंड जालसाजी

देश में भेडियो झुंड पार्टी की सरकार के निजीकरण के विरोध में किसानों के आंदोलन के साथ सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से लेकर सभी सरकारी संस्थानों रेल, तेल,भेल, सेल, गेल, बैंक, बीमा कंपनियां, विद्युत, संचार, राज्य के लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं अभी सब को निजी करण में कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। इसके साथ ही सारे छोटे व्यवसाय, फैक्ट्रियां, लघु उद्योग, बाजार, मंडिया सबको खत्म करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन खाकर और महीना लेकर उनके हवाले करने का और जनता को लूटने का षड्यंत्र है इसलिए सबको बाहर निकल कर राष्ट्र स्तर पर भारी आंदोलन करना ही होगा। अन्यथा 12 लाख करोड़ की पावर ट्रांसमिशन लाइन की लगभग 25हजार किमी लंबी पूरे देश, प्रदेश में फैली हुई जिसके खंभों और तारों की कीमत ही हजारों करोड़ में थी केवल 1200 करोड में अडानी को सौंप दी गई जो पाकिस्तान को भी 8000 करोड रुपए महीने की बिजली आपूर्ति करता है उसका उद्देश्य ही प्रदेश की बिजली की हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन की चोरी करेगा और भुगतान सैकड़ों करोड़ में करके कुछ टुकड़ा मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री प्रधान सचिव ऊर्जा और संबंधित इंजीनियर को डालकर उनका मुंह बंद रखेगा। इसलिए उसने जानबूझकर पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ही कबाड़ के भाव 1200 करोड़ में 35 साल के लिए ले लिया। क्योंकि वहां पर स्टॉप भी कम था वेतन भी कम बांटना पड़ेगा और लूट की पूरी छूट मिलेगी कोई समझ में भी नहीं आएगा कहां से किसका पावर चोरी करके देश में प्रदेश में अंधेरा करके वह है राष्ट्र के चिर शत्रु पाकिस्तान को भी बिजली बेचकर मोटा धन कम आएगा जैसा कि उसने मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन मंगवा कर राष्ट्र की पूरी पीढ़ी को नशे में डूबो देने का षड्यंत्र किया। जानबूझकर पहले चांडाल मोदी ने उसे देश की कोयला खदानें बैची। बाद में कोयले की कमी दिखा कर उस पर मोटा धन वसूल करने का षड्यंत्र रचने के साथ में जानबूझकर उसकी आड़ में प्रदेश के 10 से ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन गृहों को बंद करने का षड्यंत्र रच दिया गया। सिंगाजी पावर प्लांट को कभी भी पूरी उत्पादन क्षमता से नहीं चलाया गया, बिरसिंहपुर पाली सारणी व अन्य के प्लांट पुराने हो जाने की आड़ में पिछले 15 सालों से उसको बंद करने का षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता में ना केवल कोयला वरन अन्य सुधार कार्य, व रखरखाव के कार्य में जानबूझकर लापरवाही पूर्ण तरीके से मोटा भ्रष्टाचार करके ही धन हजम किया जा रहा है।

जबकि 15000 मेगावाट से ज्यादा जल विद्युत के उत्पादन के साथ लगभग 15000 मेगावाट निजी क्षेत्रों से जिसमें इनका धन लगा हुआ है। विद्युत सौर और पवन ऊर्जा की खरीदने के समझौतों के अंतर्गत यह हरामखोर जालसाज शिवराज हजारों करोड रु हर महीने का भुगतान करता है। तात्पर्य यह है कि जब 30000 मेगा वाट बिजली बिना ताप विद्युत उत्पादन ग्रहों के आपके पास उपलब्ध है। तो प्रदेश की जनता को डराया क्यों जा रहा है? बेशक वह 15000 मेगावाट सौर व पवन विद्युत के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्रों में भारी भरकम अनुदान करों में छूट किस लिए दी गई थी जनता के पैसे से कि बिना एक यूनिट बिजली लिए उनको हजारों करोड़ का भुगतान भी करते रहो।

यथार्थ में जनता के हर उपभोक्ताओं को संगठित होकर ऐसी सारी सरकारी संस्थानों की बारीकि से न केवल जांच करनी चाहिए बल्कि उन पर उनके लेखों कार्यों वित्तीय लेनदेन और सभी प्रकार के अन्य कार्यों की निगरानी के लिए संगठित होकर कार्य करना ही पड़ेगा।

इसके साथ ही यह भेड़िए देश को लूट कर संस्थानों को बेचने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसके लिए जनता को सड़कों पर निकल कर न केवल आंदोलन करना पड़ेगा वर्णन पूरी सत्ता को पलटा कर जहां-जहां यह भेड़िए उत्पात मचा रहे हो उत्पात के बदले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन से उत्पात का जवाब देना ही होगा।

आखिर बिरसिंहपुर पाली, सारणी, खंडवा के ताप विद्युत गृह जानबूझ के बंद क्यों किए गए?

यह सरकारी ताप विद्युत ग्रहों को बंद करने का षड्यंत्र तो 2007-8 से ही शुरू कर दिया गया था।

जिससे बिजली संकट गहरा गया। ताकि निजी करण का रास्ता तैयार हो सके। फिर जिन बापों से, टाटा पावर अडानी, अंबानी पावर की ताप विद्युत, व अनेकों अन्य से सौर और पवन ऊर्जा खरीदने के हजारों करोड़ के एग्रीमेंट कर रखे हैं। उनको बिना एक पैसे की बिजली खरीदें भुगतान भी किया जा रहा है। पिछले 5-10 सालों से। फिर प्रदेश में जल विद्युत की जो 15000 मेगावाट की इकाइयां काम कर रही हैं।वह बिजली कहां है?

गांधी सागर, इंदिरा सागर, रानी अवंती सागर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर व अन्य की जानबूझकर निजीकरण के लिए वह जल विद्युत अन्य प्रदेशों को मोटे लाभ के लिए बेंची जा रही है व प्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है।

बिजली कर्मियों इसे भी समझो और जानबूझकर बिजली कटौती के संकट को उत्पन्न करके जनता को परेशान कर निजी करण के मार्ग को प्रशस्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको भी रोको।

भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी जहां जहां बैठता है वहां लूट पाखंड जालसाजी के सारे खेल खेले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर उसी खेल का हिस्सा है जो 40 से 200ङ तेज दौड़ता है। और कम आपूर्ति करने के बाद में भी ज्यादा रीडिंग दिखाता है और उसका सीधा सा खेल सच्चाई इस प्रकार पकड़ी जा सकती है। की कुल किसी शहरी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की गई उसमें से पारेषण विद्युत क्षति व चोरी घटा दीजिए। के बाद में कितनी आपूर्ति की गई और कितने युनिट की बिलिंग की गई। जिसमें 200 से 500ङ का अंतर आएगा। जिससे मोटी कमाई की जा रही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर लगाए गए थे।

स्मार्ट मीटर का खेल तो और भी ऊंचा है वह तो ऑफिस में बैठे ही बैठे एक सॉफ्टवेयर के एक कमांड देने मात्र से 25 50 से लेकर सौ दो सौ प्रतिशत तक रीडिंग भी ज्यादा दिखाएगा और उसके आधार पर बिलिंग तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से मनमाने तरीके से की जा रही है।

जनता के लुटे धन को खर्च करके, दूसरी ओर पूर्व में मैंने कल बताया था पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पुत्र मिलिंद और मंदार महाजन की कंपनी पिछले 20 सालों से बिजली के बिलों की बिलिंग मुद्रण का काम करती है। बिल विद्युत मंडल देता है। उस पर केवल नाम पता यूनिट और बिलिंग की राशि डाली जाती है जो मात्र खुला टेंडर निकालने पर 10-20 पैसे प्रति बिल का भुगतान होना चाहिए की अपेक्षा कुल बिलों में वसूली की बिलिंग की राशि का 1ङ उन डकैतों को मंडल से कंपनियां बनाने के बाद मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं की बिलिंग ज्यादा क्यों की जाती है। और वह काम बिना टेंडर के ताई के लौन्डों को लूटने के लिए ही इस तरीके से दिया गया है। जबकि यथार्थ में उन्हें बिल की राशि से क्या मतलब है। उन्हें प्रति बिल10-20 पैसे एक रुपए ?2 बिल दिया जा सकता है। बिना टेंडर निकाले यह काम क्यों और कैसे दिया गया। जब ताई संचार मंत्रालय में थी तब उसने टेलीफोन की बिलिंग का काम भी इसी आधार पर लिया था। और किस प्रकार उसके सांसद होने का लाभ उसकी औलादें न केवल बी एस एन एल की वरन पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के न केवल बिलिंग में बल्कि पूरा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड को हजम कर जाने में भी किया गया। चुपचाप लूट का खेल चलता रहा और वह ईमानदार बनी रही। दूसरी तरफ जो सैकड़ों करोड़ की मालकिन है। वह उसने उससे सुप्रीम एवियशन का पंजीयन करवा लिया था और वह नई एविएशन कंपनी शुरू करने की तैयारी में भी थे पर इतना सारा धन एक नंबर में दिखाना संभव नहीं हुआ। जहाज को पट्टे पर लेना दिखाने पर भी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए उसको शुरु नहीं किया गया।

किस प्रकार से बीएसएनएल और विद्युत मंडल की कंपनियों को ताई के डकैत सपूतों ने लूटा और डुबोया समझा जा सकता है। इसीलिए ताई आकाश त्रिपाठी को पहले इंदौर कलेक्टर के रूप में वहां से इंदौर में पालती रही विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में। फिर इंदौर के आयुक्त के रूप में, यह सच्चाई सारे समाचार पत्र वाले जानते हैं। पर किसी ने नहीं छापी। यही कारण है कि जब से यह भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी इन विद्युत वितरण कंपनियों में बैठे हैं हजारों करोड़ हर साल हजम कर जाते हैं और यही कारण है कि इतना सब कुछ लूटपाट के बाद में भी सरकारी राज्य का केंद्र का धन भी मिलने के बाद में कंपनियां घाटे में रहती हैं जबकि 25ङ स्टाफ जो है संविदा नियुक्ति पर काम कर रहा है तो आकर शरद धन कहां जा रहा है क्योंकि यह चांडाल डकैत जिन्हें बिजली का क ख ग घ नहीं आता। आखरी आकर करते क्या हैं यह केवल प्रताड़ित करते हैं पूरे स्टाफ को और खरीदी में रख रखाव में, भुगतान में, दिलों की कई गुना ज्यादा वसूली में भी अपनी वसूली करते हैं। जनता समझ सकती है किया के हर कदम कदम पर यह सफेद पोश सरकारी डकैत किस प्रकार देश को लूट कर अपना पैसा विदेशों में भेजते हैं। जब तक 2, 5, 10 दिन के लिए पूरे प्रदेश व देश में अंधेरा में नहीं करोगे। यह भूखे भेड़िए नरेंद्र दामोदरदास मोदी अमित शाह सारे भाजपाई मुख्यमंत्री मानेंगे नहीं। यह संक्षिप्त शुरुआती प्रदर्शन का प्रथम प्रयास है। एकजुट हो और हुंकार भरो। सारी ट्रेनें सारे उद्योग सारे हवाई अड्डे बैंक व्यवसाय इंटरनेट सबको विद्युतहीन कर पूरा देश जाम कर दो। दिखाओ शक्ति प्रदर्शन कर भय पैदा करो। बता दो देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं और कानून बनाना और थोपना बच्चों का खेल नहीं। सारे सार्वजनिक व निजी श्रमिक संघों, सभी विभागों के सभी क्षेत्रों के, सब को एकत्रित करो ना केवल विद्युत मंडल होगा बल्कि बैंकों बीमा कंपनियों सरकारी विभागों और रेलवे, तेल, भेल, सेल, बेल, गेल, मेल आदि सबको जोड़ो, एकत्रित करो और पूरा देश जाम करो।

आखिर जब आपके पास ताप और जल विद्युत की साडे 28000 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे आपको 12000 मेगावाट बिजली बाहर बैचनी पड़ रही है। तो हजारों करोड़ के पवन व सौर ऊर्जा के साथ अडानी रिलायंस मोसर वेयर, टाटा पावर व अन्य से बिजली खरीदी के जो अनुबंध हस्ताक्षर किए और उसमें हजारों करोड़ लुटाया जा रहा है। हर महीने तो आखिर क्यों?

फिर भी धड़ाधड़ सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन और खरीदी के 25 पैसे यूनिट की बिजली के ढाई रु मैं खरीदी के अनेकों अनुबंध करते रहो। दूसरी ओर अपने ही भाई वंदों, पूंजीपतियों की कंपनियों से मोटे कमीशन पर अनुबंध क्यों किए जा रहे हैं। साथ ही जब आप पुराने विद्युत मंडल की वर्तमान ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत ताप और जल विद्युत को उपयोग नहीं कर पा रहे, तो महंगी खरीद कर सस्ते में बिजली अन्य राज्यों को और कंपनियों को क्यों बेंची जा रही है। प्रदेश की जनता से महंगी बिजली की कीमत वसूल की जा रही है। तो आखिर क्यों?

विद्युत नियामक आयोग आखिर विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता ही क्यों देखता है? उसे पावर ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसमिशन और उत्पादन कंपनी की बैलेंस शीट भी देखनी चाहिए। इसमें वहां बैठे हरामखोर जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जिन्हें विद्युत का आ व स द नहीं आता और हजारों करोड़ रुपए हजम करके वह सारे फर्जी खर्चों को वसूली में जोड़कर जानबूझकर घाटे में पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद में घाटा दिखाकर कंपनियों को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं तो तुम्हारे कर्मचारी नेता अभियंता संघ नेता आखिर इन सब बारीक जालसाजियों को उजागर कर जनता के सामने व मिडिया में क्यों नहीं रखते? क्यों दबाव नहीं बनाते कि जब सरकारी कंपनियां है तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 में सारे के सारे बिजली खरीदी के अनुबंध, बिक्री व अन्य सारे दस्तावेज अपलोड क्यों नहीं करते और आखिर तुम्हारे बाप की जागीर है कि एक तरफ हजारों करोड़ हर महीने बिना एक पैसे की बिजली खरीदें भुगतान करते रहो।

मेंटेनेंस का आधा पैसा खा जाओ आधे पैसे से उल्टा सीधा काम करवा दो। और पूरा विद्युत मंडल के संरचना का निजी क्षेत्रों में देने के लिए बड़ा गर्क करो।

छोटी-छोटी बातों में उलझा के रखो और उलझ के रहो। और धीरे से पीछे से वो भेड़िया झुंड पार्टी के चांडाल सत्ता धीश पूरे कानून बनाकर कंपनियों को चटकाते रहें।

यह कब समझ में आएगा ग्रुप में मैने इसलिए नहीं जोड़ा था कि आपस में छोटी छोटी सी बातों को और ओबीसी को लेकर अपनी छोटी-छोटी सफलता के झंडे गाड़ कर उछलते कूदते रहो।

विद्युत मंडल की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा ग्रुप बनाया था। ताकि आप उसे एक मंच पर आकर तरीके से सत्ता के निजी करण के मंसूबों पर पानी फेर सको।

ना तो सारी जानकारियां आप के नेता और अभियंता इकट्ठा कर पाए ना तथ्यों को लेकर सामने रख पाए ना उसके आधार पर लड़ाई लड़ने की कोई रूपरेखा बनाई और औचित्य हीन विवादों में समय बर्बाद कर रहे हो सबका अपना सबका।

जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग सूचना के अधिकार में अंदर की जानकारी एकत्रित करके सारे जो एग्रीमेंट साइन किए हैं खरीदी के बिक्री के आपूर्ति के आउटसोर्सिंग के उन सब के तत्वों को निकाल कर इनकी बैलेंस शीट को चैलेंज करो इनकी खर्चों को इनकी बर्बादियों लूटपाट को सामने रखकर इनसे जवाब सवाल करो कि किस प्रकार से जानबूझकर कंपनियों को बर्बाद करके जनता को और कर्मचारियों को शोषण करके कंपनियों को घाटे में दिखाकर बेचने का सृजन किया जा रहा है उस पर तो कोई काम नहीं किया आप लोगों ने, जबकि सबसे पहले वही काम करना चाहिए और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उठो, तथ्यों की जड़ में जाकर तथ्य इखट्टे करो। फिर बताओ किस प्रकार से यह घोर डकैत सफेदपोष जालसाज हजारों करोड़ हजम कर जनता को लूटने का बिलों से उल्टे सीधे षडयंत्रों से एक तरफ जनता को बर्बाद कर रहे हैं 20 20 साल से संविदा के कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और हजारों करोड़ हजम कर पूरी कंपनियों को बर्बाद कर रहे हैं।

कब लड़ाई में जनता आपके साथ आएगी और तब आप सफल हो पाएंगे कानून फानून कुछ नहीं जैसे बनाए गए हैं। वैसे फाड़ भी दिए जाएंगे और रद्द कर दिए जाएंगे।

बशर्ते कि आप की लड़ाई के साथ ठोस आधार और जनता शामिल हो। इस को आधार बनाएं। बड़े अनुभवी अभियंताओं को साथ लें। जिनके पास ज्ञान अनुभव और जानकारियां हैं।

सत्ताधीश भेडियो को समझाओ, शक्ति प्रदर्शन से बतलाओ,

छल कपट ईवीएम की जालसाजी से सत्ता हथियाई।

7 साल में खूब तबाही मचाई। करोड़ों का नरसंहार किया। करोड़ों के रोजगार पर खूब प्रहार किया। पूंजीपतियों के लिए खूब देश बर्बाद किया। अब नहीं चलेगी की देश की बर्बादी। और मजदूर जाग गया है।

आप सब लोग छोटी-छोटी बातों की लड़ते रहना और वहां पूरे विद्युत मंडल तक बेड़ा गर्क हो जाएगा। यह समझ में आ रहा है। और हर सत्ताधीश चाहता कि आप छोटी-छोटी लड़ाइयों में उलझे रहो और वह पीछे बड़ा बड़ा खेल करते रहें।

दूसरी तरफ जब सबसे महत्वपूर्ण में इतना लिख रहा हूं बता रहा हूं वीडियो भेज रहा हूं।

साप्ताहिक समय माया

सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के आधार पर पदोन्नति ना देकर,

मोटी लूट व कमाई का साधन, प्रभार लेकर प्रभारी बनाना

घोर भ्रष्ट जालसाज शिवराज और उसके मंत्रिमंडल का गिरोह कर रहा मोटी वसूली

घोर भ्रष्ट जालसाज शिवराज और उसके मंत्रिमंडल का गिरोह पूरे मध्यप्रदेश में सभी विभागों में प्रभार का भारी खेल खेल रहा है। पिछले 6 साल से पूरे मध्यप्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति नहीं दी गई सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के आधार पर, जबकि भाई स्टेशन केवल सर्वोच्च न्यायालय ने जो पदोन्नत हो चुके हैं उनको पदोवनत ना करने के लिए दिया है। इसके बारे में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति यों पर कहीं कोई रोक नहीं है परंतु पदोन्नति अन्ना देकर अरबों रुपए प्रतिमाह की जो कमाई इसके गिरोह के मंत्रियों और स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है इसलिए जानबूझकर प्रदेश के लगभग 130 से ज्यादा विभागों में अधिकांश पद खाली होने के बाद में भी पदोन्नतियां ना देकर, प्रभारी बनाए जा रहे हैं और प्रभारी बनाने से पहले मोटा प्रभार पद और कमाई के अनुसार एकमुश्त लेने के बाद प्रभार में दिए गए सभी पदों के प्रभारी से मासिक रॉयल्टी के रूप में लगातार वसूल किया जा रहा है तो कौन मूर्ख होगा जो सभी कर्मचारियों अधिकारियों इंजीनियरों डॉक्टरों को स्थाई पदोन्नति देकर यह मुफ्त का मक्खन अपने हाथ से जाने देगा इसलिए हरामखोर डकैतों की फौज जानबूझकर भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों से मोटा प्रभार लेकर वरिष्ठ पदों पर प्रभारी बनाकर बैठा कर मोटी कमाई कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक वह प्रभार में है जब तक उससे मासिक वसूली भी करो और दूसरी तरफ उसे डराते धमकाते भी रहो जिस महीने वसूली बंद उस महीने लौटा के वापस अपने कनिष्ठ पद पर पहुंचा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक बार जो कर्मचारी अधिकारी बड़े पद पर बैठ गया पुनः पुराने पद पर जाने पर उसकी बेज्जती होने के साथ, समाज परिवार और विभाग में आसपास के लोगों की भी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। और उसके बदले में यह हरामखोर चांडाल आपराधिक मानसिकता के मंत्री पद पर बैठे और उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मोटी कमाई करते रहते हैं इसलिए प्रभार के खेल में हाईवे से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री की भी चांदी कट रही है इसलिए प्रभार के खेल को जिंदा रखने के लिए जानबूझकर यह चांडाल डकैतों का गिरोह सभी कर्म चारियों अधिकारियों को स्थाई पदोन्नतियां देना नहीं चाहता। दूसरी तरफ क्योंकि सभी प्रभार में है किसी को भी केंद्र सरकार की तरह पद प्रभारी जितने दिन भी जिस पद के प्रभार में और पद पर काम किया है?। उस पद का वेतन दिया जाता है।पर मध्यप्रदेश में नियमों की धज्जियां बिखेरते हुए वह प्रभारी किसी भी पद का हो। वेतन उसे मूल पद का ही दिया जाता है। इससे सरकार को वित्तीय प्रभार भी नहीं उठाना पड़ता।

प्रदेश के सभी विभागों में घोर भ्रष्ट जालसाज विभागों में सबसे बड़ा कमाई के अड्डा राजस्व विभाग, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्ट पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक जिला अधिकारी उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, संभागायुक्त जो सत्ता के बड़े सिरमोर होते हैं। आए जाए भले ही कुछ नहीं पर डंडा घुमाने का अधिकार की आड़ में हर विभाग से हर कदम पर मोटी वसूली करते हैं। यही कारण है कि पूरे मध्यप्रदेश के बड़े-बड़े जिलों में जहां ज्यादा मोटी कमाई की व्यवस्था है सभी पदोन्नत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का भ्रष्टाचार का मोटा धान लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा का पद खरीद वाया गया। वही अब पूरे प्रदेश चला रहे हैं उसमें इंदौर का गॉड भ्रष्ट जालसाज कलेक्टर मनीष सिंह भी हैं। जिसकी जल साजियों के बारे में अगर सन 2000 से इतिहास निकाला जाए तो अधिकांश समय इंदौर में बिताने के साथ ही साथ उसने भारी जालसाजियों को न केवल भू माफियाओं, कॉलोनी माफियाओं के साथ वरन डीजल पेट्रोल, गैस, मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, साल्वेंट माफिया, गुटका माफिया, खाद्य, कन्फेक्शनरी, औषधि निर्माता माफिया, चिकित्सीय व नशा औषधि विक्रय माफिया, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल माफिया, पैथोलैब, स्वास्थ्य, खनन, निगम का ठेकेदार माफिया, सड़क चौड़ीकरण और स्मार्ट सिटी के नाम त्योहारों के समय सघन बस्ती तोड़फोड़ का सरकारी व निगम अधिकारियों का माफिया, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सफाई, विद्युत, देसी विदेशी शराब माफिया, एआइसीटीसीएल की लूट, परिवहन में, सिटी बसों, मैजिक, ऑटो, बसों ट्रकों के परमिट का माफिया आदि के साथ महिला बाल विकास, कृषि उद्यानिकी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायत, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, निगम, पुलिस, आबकारी, खनन, आदि से पाइप लाइन की वसूली तो की ही, यहां तक की फल सब्जी वालों से लूट कर वसूली के साथ फल सब्जी बिकवाने तक में वसूली के साथ तालाबंदी के नाम पर, गाड़ियों के परमिट आने-जाने के परमिट फैक्ट्री बाजार खुलवाने की छूट मैं भी भारी लूट कर अपने आका को पहुंचाने के कारण ही इस प्रमोटी को 28 मार्च 2020 को इंदौर में कलेक्टर बना दिया गया था। यह हल केवल इंदौर कहीं नहीं ग्वालियर जबलपुर भोपाल उज्जैन के साथ सभी जिलों का भी रहा। जहां पर अधिकतम प्रमोटी कलेक्टर को प्रभार में बिठाकर मोटी वसूली की गई। प्रमोटी कलेक्टर में भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी की तरह नियमों से काम करने के अतिरिक्त मंत्री मंत्री संत्री, सांसद, विधायक, नेताओं को ज्यादा सिर पर नहीं बैठाते, नहीं उसे इशारों पर नाच कर ज्यादा उल्टे सीधे काम करते हैं।

जबकि एकमुश्त करोड़ों लेकर, मासिक करोड़ों की वसूली में प्रमोटी कलेक्टर मोटी चमड़ी का शूकर 20-30 साल तक राज्य सरकार के भ्रष्टाचार में रम, रच, बसने के कारण सत्ता के सरपंचों, पार्षदों, विधायकों, नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के इशारे पर नाचता हुआ उनके साथ अपनी और अपने साथ उनकी मोटी कमाई की व्यवस्था लेन देन करने के साथ अपने आका के हर आदेश को सिर माथे पर रख नियम कानून की धज्जियां बिखेर वैध-अवैध सब कुछ करने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ा रहता और करता है। इसलिए घोर भ्रष्ट, जाल साज मुख्यमंत्री जानबूझकर सीधे आईएएस बनकर आए अधिकारियों को जिलों का प्रभार नहीं देता। ताकि उसकी किसी भी काम में कोई भी कानून, वैध- अवैध जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो। और लूटपाट जालसाजी भ्रष्टाचार से वसूली में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।

पुलिस विभाग में भी जानबूझकर 6-7 सालों से पदोन्नतियां ना देकर उनके आक्रोश को दबाने, मोटी कमाई के लिए सिपाही या कांस्टेबल को एक पट्टी, दो पट्टी,तीन पट्टी, मुख्य सिपाही या हेड कांस्टेबल बनाना, हेड कांस्टेबल को एआई का, एआइ को एसआइ का, एस आइ को टीआई, टीआइ को एएसपी, एएसपी को डीएसपी, डीएसपी को एसपी बनाने मैं प्रभार के बदले अरबों रुपए का प्रभार वसूला गया आखिर बेचारे 15 महीने की सरकार ना होने के कारण सारी भेडियो झुंड पार्टी के मंत्रियों को कमाई के साधन भी तो चाहिए आखिर सरकार खरीदने बनाने पद पर बैठने के लिए भी तो मोटा पैसा खर्च किया है। तो मोटी कमाई के साधन भी चाहिए। यह जो हाल गृह विभाग के पुलिस विभाग का है वही हाल लोक निर्माण विभाग का है। यहां पर भी शासकीय विभागों के भवन निर्माण के लिए बनाई गई परियोजना क्रियान्वयन इकाई शाखा में सभी जिलों संभागीय परियोजना यंत्री के सभी पद मोटा प्रभार लेकर प्रभारियों से भरे गए हैं। मोटा धन लेकर और मासिक वसूली पर भवन एवं पथ के 80 संभागों में से लगभग 60 संभागों में भी मोटी बसूली कर घोर भ्रष्ट और जालसाज जो मोटी कमाई कर मोटा पैसा दे सकें प्रभारियों को कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। यही हाल उपयंत्री यों को सहायक यंत्री का, इसी प्रकार का. य. को प्रभारी अधीक्षण यंत्री प्रभारी अधीक्षण यंत्री को प्रभारी मुख्य अभियंता बनाकर मोटी कमाई की जा रही है। स्वाभाविक है जो घोर भ्रष्ट जालसाज निकम्मे इंजीनियर है वह मोटी कमाई करते हैं मोटा धन लुटाते हैं और प्रभार पाकर पुनः भ्रष्टाचार करने के लिए जुटे रहते हैं ताकि अपने आकाओं को महीना पहुंचाया जा सके। यही हाल नर्मदा घाटी विकास विभाग में हो रहा है और वहां तो सारा खेल करोड़ों अरबों में होता है।

पर इस घोर भ्रष्ट जालसाज मुख्यमंत्री शिवराज ने हार के बावजूद, विपक्ष के विधायकों को डरा धमका और धन दे खरीद कर कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसके बाद वही पुराना रेत खनन भ्रष्टाचार वसूली का खेल उसने पुनः शुरु कर दिया और इसके साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल गैस और शराब बेचने के बाद भी उससे लगभग एक लाख करोड़ की कमाई करने के बाद में भी लगातार 18 महीने में 32 बार कर्ज प्रदेश के विकास के नाम पर लिया। पर लाखों कर्मचारी को समय पर पदोन्नति नहीं दी जा रही। पदोन्नति के इंतजार में सभी विभागों में हर महीने हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं। और पदोन्नति न मिलने के कारण उनको पेंशन भी पुरानी पद के वेतनमान की ही मिल रही है। यही हाल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जिसमें हजारों को हर विभाग में उचित समय मान और वेतनमान ना मिलने के कारण सेवानिवृत्ति पर उन्हें भी भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है। फिर न हीं केंद्र सरकार के बराबर उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 31ङ महंगाई भत्ता देना शुरू किया तब प्रदेश की सरकार ने 8ङ बढ़ाकर 20ङ कर दिया। वर्तमान में प्रदेश के हर विभाग में लगभग 2लाख तकनीकी, गैर तकनीकी, शिक्षक कांस्टेबल, बाबू चपरासी स्तर तक के कर्मचारियों की आवश्यकता होने के साथ-साथ दो लाख से ज्यादा पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर जो तकनीकी कर्मचारी हैं और हर विभाग में वर्षों से दैनिक वेतन भोगी की दरों पर वेतन प्राप्त करते करते बूढ़े हो गए पर धना भाव का रोना रोकर उन्हें भी नियमित नहीं किया जा रहा उल्टे ही उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्ति देकर उनके कलेक्टर मजदूरी की दरों जिसमें आप कुशल अर्ध कुशल कुशल स्तर के वेतनमान भी नहीं दिए जा रहे उल्टे ही ठेकेदार अपना कमीशन काटकर जो वह ठेका लेने के समय और अधिकारियों को मासिक मजदूरी का भुगतान करने के समय रिश्वत के रूप में देता है। काटकर लूटा जा रहा है। कर्मचारियों अधिकारियों को समझना चाहिए कि जिसको उन्होंने ईवीएम के छल कपट से सत्ता में पहुंचाया था अब वह है छल कपट का परिणाम सरकार छल कपट से ही दे रही है।

डब्ल्यू एच ओ बनाम विश्व स्वास्थ्य के नाम डराओ लूटो संगठन

(पेज 1 का शेष)

फिर विश्व की भर्ती औद्योगिक ताकत के रूप में चीन ने भी मोटा कमीशन बांट इस विश्व घातक संगठन से हाथ मिला लिया। और पूरी दुनिया में सस्ता स्तर हीन घातक माल सप्लाई करने के लिए कुख्यात लाखों करोड़ के मास्क थर्मो गन, ऑक्सीमीटर, आर्किड बैच डालें। संजय अमेरिका इस पाखंड को पुख्ता करने के लिए चीन से वायरस फैलाने के सुरेंद्र की बात करता रहा एक दूसरे से दिखावटी नूरा कुश्ती करते हुए दोनों देशों की कंपनियां हजारों करोड़ कोरोना के नाम कमाती रही। फिर बदलते समय के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें वॉलमार्ट अमेजॉन भारत की अंबानी अडानी टाटा बिरला आईटीसी युनिलीवर के साथ बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल भी अपनी कमाई में से 20 से 25ङ इस पाखंड को फैलाने और अपने मालवी को आने के षड्यंत्र में शामिल हो गए। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण गंदी बात हुई कि हमारे देश का भूखा भेड़िया जाहिल मोदी, इस करुणा की तैयारी को में सन 2016 से लगा हुआ था अरबों रुपए की कोरोना की किट की आपूर्ति पूरे देश में कर दी गई थी और तैयारी चल रही थी उसके पहले उसने जानबूझकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर उस हरामखोर अनपढ़ गवार ने देश में कैशलेस की नौटंकी की जब वह सफल नहीं हुई तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की ताकि देश के सारे नकदी लेन-दन पर चलने वाले छोटे व्यवसाय, उद्योगों को खत्म कर दिया जाए। सारे व्यवसाय को ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया जाए। ताकि उनके लाभ में से मोटा लाभ चुनकर आए भूखेरे श्वानों, यथा विधायक सांसद मंत्रियों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व परीक्षा से चुने भारतीय प्रताड़ना सेवा के मोटी चमड़ी के सूकरो को करोड़ों में महीना मिलता रहे। इसलिए वह सब आंख मीच कर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम बनकर आदेशों का पालन कर देश में करोना के नाम पर पिछले 19 महीने से 24 घंटे टीवी मोबाइल समाचार पत्रों में दहशत बांट और मुंह पर मास्क बांधने के लिए विवश कर जानबूझकर बीमार बना कर करोड़ों लोगों का नरसंहार करवाने के साथ, अब टीके का पाखंड कर रहे हैं और सौ करोड़ टीके लगा कर अपनी उपलब्धि को महानता का कृत्य बता रहे हैं। जबकि गिट्टी को को बनने में 15-20 साल लगते हैं। वाटिका नवंबर दिसंबर 2020 में ही बना लिया गया था। टीका लगने के बाद उसी स्वास्थ विभाग के जो यह पाखंड कर रहा है। 20,000 से ज्यादा डॉक्टर की मौत हो चुकी है। करोड़ों लोग जिसमें हजारों छोटे-मोटे नेता, अधिकारी, हजार से ज्यादा पत्रकार, टीका लगने के बाद मौत के शिकार हो चुके हैं। पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिले धन और 5उ मोबाइल सेवा जिसके माध्यम से 5उ मोबाइल उपयोग करने वाले और टीका लगाने वाले उपयोगकर्ता के दोनों एक दूसरे से शारीरिक मानसिक रूप से जुड़ जाएंगे। उनकी हर गतिविधि पर, मस्तिष्क की तरंगों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नजर रखकर अपना माल बेंचने का षड्यंत्र पूरा कर रही हैं। इसके लिए 125 अरब डॉलर विश्व बैंक ने दो किस्तों में मोदी को दिए थे। उसकी आड़ में भी जानबूझकर लाखों लोगों को पूरी दुनिया में मार कर स्वाइन फ्लू का टीका बेंचा गया। इसलिए ये भूखेरे श्वान मोदी अमित शाह के साथ में पूरा भेड़िया झुंड पार्टी का मंत्रिमंडल सारे नेता सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों से लेकर जिलों के कलेक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो मोटा पैसा हजम कर रहे हैं कमीशन में जनता को टीका लगाने के लिए विवश कर रहे हैं और उसके लिए जबरदस्ती नए-नए षड्यंत्र व पाखंड भी किए जा रहे हैं। देश और दुनिया में अमेरिका और चीन की कंपनियों ने पिछले 19 महीने से चलाया जा रहा करोना के पाखंड में और भी बहुत सारे बड़े-बड़े कांड किए। महामारी की आड़ में जबकि कोई भी व्यक्ति बीमार किसी भी देश में सड़कों पर बाजारों में दुकानों में कार्यालयों फैक्ट्रियों खेतों उद्योगों में नहीं मरा। सब को भयभीत कर मानसिक संत्रास से लिखकर बीमार बनाया और ले जाकर अस्पतालों में उनकी वहां के बोर्ड बाय ओनर सोनी जिसको जो मन में आया इंजेक्शन और दवाई लगाकर हत्या कर दी गई। उसके आधार पर जो तालाबंदी का नाटक किया गया उसका सारा फायदा अमेरिका की वॉलमार्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट को मिलने के साथ है चीन के उद्योगों को फायदा हुआ और भारत में भी वॉलमार्ट अमेजॉन के साथ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, आईटीसी युनिलीवर आदि के शॉपिंग मॉल से भी लाखों करोड़ का इन्हीं का माल बिका। इनकी संपत्तियां चौगुनी से 10 गुनी हो गई। बदले में देश के 30 करोड़ लोग बेरोजगार होने के साथ लगभग एक करोड़ छोटी दुकानें उद्योग फैक्ट्रियां स्थाई खर्चों के चक्कर में नष्ट हो गए।

शासकीय निगम और मंडल लूट और डकैती के अड्डे यथा मप्र सड़क डकैती विकास निगम

खराब सड़कों पर लूट और डकैती के साथ 25000करोड़ की डूबंत भी

समय माया ने 2002-03 मैं सड़क डकैती विकास निगम के बारे में जो लिखा था वैसा का वैसा ही शब्द का शब्द शाह सच जनता के सामने हैं जहां सड़कों पर पूरे मध्यप्रदेश में लगभग 30000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर जनता से जनता से ब्यूटी सड़कों के ठेकेदार लूडो लूट तो भरपूर मनमानी कर रहे हैं बदले में उबर खाबर सड़कें दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती इस तरह इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालते हुए लूटने के बाद में भी चलने के लिए मजबूर हैं प्रदेश के 8 जिले के संभागों के संभागों के सड़क डकैती विकास निगम के प्रबंधक अपना महीना खाकर सबकी अच्छी स्थिति बताते हुए चुपचाप बैठे हुए हैं लेबड से रतलाम लेबल से रतलाम की सड़क अत्यधिक गंभीर होने के कारण जोकि पिछले 10 साल से ज्यादा समय से खराब होने के उपरांत भी जहां पर हर दिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती है टोल टैक्स देने के बाद में भी वाहनों में टूट-फूट बंद होना साजन से बात होने के बाद में भी ना भाजपा सरकार कुछ पर कर पाई और ना ही कांग्रेश वही हाल इंदौर से उज्जैन की सड़क का भी है सन 2008 में जब इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था तब लगभग 55 किलोमीटर क्षेत्र में

12 साल के बाद में भी ना तो दोनों तरफ 30 30 फुट अधिग्रहित भूमि पर और बीच में 20 फुट की पट्टी पर पेड़ नहीं लगाए गए जिसकी घोषणा बड़ी शान से समय माया के लिखने पर उस समय के तत्कालीन प्रबंध संचालक सुलेमान खान ने की थी दूसरी तरफ दोनों तरफ 5 फुट के शोल्डर से पट्टिया नहीं भरी गई इसके विपरीत जैसा कि इस अनुबंध में था हर 3 वर्ष में सड़कों की मरम्मत के साथ 33इ पुनर नवीनीकरण किया जाएगा वह भी पिछले 12 सालों में नहीं किया गया जबकि इस तरीके से पूरी सड़क को अभी तक तीन बार पुनर नवीनीकरण कर दिया जाना चाहिए था साथ ही इस उबड़ खाबड़ ऊंची नीची सड़क पर दोनों तरफ उसमें बने गड्ढों पथ तल की समानता गुणवत्ता के अनुसार नहीं है अनेकों स्थानों को सड़कों में दरारें पड़ी हुई है परंतु उज्जैन में प्रारंभ से अभी तक बैठने वाले सभी घोर भ्रष्ट संभागीय यंत्र से लेकर प्रबंध संचालक जोकि भारती प्रताड़ना सेवा का अधिकारी होता है को महीना बांट कर सब के मुंह पर ताले लगा के रखे जाते हैं और इन सारी कमियों और दोषों को महीना वसूली के चलते कोई टिप्पणी या ठेकेदार को चेतावनी सड़कों की हालत ठीक करने के लिए नहीं दी जाती यह एक छोटा सा उदाहरण है जबकि लेबड रतलाम पिछले 15 सालों में कभी नहीं बनाई गई उसमें गहरे बड़े गड्ढे हो चुके हैं परंतु वह सड़क सुभाष चंद्रा ज़ी न्यूज़ के मालिक के ठेकेदारी में है वह 1 सूत्री कार्यक्रम वसूली का कर रहा है आज तक किसी की औकात नहीं हुई भाजपा यह कांग्रेसमें कि उसकी सड़क का अनुबंध खत्म कर दिया जाए दूसरी तरफ उसने उस सड़क का जो ऋण सरकारी बैंक से लिया था वह भी नहीं चुकाया गया। जबकि ऐसे बीओटी सड़कों के निर्माण में सरकार की गारंटी पर बैंकों ने संबंधित ठेकेदार को फर्जी 3-4 गुना ज्यादा लागत की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता दी थी। जिसमें तत्काल ही 25इ पैसा घोर भ्रष्ट और जालसाज संभागीय प्रबंधकों से लेकर प्रबंध संचालक प्रधान सचिव मुख्य सचिव और लोनी वि मंत्री वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री में ठेकेदार को अग्रिम स्वीकृत कर हजम कर लिया गया था 25इ में सड़क बनाई गई 25इ का जो हिस्सा ठेकेदार को निवेशित करना था वह उसने निवेशित नहीं किया। 25इ में काम चलाओ सड़क बनाकर इन्हीं सब हरामखोर उन्हें उसे पूर्णता प्रमाण पत्र देकर यह क्या कर वसूली शुरू करवा दी कि धीरे-धीरे उसकी गुणवत्ता सुधार ली जाए। परंतु 12 साल गुजर जाने के बाद में भी उस सड़क पर थिगड़ों से काम चलाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार के घोर भ्रष्ट मंत्री ने भी ऐसे सभी 50 से ज्यादा ठेकेदारों से मोटी वसूली कर मुंह बंद करना ही उचित समझा कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टे ही जोग और भ्रष्ट जालसाज उज्जैन के संभागीय प्रबंधक राकेश जैन जैन द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और ठेकेदारों को दिए जा रहे सरंक्षण के बदले में मोटी कमाई मिल जाने के कारण उसे इंदौर में स्थापित कर दिया जबकि इस घोर भ्रष्ट जाल साज राकेश जैन ने सिंहस्थ में सड़क निर्माण में सड़क के डिजाइन बदले बदलने के बदले में मोटी करोड़ों की रकम हजम की थी और अवैध बने हुए शांति पैलेस कि उस सड़क को उसके आगे से मोड़ा गया। जबकि वह नाना खेड़ा खेड़ा से आने वाली सड़क सीधे ही बाईपास से जोड़नी थी। इसी प्रकार राकेश जैन उज्जैन संभाग में आने वाले 7 जिलो के अंतर्गत 2012 -13 से 2019 तक सभी बीओटी सड़कों के निर्माण के साथ सीआरएफ वर्ल्ड बैंक मंडी रोड के निर्माण कार्यों में भी उसने मोटी कमाई की और इसके बाद में मोटा धन देकर इंदौर आ गया शिकायतें होने के बाद उसको भोपाल अटेच किया गया परंतु आसानी से मोटा धन खर्च कर वापस इंदौर लौट आया ।

मध्यप्रदेश में बनी लगभग ?30000 कर्? मी से ज्यादा की सड़कों में जिसमें बैंकों ने लगभग 25000 करोड से ज्यादा निवेशक किया है उनकी मूलधन की किस्त आने की तो दूर जिसके ब्याज की किस्त भी जमा नहीं हो रही है अर्थात वह सारा खर्च भी ब्याज मूलधन ना केवल सरकार को देना पड़ेगा वरना दूसरी तरफ वह जनता से दोनों हाथ से वसूली करने के बाद में भी 15 सालों में उसने एक भी बार सड़कों पर मरम्मत कार्य तक नहीं करवाया जैसा कि समय माया ने सन 2003 में इस बी ओ टी प्रोजेक्ट के और मध्य प्रदेश सड़क डकैती विकास निगम की स्थापना पर लिखा और कहा था। वर्तमान में वह सब अक्षरशः सही सिद्ध हो रहा है। यह सारी बातें और तथ्यों की जानकारी बेहतर तरीके से मुख्य सचिव प्रधान सचिव लोनिवि से लेकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय मुख्य सचिव भूतल परिवहन मंत्री वित्त मंत्रालय योजना आयोग सबके सामने स्पष्ट थी।

इसके बाद में भी पूरे देश में जानबूझकर इस प्रकार की बीओटी सड़कों का खेल खेला गया जिसके परिणाम ना केवल प्रदेश में वर्ण पूरे देश में सामने आ रहे हैं कि ठेकेदार ना तो सड़कों का ढंग से रखरखाव करता है और ना ही वाहन चालकों को टोल टैक्स वसूली देने के बाद में भी पर्याप्त सुरक्षा ही प्राप्त होती है। अधिकांश टोल नाकों पर जहां एंबुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है।

हाल ही में एक जनहित याचिका के अंतर्गत उस सड़क को इंदौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जब तक सुधार कार्य ना हो। तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब उसमें किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता है।

साढ़े 7 साल में जाहिल घोर लालची मोदी ने देश को हर तरह किया बर्बाद

(पेज 1 का शेष)

नोटबंदी में जहां 40,000 से ज्यादा छोटी कंपनियों का अस्तित्व साफ हो गया वही लगभग 5 करोड़ मजदूरों कर्मचारी स्थाई बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ उन सब का फायदा भेडियो से जुड़े सारे व्यवसायियों कंपनियों पूंजी पतियों व्यापारियों को कई गुना हुआ। जबकि झूठे मक्कार जाहिल मोदी ने देश की जनता और दुनिया को बताया किससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी यथार्थ में उनकी कमर तो नहीं टूटी? उल्टे ही नए जारी की गई नोटों की जाली करेंसी विदेशों से भी लाकर देश में खूब खपाई गई। जिससे उल्टे ही कश्मीर में पाकिस्तानी और देसी आतंकवादी ज्यादा मजबूत हो गए। दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की और मध्यम वर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय, मजदूर किसान जनता की कमर तोड़ी। उस नोटबंदी के घातक प्रहार से ज्यादा कमर टूटी हजारों लोगों ने उस परेशानी से व्यथित होकर आत्महत्या करने के साथ-साथ कई भूख और बेरोजगारी में तबाही से भी मरे और पर उन भेड़ियों को इसका तिल मात्र असर भी नहीं हुआ। इस परेशानी से बाजार उठ भी नहीं पाया था कि उसने 7 महीने बाद ही देश में जीएसटी लागू कर दिया जिसे आज तक जीएसटी काउंसिल से लेकर नीचे राज्यों के कर्मचारी अधिकारी नहीं समझ पाए और 1 जुलाई 2017 से लागू होने से पहले जैसा कि मैं लिख रहा था यथार्थ में है कानून अत्यधिक उलझन पूर्ण और आपराधिक तौर-तरीके का बनाया जाएगा जिसमें बड़े पूंजीपति बड़े आसानी से निकल जाए और छोटे व मध्यम पूंजीपति दुकानदार व्यवसाई उद्योगपति उस में उलझ जाए, और कानून की पेचीदगीयों मैं उलझ कर सही तरीके से कर भुगतान न कर सकें तो उन्हें आसानी से जेल पहुंचा कर उनकी सामाजिक आर्थिक उनकी कमर तोड़कर का व्यवसाय को बंद किया जा सके इस षड्यंत्र के अंतर्गत जीएसटी को देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंबानी अडानी के साथ-साथ टाटा बिरला आईटीसी युनिलीवर के लिए विशेष तौर से लगाया गया उसका प्रभाव पड़ा लाखों छोटे व्यवसाई उद्योग आदि उसके चक्कर में बंद हो गए जिससे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी। पर उस जाहिल को उससे कोई मतलब नहीं था बातें बस लंबी चौड़ी हक वाओ करवा लो बाकी काम तो है पूजी पतियों के सारे पर उनका मोटा व्यवसाय करने के लिए ही कर रहा है यह सब चल ही रहा था इसी बीच उसने धीरे धीरे सर की संपत्तियों को जिसमें सबसे पहले बैंक बैंकों के बाद बीमा कंपनियां जिसमें उसने 100% विदेशी निवेश की छूट दे दी जबकि यही दूरियों का झुंड पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो 49% से ज्यादा के विदेशी निवेश को रोकने के लिए हंगामा धन्य प्रदर्शन किया करते थे पर सत्ता में आते ही वह सब भूल गए और ना केवल बैंक बीमा यहां तक कि उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में भी 100% बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के अंदर कार्य करने की छूट देकर 100% विदेशी बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनियों का देश के जमे जमाए दूरसंचार की संरचना को तहस-नहस कर 130 करोड़ लोगों के साथ तो घात तो किया ही। साथ ही देश की न केवल जनता वर्ण सारे के सारे विभागों उस में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों से लेकर रक्षा कर्मियों के मोबाइलों की भी जासूसी करवाने का खुला आमंत्रण देकर देश को बर्बाद करने की आधारशिला रखी। जबकि पहले से ही इंटरनेट पर गूगल के सर्च इंजन और ईमेल के माध्यम से देश के सभी विभागों की गोपनीयता को विदेशी कंपनियों के हवाले करने का षड्यंत्र चल ही रहा है। इसकी दूसरी तरफ वही जानकारियां जब सूचना के अधिकार में देश के नागरिक मांगते हैं तो उसको गोपनीयता का हवाला दिया जाता है जबकि उनकी गोपनीयता पिछले 10 सालों से गूगल के हवाले करके व्यवसायिक उपयोग करने और जासूसी करने के काम आ रही है। यह सब कुछ देश के इन भाइयों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा उल्टा ही वह सूचना के अधिकार को भूसा बनाने और खत्म करने का षड्यंत्र करते रहते हैं जबकि वही सारी जानकारी गूगल के सारे ऐप के माध्यम से ईमेल, अनुवाद, कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से यहां से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में संग्रहित कर ली जाती हैं और बाद में सरकारी फैसलों के ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने निर्णय तैयार करती व थोपती रहती हैं। वित्तीय प्रबंधन में भयंकर जालसाजी, हेरा फेरी करने के साथ अपनी मौज मस्ती के लिए और विदेश यात्राओं, खास तौर पर अमेरिका में हावडी मोदी, मैजिक मोदी, रू 41लाख करोड़ रिजर्व बैंक से किस्तों में निकाल लिया गया, फिर भारतीय जीवन बीमा निगम से रुपए डेढ़ लाख करोड़, सारी तेल कंपनियों से न केवल लाभ के नाम पर धन वसूला, साथ ही उन कंपनियों को कमजोर करने के लिए एक तरफ तो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से उत्पादित पेट्रोल डीजल जिसमें 38-40 ऑक्टेन का पेट्रोल होता है इंसान व्यक्ति के नाम पर लिखवाया जाता रहा और उसमें हजारों करोड़ प्रतिदिन का मोटा लाभ कमाया जाता है। जिसका भुगतान जनता को पेट्रोल डीजल में कम माइलेज मिलने के कारण चुकाना पड़ता है। यह सब जालसाजी हरामखोरी मोदी का सरंक्षण में रिलायंस को लाभ पहुंचाने के लिए की जाती है।

राष्ट्रीय कृत बैंकों से न केवल न केवल उनका लाभ बटोरा गया। वरन लाखों करोड़ का गुजराती पूंजीपति मित्रों का हजारों करोड़ का कमीशन खाकर माफ करवाने के साथ विदेशों में भी भगा दिया गया। इसके बाद में भी जनता का पैसा हजम करने व लूटने के लिए बैंकों का संविलयन भी किया गया। जिसमें उदासीन खातों का ही लाखों करोड़ रु हजम कर लिया गया। चेन यहां तक नहीं पड़ा जनता को लूटने और बैंकों को भविष्य में लूटते रहने के लिए अब स्टेट बैंक हर बार पैसे मशीन से जमा करने पर भी रुपए 25 का चार्ज लगाकर हजारों करोड़ रुपए जनता से लूटे जा रहे हैं जबकि पैसे निकालने पर भी उस हरामखोर चांडाल ने सेवा शुल्क के साथ में रु. 175 चार ट्रांजेक्शन के बाद ठोक दिया जिसमें रु. 28 का जीएसटी वसूलने के बाद लगभग रु. 203 प्रति बार पैसा निकालने का भी वसूलना शुरू कर दिया गया आखिर बैंकों को बनाया किस लिए गया था जब पैसा जमा कर लो पैसा निकालने पर भी वसूली कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जनता को जमा धन से ही लाखों करोड़ की जालसाजी अब बैंक के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर वित्त मंत्री तक कर और करवा रही है तो बैंकों का और औचित्य कहां रह गया? यह भी महंगाई का कारण बढ़ने के साथ-साथ जनता से लूट का साधन बन चुका है। इसके साथ सरकारी संपत्तियों इसमें हर राज्य के विद्युत मंडलों को बांट कर अटल बिहारी के समय बनाई गई कंपनियां भी बेच बेच के पैसा कमाया जा रहा है और सारा माल जो लाखों करोड़ का है हजारों करोड़ में भी नहीं बेचा जा रहा वर्णन तो मोटा कमीशन हजम कर सैकड़ों करोड़ में ही अपने वह सूअर चांडाल मित्र अडानी को सौंपा जा रहा है। रेलवे का हाल पहले स्टेशन फिर माल गाड़ियां बाद में यात्री गाड़ियां इस कोरोना की आड़ में अडानी को कबाड़ के भाव सौंप दी गई हैं। तेल बीमा भेल सेल गेल बेल को भी कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है हवाई अड्डे अड़ाणी को बेचने के साथ, पूरी एयर इंडिया को भी हजारों करोड़ का कमीशन खाकर मात्र 18000 करोड़ में पुनः टाटा को सौंप दी गई। जबकि एयर इंडिया के बेड़े में 132 प्लेन थे। उनकी कीमत तो दूर एयर इंडिया की सभी विमानपत्तन ओं और सभी बड़े शहरों में जो कार्यालय कैंपस की जमीन थी उसकी कीमत ही 18000 को से ज्यादा थी। और सब कुछ कबाड़ के भाव में उस हरामखोर रेलवे का चोरी कर कबाड़ बेचने वाले कबाड़ी बाप की औलाद ने हीं देश का प्रधानमंत्री बन कर संस्थानों को कबाड़ बनाकर बेचने में अपनी महानता समझ रहा है। शास्त्रों में और कविताओं में कहा जाता है बाकी गुंडा बदमाश लोफर टाइप की जो औलाद होती है वह अपने बाप के जमे जमाए पुश्तैनी संपत्तियों को बैठ कर खाते हैं और जब प्रतिभाशाली मेहनतकश ईमानदार बेटे पुत्र और नेता होते हैं वह अपने पूर्वजों बुजुर्गों और बाप दाताओं की संपत्ति को बेच कर ही खाते हैं।

वही हाल मोदी उसके भेढ़िया झुंड पार्टी कर रही है कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं जिसमें मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक नितिन गडकरी भी बार-बार पर उनकी आवाज दबा दी जाती है और जो सचमुच बुद्धिजीवी देश भक्त वरिष्ठ भाजपाई, मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज स्वर्गीय अरुण जेटली स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर स्वर्गीय दवे थे, की चिकित्सीय हत्या कर दी गई अब जितने भी हैं वो आपराधिक मानसिकता के मोदी और अमित शाह की गुंडागर्दी के सामने मुंह नहीं खोल रहे हैं जिसका वह भरपूर दुरुपयोग कर देश की संपत्तियों को बेचने के साथ कोरोना की महामारी के पाखंड की आड़ में देश को तबाह कर चुका है।

जनता की मेहनत से कमाये पेट्रोल, डीजल,गैस में लूटे हुए करों से सरकारें चलती हैं

8 माह काम, 14माह का वेतन, फिर भी कामचोरी, भ्रष्टाचार, डकैती

देश के 50 करोड लोगों को अपने जीवन यापन के लिए 365 दिन काम करना पड़ता है

केंन्द्र व राज्य सरकारों में बैठे कर्मचारी जो 8 महीने काम करके 14 महीने का वेतन लेते हैं इसके बावजूद 8घंटे की जगह 4से6 घंटे काम, हर कदम लूटपाट भ्रष्टाचार डकैती डालना इन का जन्मसिद्ध अधिकार है।

कोरोना की आड़ में मध्यप्रदेश में भी 5 दिन का सप्ताह घोषित करने के साथ सरकार ने 10:00 बजे से 6:00 बजे तक कार्यालयीन समय निश्चित किया था इसके विपरीत सभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालयों में जो बल्लभ भवन सतपुड़ा विंध्याचल से लेकर नीचे तक, सभी जिलों के सभी शासकीय विभागों में अधिकारी कर्मचारी 11: 30 से 12 बजे तक आते हैं और साडे 4:30, 5 बजे तक सारे कार्यालय खाली हो जाते हैं। यह हाल सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालयों से लेकर 30,000 से ज्यादा पंचायतों में अधिकांश स्टाफ साडे 4-5 बजे तक गायब हो जाता है बंद करो यह पाखंड वापस 6 दिन का सप्ताह करो। साथ ही जो कार्यालयों में अंगूठा लगाने की मशीन लगाई गई थी सभी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर उसको खराब कर के कोने में पटक दिया है। ऐसे तो अंगूठा लगाने वाली मशीन का भी विकल्प तैयार कर लिया था लोगों ने अपने अपने अंगूठों की सीलें बनवा ली थी जो दूसरे कर्मचारी आकर कर्मचारी का अंगूठा मशीन में लगा दिया करते थे इस प्रकार कंप्यूटराइज हाजिरी का सिस्टम सदा के लिए दफन होकर वापस ढर्रा वही पहुंच गया। कई विभागों में महिला कर्मचारियों का हाल तो और भी ऊंचा है वे 12:30, 1बजे तक आते हैं 1 घंटे बाद लंच शुरू हो जाता है जो 3:00 बजे तक चलता है बाद में 4:30 बजे तक अधिकांश महिला अधिकारी व कर्मचारी किसी भी बहाने अपना झूला झंडा उठाकर चल देती हैं। पुरुष अधिकारी वर्ग उनसे कुछ नहीं बोल सकता। महिला कानूनों के चलते सभी अधिकारी उनसे डरते हैं अन्यथा उनके पास हरामखोरी काम चोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने का हथियार सदा तैयार रहता है। यह हाल जिलाधीश कार्यालयों से चलकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वाणिज्य कर, महिला बाल विकास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खनन, पंचायत कृषि, उद्यानिकी, नगर निगमों, पालिकाओं, न्याय विभाग, विद्युत मंडल की कंपनियों प्रदूषण मंडल नर्मदा घाटी, गृह निर्माण मंडल, शहरीय विकास, ग्राम एवं ग्रह निवेश, श्रम, गृह, जनसंपर्क, आदिम जाति अल्पसंख्यक 2 पिछड़ा वर्ग कल्याण, रेशम मत्स्य,खाद्य व औषधि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि प्रदेश सरकार के 130 विभागों का है। तो आखिर एक तरफ पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब, जीएसटी आदि में मनमानी लूट करो और वह पैसा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर बिना कार्य मुफ्त में लुटाओ आखिर

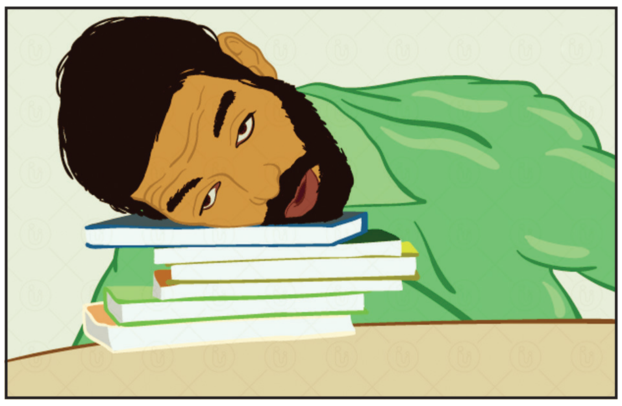

अपने बाप की जागीर नहीं। जब आमजन, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति 365 दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके कमाई करके पेट्रोल डीजल गैस बिजली पानी शराब में सरकार लूट रही है। इसके बाद में भी आयकर, जीएसटी से लूट कर सरकार अपने पर ही मुफ्त में क्यों खर्च कर रही है। सप्ताह में 48 घंटे काम होना चाहिए। जो कर्मचारी अधिकारी महिलाएं समय पर नहीं आते उन को कानूनी नोटिस देकर बाहर करने का कार्य क्यों नहीं किया जाता। पुनः6 दिन का सप्ताह किया जाना चाहिए। वैसे भी अब शीत ऋतु में लिंग छोटे होने से शासकीय विभागों में महिला कर्मचारी ना केवल 12:30, 1 बजे तक आती है। और दिन छोटा होने का बहाना लेकर 4:00 बजे निकल जाती है। केवल सप्ताह में दूसरे शनिवार की छुट्टी रखो। तीसरे शनिवार की छुट्टी भी खत्म करो। आखिर 8 महीने काम करके 14 महीने का वेतन क्यों जनता से लूटकर इन हरामखोर जालसाज सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर लुटाया जा रहा है। फिर कभी छठवां वेतनमान चाहिए कभी सातवा चाहिए और कभी आठवां वेतन मान चाहिए। उसके बाद में महंगाई भत्ता भी चाहिए साल में एक बार घूमने के लिए आने जाने का पद के अनुसार रेल किराया से लेकर विमान किराया तक घूमने को भी चाहिए। रहने के लिए निवास उसके भी खर्चे चाहिए यह सब उन 50 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई पर हरामखोर सूकरो की फौज सारी मौज मस्ती और ऐश करने के बावजूद सरकारी अधिकारी कर्मचारी 365 दिन में से मात्र 240 दिन अर्थात 8 महीने काम करता है। साल के 52 रविवार 52 शनिवार और 15 से 20 अन्य अवकाश अर्थात् कुल 124 दिन या 4 माह सरकारी छुट्टीयों में गुजार जाते हैं।

और वेतन लेता है। पूरा 14 महीने का। क्योंकि उसे 33 दिन का अर्जित अवकाश 13 दिन का आकस्मिक 15 दिन का सर्वेतनिक चिकित्सा अवकाश मिलता है जो 61 दिन होता है अर्थात 2 महीने।

इसके विपरीत यह पूरी जाल साजियां करेंगे। अपने मनमर्जी से जनता का खून पीने के लिए कानून बनाएंगे यह जनता का लूटा हुआ पैसा अपने बाप की जागीर समझ कर कहां कैसे खर्च करेंगे या किया। या कागजों पर ही सारा काला पीला कर हजम कर गये। उसका भी हिसाब नहीं देंगे। सूचना अधिकार कानून बड़ी मुश्किल से आजादी के 58 साल बाद लगाया गया। उसका नाम सुनकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक, नीचे पंचायतों तक हर किसी अधिकारी की गले में अटकती है। क्योंकि हर किसी की रग-रग में खून के हर कतरे कतरे में भ्रष्टाचार मक्कारी लूट डकैती भरी हुई है।

सूचना का अधिकार लगे हुए 16 साल हो चुके हैं धारा 4 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री कार्यालय सभी मंत्रालय जनता के धन को लूट कर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं चाही गई 17 बिन्दुओं की जानकारी अभी तक न हीं विभागीय इंटरनेट साइट पर लोड नहीं की जाती। शासकीय विभागों में बैठे 99% अधिकारी द्वितीय श्रेणी से लेकर और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे सभी कनिष्ठ व वरिष्ठ भारतीय प्रताणना सेवा अधिकारी तक घोर भ्रष्ट जालसाजों का गिरोह है।

सारे राजनीतिक दल जो स्वयं गुंडे बदमाशों अपराधियों का गिरोह है। 16 सालों में किसी भी राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत लगाते हैं। पर कभी किसी ने यह मांग की, कि निचले स्तर से लेकर दिल्ली के राजधानी स्तर तक की सभी विभागों में धारा 4 पूरी की जाए। वह अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा ईमानदार बनता है क्या दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों की साइट पर कितना धन कहां से आया? कहां खर्च किया? कौन सा अधिकारी किस पद पर कब से बैठा हुआ है? उसके जाति प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। जब वह नौकरी में आया था। तब की कितनी संपत्ति थी और वर्तमान में कितनी संपत्ति है। नियमित रूप से,हर साल के अंत में घोषणा की जाती है। कितने मामले पर कहां पर लंबित हैं। की जानकारियां लोड की गई क्या?

कौन सा कार्य जनहित के लिए कहां करवाया जा रहा है? उसकी लागत क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई उसका ठेकेदार समय सीमा क्या है? 15 साल गुजर जाने के बाद भी लोड नहीं की गई। क्योकि सभी

किसी भी समाज, किसी भी गैर सरकारी संगठन, किसी भी जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कभी कहा जो अपने आप को ईमानदारी का काला काला चोगा पहन कर जनता को न्याय देने का पाखंड करते हैं। की जनता से लूटा हुआ धन आप के बाप की जागीर नहीं है। तो सारी जानकारियां सार्वजनिक करो जब संविधान में 1950 में इसकी व्यवस्था की गई है। परंतु काम नौ माह का और वेतन 14 क माह का, फिर भी हर स्थान पर जहां तो

क्योंकि भ्रष्टाचार के हमाम में सभी गले तक डूबे हुए समय का लाभ लेते हुए पूरे मौज के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।

जनता जागो, अधिकारों को मांगो।

आखिर एलोपैथिक डॉक्टरों का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक यूनानी डॉक्टरों से क्यों इतना बैर

एलोपैथिक डॉक्टर यथार्थ में अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय दवा, चिकित्सीय उपकरण मशीनें वैक्सीन इंजेक्शन निर्माता गिरोह की कठपुतली है और इन सब का ड्रग चिकित्सीय उपकरण वैक्सीन इंजेक्शन मशीन ट्रायल का भारत सबसे बड़ा अड्डा और यह सारे एलोपैथिक डॉक्टर उन सब के चुप्पे जासूस एजेंट है भारत में जो देश की जनता को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हीन समझकर सारे हथकंडे अपनाकर जनता को पहले बीमार बनाते हैं फिर उन पर ड्रग, वैक्सीन इंजेक्शन मशीनें उपकरण आदि का ट्रायल कर करोड़ों रुपए कमा कर युवाओं को बाले बाले चटका देते हैं और मोटी कमाई दीवारों से भी की जाती है और उन कंपनियों से भी जिसके परिणाम सन 2008 में सारे देश दुनिया ने देखें। 95% मधुमेह उच्च निम्न रक्तचाप, हरजाई किडनी लीवर कैंसर जैसी घातक बीमारियों में आपका लापरवाह जालसाजी व लालच पूर्ण लूट की मानसिकता होती है। जानबूझकर 95इ मरीजों को आप पहले घातक दवाइयां देकर बीमार बनाते हैं। और फिर उनकी सभी चिकित्सा करते हैं और लूटते हैं। जनता को आप अमर फल खाकर नहीं आए मौत आपकी भी होगी तो जो आप की शरण में आते हैं। उनको गिद्धो की तरह क्यों नोंच कर लूटते खाते हैं।

एलोपैथिक डॉक्टरों को अपने इतिहास देखना चाहिए आखिर आयुर्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है जहां मनुष्य को निरोगी बनाने के लिए प्राकृतिक, योग, मंत्र तंत्र, से आत्मीय और मानसिक शक्तियों को विकसित कर आत्मविश्वास जगाकर निरोगी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाने से लेकर हृदय यकृत प्लीहा दंत मुख आदि की उपकरणीय जैविक जिसमें अर्बुद या कैंसर आदि के घावों के दूषित रक्त व मवाद आदि को साफ करने के लिए पानी एवं कीचड़ की जोंको का उपयोग किया जाता है यह भी शल्य चिकित्सा का ही हिस्सा है। महाभारत काल में जब 40 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा तो जो सैनिक दिनभर चोट, घाव व क्षत विक्षत हो जाते थे। परंतु उस समय संजीवनी बूटी से लेकर अन्य उच्च स्तरीय औषधियां ऐसी होती थी कि वह रात भर में सारे घाव भर जाते थे सारी चोटें और क्षत विक्षतपन सुबह तक दूर कर दिया जाता था। और वे घायल याद घायल सैनिक पुनः युद्ध मैदान में तरोताजा हो कर युद्ध लडते थे।

आपके बर्तमान आधुनिक एलोपैथिक शल्य चिकित्सा से लेकर बाकी सभी औषधियों और विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की जो महाभारत काल तक भरत ने आयुर्वेदिक पद्धति से की जाती थी इसके साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जिसकी अनेकों विधाएं हैं जिसमें स्वमूत्र गोमूत्र चिकित्सा सुगंध चिकित्सा, ज्योतिषी रत्न चिकित्सा, सूर्य किरण व रंग, जल मृदा चिकित्सा जैसी विधाओं को अंग्रेजों ने आकर भारत से नष्ट कर विदेशों में ले जाकर अपने तरीके से रसायनिक योगिकों को विकसित कर एलोपैथिक का नाम देकर हमारे साथ दुनिया पर थोप दिया। आज से 100 साल पहले एलोपैथिक चिकित्सा का अस्तित्व कहां पर और क्या था? क्या उसके पूर्व भारत में सारे लोग जो बीमार या घायल होने सब मर जाते थे क्या। तो एलोपैथिक डॉक्टर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सहस्त्रों वर्ष पूर्व से हमारे ऋषि-मुनियों से लेकर हमारे पूर्वजों ने हमारे घरों में कटे-फटे चोट से लेकर सर्दी खांसी बुखार आज की गहन बीमारियों के लिए भी पूरी आयुर्वेदशाला हमारी रसोई घर में सजा दी थी जिसका उपयोग आप आज भी मसालों के रूप में करते आ रहे हैं पहले आप अपने अस्तित्व को देखो फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी के डॉक्टरों को शल्य चिकित्सा से रोकने के लिए आंदोलन करना और अभी वर्तमान में जो महामारी का पाखंड चल रहा है अंत में एम्स से लेकर सारे छोटे-मोटे नर्सिंग होम सरकारी व निजी अस्पताल क्या वही आयुर्वेदिक काढ़ा पिला कर सबको ठीक करके भगा रहे हैं क्यों आपको तो वायरस भी नहीं मिला बीमारी भी नहीं मिली और चिकित्सा भी नहीं है आपके पास और आपके इस पाखंड में सचमुच अगर महामारी थी तो लोग अस्पतालों में ही क्यों मर रहे हैं घरों पर सड़कों पर बाजारों में फैक्ट्रियों में कार्यालयों में दुकानों पर लोग क्यों नहीं मरे और मरने वाले 90इ केवल निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गीय हिंदू ही क्यों है दूसरी तरफ ना तो कोई सफाई कर्मी मर रहा है ना कोई मर रहा है ना कोई मजदूर रहा है तो यह महामारी के पाखंड की आड़ में क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पेट भरने का षड्यंत्र नहीं है आप सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है जो अपनी जाल साथियों चाल बाजुओं को छुपाने के लिए एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हो आप पहले गिरेबान में झांक लो आप कितने ईमानदार सेवादार मानव सेवाओं के प्रति कितने समर्पित है।

उसके बाद आंदोलन करना।

कोरोना वायरस के कारणों पर शोध से चीन ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे परोक्ष रूप में भारतीय वैदिक संस्कृति का अनुमोदन करते हैं। जो कि इस प्रकार है :-

हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदों के आधार पर शवों को अग्नि में जलाकर दाह संस्कार करने का विधान बनाया था।

चीन ने घोषणा की है कि अगर शवों को जमीन में गाड़ देंगे, तो उनके शरीर में जो कोरोना वायरस या अन्य वायरस व बैक्टीरिया होते हैं वो जमीन में मिल जाएंगे और ये वायरस और बैक्टीरिया कभी नष्ट नहीं होंगे, बल्कि जमीन में ही फैलेंगे और जल तथा वायु को प्रदुषित करेंगे। शवों को जला देने से आग के जरिये वायरस और बैक्टीरिया सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाते हैं।

इसीलिए चीन ने घोषणा की है कि जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर मर रहे हैं, उन सभी का अंतिम संस्कार जलाकर ही किया जायेगा।

वेद और वैदिक सहित्य में शाकाहार को ही मनुष्य का भोजन कहा गया है। मांसाहार रोगों को बढ़ाने वाला और महापाप की श्रेणी में आता है।जिसका सेवन स्पष्ट रूप में वर्जित है।

मांसाहार कितना खतरनाक होता है , इस बात की जानकारी चीन को ही नहीं सारे विश्व को कोरोना के कारण पता चली है।

(शेष पेज 7 पर)

म प्र वाणिज्य कर विभाग में

चारों तरफ जालसाजो, भ्रष्टों का का अड्डा, कंप्यूटर खरीदी में भारी भ्रष्टाचार

सूचना के अधिकार में जानकारी देने के अपेक्षा 5-5 पेज के बकवास तर्कों के जवाब

मध्यप्रदेश शासन की आयका महत्वपूर्ण स्त्रोत मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग जिसमें जीएसटी लग जाने के बाद शरीर रोनक जा चुकी है फिर भी चारों तरफ भ्रष्टों और जालसाजों को दो-दो पद देकर सुशोभित किया जा रहा है बेशक स्टाफ की भारी कमी और पदोन्नतियों के अभाव से यह स्थिति 2014 की पदोन्नतियों के बाद से 5-6 साल से लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ 1990 के बाद भर्तियां ना होने के कारण क्लेरीकल स्टाफ के साथ-साथ अधिकारी निरीक्षक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी लगातार कम होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार में घोर जाहिल, भ्रष्ट, जालसाज, आपराधिक मानसिकता के पूंजी पतियों के गुलाम रखेले मोदी ने जीएसटी लगाने के बाद जो दावे किए गए थे उन सारे दावों की हवा निकलने के साथ-साथ पिछले 1 जुलाई 2017 से टूबर 2021 तक लगभग 11सौ से ज्यादा संशोधन कर दिए गए हैं। पूंजी पतियों के वेतन प्राप्त चार्टर्ड या करप्ट अकाउंटेंट्स की टीम ने पूंजी पतियों के फायदे के लिए जैसा की दुनिया में अधिकांश देशों की सरकारों ने पूंजी पतियों के वेतन प्राप्त करने वाले या किराए पर जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम से अत्यधिक आपवादिक और उलझन पूर्ण प्रकृति का जिस माल एवं सेवा कर का केंद्र व राज्य सरकार पर थोपा गया है यथार्थ में उसको बनाने वाले ही नहीं समझ पाए तो लागू करने और भुगतान करने वाले कैसे समझ सकते हैं। फिर जीएसटी काउंसिल जो पूरे जालसाज भ्रष्ट पूजी पतियों के कर्मचारियों की वेतन प्राप्त गिरोह का अड्डा है। परंतु शिवराज ने यह बात सही है की सबसे अंत में जीएसटी के बिल पर हस्ताक्षर किए। जबकि संविधान की 42 वी अनुसूची में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी राज्य अपनी वित्तीय व्यवस्था के संचालन के लिए करारोपण की व्यवस्थाएं स्वंय सभालेंगे। इसके विपरीत मोदी ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर नाच कर बिना संविधान संशोधन किए माल एवं सेवा कर के अधिनियम की व्यवस्थाओं को थोप दिया। जीएसटी काउंसिल मैं बैठे सभी सदस्यों को कोचु की पूंजीपतियों से मोटा पैसा मिल रहा है इसलिए वह बार-बार संशोधन कर छोटे, मध्यम वर्गीय व्यापारियों, उद्योगों, उत्पादकों को उलझाने और कानून को अत्यधिक जटिल और क्लीष्ट बनाने के लिए लगातार संशोधन कर रही है पर स्वयं ही जीएसटी काउंसिल के सामने उनके सदस्यों जो कि कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है का उद्देश्य केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का है। बार-बार और लगातार संशोधन होने से ही सारे कर व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है फिर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस वाणिज्य कर विभाग में उसका आयुक्त जो किसी भी विषय का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं होता और फिर वर्तमान में कार्यरत मध्य प्रदेश वाणिज्य कर आयुक्त राघवेंद्र सिंह जिसके बारे में आपने पड़ा कि उसने भरे तालाबंदी काल में उस घर ब्रेस्ट जालसाज किशोर वाधवानी से 18 बार बात की थी उसका रु 7हजार करोड़ का गुटका बिकवाने के लिए, जिस पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की परंतु मध्य प्रदेश सरकार का करआयुक्त चुपचाप बैठा रहा। स्वाभाविक था कुल गोष्टी करारोपण का आधा हिस्सा मध्यप्रदेश का भी था तो कर चोरी में जो हानि हुई बेशक उससे कलेक्टर मनीष सिंह ने 180 बार लंबी बात करके हजारों करोड़ की चोरी करवाने में प्रत्यक्ष सहयोग दिया उन दोनों पर जो कि केंद्र में भाजपा की सरकार के साथ राज्य में भी भाजपा की सरकार है। चुपचाप मोटी वसूली कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जबकि कलेक्टर मनीष सिंह के साथ कर आयुक्त राघवेंद्र सिंह को भी यहां से हटाया जाना चाहिए था और यही कारण है कि मैंने लिखा था की तत्काल प्रदेश सरकार को अपने नाकों को चालू कर देना चाहिए ताकि भले ही वहां पर कोई लेन-देन हो ना हो परंतु 36 जांच चौकियां पूरा शुरू की जानी चाहिए ताकि कर चोरी की देख रेख अवश्य हो। दूसरी तरफ जब थोपा गया। जीएसटी स्वयं सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को 3 साल बाद समझ में नहीं आया तो राज्य सरकारी कर्मचारियों को कर सलाहकारों को वकीलों और किराए के चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट्स को कैसे समझ में आएगा। पर व्यवस्थाएं चल रही है और प्रशंसा भी की जा रही है कितने लाख करोड़ हमें ज्यादा टैक्स में वसूल कर लिया।

दूसरी तरफ बेशक काम बढ़ता जा रहा है और पूरे वाणिज्य कर विभाग में कोई भी अपर आयुक्त नहीं है 1-1 पूर्व के ऐतिहासिक भ्रष्ट, जालसाज उपायुक्तों के जिन पर पूर्व में ही किसी पर लोकायुक्त का किसी पर विभागीय जांच लंबित है, भारी भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। पास ही दो दो संभागों के प्रभार हैं। साथी अधिकांश कर्मचारियों निरीक्षकों अधिकारियों को एक ही स्थान पर बैठे-बैठे 10 10 वर्ष तक गुजर चुके हैं। फिर जहां तक महिला कर्मचारियों का सवाल है तो मंत्री से लेकर आयुक्त तक सभी रस लोलुप हैं। रसास्वादन के चलते कैसे किसी अतिरिक्त प्राप्ति के उनके स्थानांतरण करें स्वभाविक सी बातें भले ही जीएसटी में भ्रष्टाचार के साधन खत्म हो गए। पुराने वर्षों के का निर्धारण में भी कमाई अभी भी चल रही है कर समाधान योजना के अंतर्गत एसीटीओ, सीटीओ, ऐसी समाधान योजना के अंतर्गत पुराने प्रकरणों में मोटी कमाई कर सारे केसों को उल्टा सीधा समायोजित व निर्धारित कर अरबों रुपए की शासन की वसूली को डुबाने पर तुले हुए हैं। यह हाल इंदौर के 15 व्रतों से लेकर प्रदेश के 80 व्रतों में सभी जगह यही चल रहा है। पुरानी पकड़ो में खात्मे के नाम पर सलाहकारों के माध्यम से मोटी वसूली के बदले में खुद ही सलाह कर दे कर 70-80% प्रकरणों में खात्में लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अब मोटी कमाई के निर्धारण के साधन खत्म होने पर अब कोई स्थानांतरण लेने या रोकने या भेजे जाने के लिए भी ज्यादा उत्साह हिलाल बनकर मोटा पैसा खर्च करने को तैयार ना होने के कारण भी ना केवल निरीक्षक एसीटीओं, वरण सीटीओ एसी डीसी भी आय ना होने कारण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं इसलिए मंत्री आयुक्त प्रधान सचिव तक किसी को कमाई के साधन ना होने के कारण पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वाणिज्य कर में स्थानांतरण उद्योग केवल एंटी इवेजन ब्यूरो तक सीमित रह गया। यहां पर जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है और या पूर्व में जो एंटी इवेजन में रह चुके हैं। वही पुनः ऐसा खर्च कर एनडीए विजन में भी कुंडली मारे बैठे हुए हैं प्रदेश में 8 एंटी इवेजन स्वीकृत होने के उपरांत भी वर्तमान में मात्र 6 चल रहे हैं। भोपाल में बैठा घूर भ्रष्ट जो इंदौर में 9 नंबर व्रत में भारी भ्रष्टाचार करके लूटता लुटाता रहा प्रदीप दुबे पैसा खर्च करके पहले जबलपुर एंटीवर्जन में जमा रहा और वर्तमान में भोपाल में बैठकर भी भारी भ्रष्टाचार कर रहा है इसीलिए दूसरी बार ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को भोपाल में बैठा रखा है वही हाल एच एस ठाकुर का भी है जो जबलपुर में एंटीवर्जन देख रहा है। जब से जीएसटी लगा स्वभाविक सी बातें वेट और उसके अंतर्गत सारे उसके नियम कानून उसके साथ ही समाप्त हो गए पर यहां बैठे सारे हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर अपने भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बताने के लिए 2009 की छूट और गजट नोटिफिकेशन का हवाला देकर सारे बच जाते हैं। जबकि 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी के संबंध में ऐसी कोई भी छूट एंटीवर्जन यह कर अपवंचन शाखा को नहीं होने के बाद में भी सर विद्यालयों की फौज पिछले 11 सालों से उस का हवाला देकर बच रही है बेशक सारे एंटीवर्जन ब्यूरो मोटी कमाई का हिस्सा मंत्री प्रधान सचिव आयुक्त के साथ लोकायुक्त को भी पहुंचाते हैं तो आखिर क्यों और फिर क्या दूसरे अच्छे अधिकारी नहीं जो बार-बार प्रदीप दुबे जैसे अधिकारी को एंटीवर्जन में पदस्थ किया जा रहा है। यही कारण है यहां बैठे गोर जल साइज भ्रष्टों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी देने के लिए बहाना लेकर बस्सी रहती है मुख्यालय में अपील करने पर अपर आयुक्त भी क्योंकि विभाग का आज अधिकारी नहीं होता जहां से मोटे धन की आवक हो मुझे खिलाफ कैसे कुछ कहा जा सकता है। फिर इतनी भी सफाई नहीं हुई कि किसी को कुछ ना मिले। इसके विपरीत पुराने कंप्यूटर जो कि जो पुरानी खरीदी सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे काम कर रहे थे।? मोटी कमाई के लिए पूरे प्रदेश में अरबों रुपए के कंप्यूटर खरीदे गए क्योंकि वर्तमान कंप्यूटर में जिस कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर खरीदे गए उनमें कोई भी सॉफ्टवेयर चाहे वह विंडो टेन हो व अन्य हो सब की खरीदी में भी अरबों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए और यही कारण है कि राघवेंद्र सिंह को दूसरी बार पदस्थ करके मोटी कमाई की जा रही है।

फिर सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां जो कामचोर कर्मचारी बैठा हुआ है और उन पर मुख्यालय का उपायुक्त जो पूर्व का ऐतिहासिक भ्रष्ट होता है जानकारी देने के नाम पर की जालसाजों फौज हमेशा दलील दे कर अपील करने पर भ्रष्ट शुगर अधिकांश को निरस्त कर देते हैं अगर हराम खोरो थोड़ी सी ईमानदारी बची है तो आयुक्त से लेकर नीचे तक 16 साल गुजर जाने के बाद में भी धारा 4 का अभी तक पालन क्यों नहीं किया अपने बाप की जागीर समझते हो लूटो खाओ और कोई जानकारी मांगे तो उसको व्यर्थ दलीले दो।

वाणिज्य कर देवास व्रत में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी संजय विजयवर्गीय पुराने लंबित वसूली के इस औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों का व्यापारियों के 10 साल से ज्यादा पुराने लंबित वसूली के अरबों रुपए के प्रकरणों को धारा 34 के अंतर्गत पुराने वेट के फॉर्म लेकर जिनमें बड़ी मोटी वसूली है। सारे दिन व्यापारियों उद्योगपतियों कर सलाहकारों को फोन पर धमका चमका कर पिछले 2 साल से स्वयं रु30-30 ?40000 लेकर रु लाखों वसूली कर उनको 34 में करवाने का दबाव बनाकर वार्ड बी के साथ-साथ पूरे वाणिज्य कर व्रत देवास के सभी वार्डों का ठेकेदार बन सभी व्यापारियों से मोटी वसूली पिछले 2 साल से कर रहा है। व्यापारियों के अनुसार वह पैसा जो है वाणिज्य कर अधिकारी जाटवा के साथ सहायक आयुक्त रीता चतुर्वेदी, व उपायुक्त को भी देने की बात करके पूरा पैसा हजम कर रहा है। बेशक सीटीओ जाटवा सीधी भर्ती का होने के कारण ज्यादा ज्ञानी नहीं। इसका फायदा संजय विजय वर्गीय पिछले 2 साल से उठाकर चारों तरफ व्यापारियों व कर सलाहकारों से सीधी मोटी वसूली करके सारी फाइलें ही गायब करवा देता है।इस प्रकार पिछले 2 साल में इस औद्योगिक क्षेत्र देवास के व्यापारियों व उद्योगपतियों से उसने लगभग 1करोड़ रुपए से ज्यादा हजम कर शासन को 50 करोड़ से ज्यादा की क्षति पहुंचाई है। इस भ्रष्ट अधिकारी को भविष्य में ट्रेप करवा कर पकड़वा दिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी।इसलिए यहां का फर्स्ट स्टेप सूचना के अधिकार में कोई जानकारी देना पसंद नहीं करता और जानकारी मांगने पर उल्टे सीधे बहाने बनाकर आवेदन को नस्ती बंद करवा देता है। इनका अपीलीय अधिकारी उपायुक्त जो है इन सबसे मोटा धन खाकर जानबूझकर वह हरामखोर सारे आवेदन रद्द कर देते हैं जबकि इसके पीछे का षड्यंत्र उपरोक्त अनुसार है इसे समझा जा सकता है।

आखिर एलोपैथिक डॉक्टरों का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक यूनानी डॉक्टरों से क्यों इतना बैर

(पेज 6 का शेष)

जिन प्राणियों को माँसाहारी खाते हैं वे कई प्रकार की घातक बीमारीयों से पीड़ित हो सकते हैं तथा उनके सेवन से मनुष्य उन बीमारीयों की चपेट आ सकता है यह बात कारोना वायरस ने सिद्ध कर दिया है। अब पूरे विश्व को शाकाहार को ही अपनाना होगा। हमारे ऋषियों ने यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा है क्योंकि शुद्ध जल और वायु मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। अग्नि में डाला गया घी एवं अन्य सामग्री वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को भी समाप्त करता है। चीन अब भारत में अपनाई जाने वाली यज्ञ पद्धति से वायरस मिटाने पर विचार कर रहा है। क्योंकि मांसाहार त्याग कर वायरस से कुछ सीमा तक तो बच सकते हैं लेकिन जो वायरस वायुमंडल में फैल चुके हैं उनको समाप्त करने का उपाय यज्ञ ही है। वैदिक संसकृति में आपसी मेल जोल में शारीरिक स्पर्श जैसे हाथ मिलाना या गले मिलना या चूमना आदि का कोई स्थान नहीं है। एक दुसरे से मिलने पर हाथ जोड़ कर नमस्ते करने का आदेश है। यह नियम हमारे ऋषियों की वैज्ञानिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से उच्च कोटि सोच को दर्शाता है। अन्य अभिवादन के ढंग छूत रोग कारक है इसलिए हाथ जोड़कर नमस्ते करना ही स्वास्थ्य के लिए उचित है। आज चीन में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए शारीरिक स्पर्श से बचने के निर्देश दिये गये हैं। यह सब निर्देश वैदिक संस्कृति का ही समर्थन करते हैं।जिनको हमने करोड़ों वर्षों से अपनाया हुआ है। आज चीन शव दाह संस्कार, शाकाहार, यज्ञ विज्ञान और भारतीय संस्कृति को अपना रहा है! वह दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व भारतीय वैदिक संस्कृति को अपनाने को मजबूर होगा।

भारत में ऋषि- मुनियों ने जो नियम धर्म और परम्पराओं के आधार पर बनाये है वही सर्वश्रेष्ठ हैं और इनको अपनाने से ही हर रोग से बचा जा सकता है।

जागो अति ज्ञानी हिंदुओं...बहुराष्ट्रीय कं. व ईसाई संगठनों के इशारे पर हिंदुओं का किया नरसंहार

(पेज 12 का शेष)

वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हिंदुओं के बच्चों, युवा पीढ़ी को, वेदों के तंत्र मंत्र से देवों को जागृत कर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए एक अकेला परशुराम विश्व को उस काल में क्षत्रिय विहीन बना सकता है। युद्ध हथियारों से नहीं मजबूत मन और शरीर से लड़े जाते हैं। ब्राह्मणों तुम्हारा कर्तव्य है कि हिंदुओं को ऊंच-नीच से दूर उनकी युवा पीढ़ी को तंत्र मंत्र से मानव शरीर से मजबूत बनाकर इतनी क्षमता ही पैदा कर दो की एक जाति इनकी औकात ही ना हो कि वह कुछ कर सकें और वह सब भूतों प्रेतों के दम पर चलते हैं और आप देवताओं के दम पर, देवताओं का अस्तित्व अनादि है। भूतों प्रेतों का अस्तित्व तात्कालिक और क्षणिक होता है। इसको समझो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुट्ठी भर हिंदू युवाओं को इस तरह से प्रशिक्षित कर मजबूत कर दिया गया तो वह देश और दुनिया पर फिर अपनी ध्वजा लहरा सकते हैं। दुनिया में मुस्लिम नहीं अभी भारत, चीन, जापान, वर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया आदि में बौद्ध लोग ज्यादा है। और मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक हैं। जो इनके अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। उनको साथ लेकर पुनः रोंद दो और साफ कर दो धरती से मुस्लिमों को। भारत की आर एस एस और भैड़िया झुंड पार्टी के डरपोंक हिंदू नार्मदों की बात छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बस हमारी हिंदुओं की वर्तमान और भावी पीढ़ी को एकजुट कर कट्टर मजबूत और भयंकर आक्रमण कारी बना दो। इतना काफी है। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। वह मुस्लिमों को साफ कर देंगे। हिंदुओं को डराईये मत। इजराइलियों की तरह मजबूत बना दीजिए। हिंदुओं का इतिहास इतना कमजोर नहीं रहा वरना 900 साल में, हिंदुत्व का नामो निशान मिट जाता। इसको समझिये।

साप्ताहिक समय माया

मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

संविदा पर बीएसएनल के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, जिन्हें सड़क का कुछ नहीं मालूम,

जालसाज भारतीय प्रताणना सेवा के अधिकारी जो ना करें वह सब कम

सन 2000 में जब भारत के 7 लाख गांवों में शहरी क्षेत्रों से सड़कों के मार्ग उपलब्ध नहीं थे तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने पेट्रोल डीजल पर 2% सेस थोपकर उसका पैसा भी जनता से ही इक्ट्ठा किया जा रहा है। जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है। उस समय देश के कुछ राज्यों ने इस योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग से करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री घोर भ्रष्ट और जालसाज दिग्गी दानव ने इसके लिए प्रदेश के विविध कार्य विभाग को जिसमें ग्रामीण यांत्रिकी य, लोक निर्माण विभाग,, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, गृह निर्माण मंडल आदि के इंजीनियरों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया। ताकि उस योजना में भी धन हजम करने की व्यवस्था भ्रष्ट इंजीनियरों से भ्रष्टाचार करवाकर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के माध्यम से की जा सके। उद्देश्य था की गांव में सड़क निर्माण के बाद एक विभाग को समाप्त करना पड़ेगा। उस की बनाई हुई सड़कें लोक निर्माण विभाग को सौंप कर सड़कों का रखरखाव किया जा सकेगा। स्वाभाविक था एक तकनीकी विभाग में सारे अधिकारी के तकनीकी ही क्षेत्र के हो। परंतु यहां पर भी लूटने के लिए प्रमुख अभियंता की जगह सीईओ घोर महा मक्कार महा जालसाज जिसे सड़क निर्माण की तकनीकी का क ख ग नहीं आता। ही पदस्थ किया गया और ग्रामीण विकास के सचिव और प्रधान सचिव जो आईएस होते हैं उन्हीं को बनाया गया जिन हरामखोरो का काम केवल लूटना होता है। के हाथों में सौंप दिया गया। वर्तमान में सभी तकनीकी कार्य विभागों यथा लोक निर्माण ग्रामीण यांत्रिकीय में 30 साल से भर्ती ना होने के कारण सभी विभागों में उपयंत्री से प्रमुख अभियंता तक के इंजीनियरों स्टाफ की भारी कमी है। इसलिए प्रतिनियुक्ति पर इस प्राधिकरण में अब इंजीनियरों को भेजना बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो सड़क निर्माण और रखरखाव का तकनीकी ज्ञान और अनुभव लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के पास होता है। वह अन्य विभाग के पास नहीं बेशक सभी सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियरों को इस में पदस्थ किया जाता है। वर्तमान में इंदौर राजस्व संभाग में कुमार मनोज बीएसएनएल के एक पूर्व मुख्य अभियंता जिसके पास केवल केबल लाइनों, टावरों, भवनों, संचार मशीनों आदि की स्थापना व निर्माण का अनुभव है, लेकिन सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कोई अनुभव नहीं है, जबकि सड़कों की सिविल इंजीनियरिंग के ज्ञान की कमी के कारण दो बार उसे खारिज कर दिया गया था। सितंबर 2019 और अक्टूबर 20 में साक्षात्कार में, लेकिन प्रधान सचिव के साथ संबंधों के कारण शुक्ला ने आरआरडीए के सीईओ शशांक मिश्रा पर आईएएस को सीजीएम के रूप में नियुक्त करने का दबाव डाला, जिसका मतलब केवल भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करना था, इसलिए कुमार मनोज अपने वर्तमान के उचित काम करने में असमर्थ है। मप्र ग्रामीण मंत्रालय न केवल उसके वेतन पर सार्वजनिक निधि को खराब कर रहा है, बल्कि ग्रामीण सड़क विकास पर सार्वजनिक निधि को भी नष्ट कर रहा है, क्योंकि वह अपने सभी 11 महाप्रबंधकों और उनकी परियोजनाओं का मार्गदर्शन, नियंत्रण और निगरानी करने में असमर्थ है, जबकि वह एक नियंत्रक, निगरानी कर्ता पीएमजीएसवाई विभाग के क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की 11 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों वाले सभी 8 जिलों के आधीन प्राधिकरण, वह अपने पिछले अनुभव और ज्ञान के कारण काम की मात्रा और गुणवत्ता के नियंत्रण करने में पूर्णतः असक्षम होने के साथ मेरे सूत्रों के अनुसार, यहां तक कि वह किसी भी डीपीआर की जांच करने में असमर्थ है, पीएस मंत्री न केवल सार्वजनिक निधि बल्कि सभी 11 इकाइयों के काम करने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों को बचाने के लिए ग्रामीण विकास को उसकी सेवायें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए।देवास इकाई क्रमांक एक में बैठा महाप्रबंधक येवले जिसने जल संसाधन विभाग के देवास संभाग में, जिसका भाई सहायक यंत्री था और पूरा 180 करोड़ का बांध, उसके लिए भूमि अधिग्रहण, 45 किमी लंबी नहरों का निर्माण में भी उसने लगभग रू. 10करोड से ज्यादा का भ्रष्टाचार करके हजम किया। जानबूझकर उसमें मेटल स्टेटा होने के बाद में भी वहां पर सुट फाल का निर्माण कागजों में करवाया। नहरों की चट्टानी कटाई में, नहर क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र में ऊपर और जमीन के नीचे कांक्रीटिंग के पूर्व ना तो ढंग से भराई, पिचिंग खुदाई की गई और इस तरह इन कांक्रीटिंग में भी लगभग 5-8 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मोटा पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद मंत्री प्रधान सचिव और प्रमुख अभियंता को देखकर वहां से है बैतूल चला गया वहां पर अनेकों योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। और सेवानिवृत्त होने के बाद में उसने मोटा पैसा खर्च कर पुनः क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में महाप्रबंधक बन गया जिसने जिंदगी भर केवल तालाब, बांध, नहरें आदि का काम किया हो। विशेष सड़क का क ख ग नहीं आता हो। इसके बाद में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो घोर भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी होता है। मोटा पैसा लेकर संविदा पर नियुक्त कर दिया। यही कारण है कि यह भ्रष्ट सूचना के अधिकार में आवेदन के अनुसार जानकारी देने में अपनी ऐतिहासिक आदत को दोहराता है।

किराए के वाहनों के नाम पर कर्मचारी ही लगा रहे चुना

पूरे मध्यप्रदेश में जब से सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के आने जाने के लिए किराए के वाहन में कार्यालय ना शुरू किया है तब से चारों तरफ कर्मचारियों अधिकारियों ने अपने ही वाहनों से मोटी कमाई करना शुरू कर दिया है यह कहानी किसी एक विभाग के नहीं बल्कि सारे विभागों की है। वाक्य और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी अपने ही वाहन अवैध रूप से वहां लगाकर महीने के 25 से 40 ?50000 महीने तक का किराया स्वयं ही हजम कर लेते हैं उसके साथ ही पेट्रोल डीजल में बिल बना कर वह पैसा भी विभाग प्रमुख से लेकर कर्मचारी में बंदरबांट हो जाती है। नियमा अनुसार अधिकारी के पद के अनुसार वाहन की पात्रता होने के साथ-साथ वाहन 1 साल से लेकर 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन पर जो चालक होगा वह वाहन लगाने वाले का होना चाहिए इसके साथ ही वाहन जो है वह टैक्सी कोटे से पास हुआ टैक्सी परमिट का होना चाहिए। चालक के पास व्यवसायिक वाहन

चालन अनुज्ञप्ति होना भी आवश्यक है। वर्तमान में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण इन मासिक किराए की दरों में परिवर्तन हुआ है कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतने का डीजल पेट्रोल और गाड़ी का इंजन ऑयल ब्रेक ऑयल कहीं-कहीं पर वाहन क्रश लेने वाला विभाग भुगतान करता है तो कहीं पर एक निश्चित किलोमीटर तक वह पेट्रोल-डीजल मालिक को देना पड़ता है। अधिकांश विभागों में वहां के कर्मचारी अधिकारी प्रभारी अधिकारी को कमीशन देकर, अपने वाहन और सरकारी ड्राइवर चलाई जा कर अवैध रूप से शासन को चुना लगाया जा रहा है। यह कहानी मध्य प्रदेश लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग के अधिकतर सहायक यंत्री संभागीय यंत्री अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता कार्यालयों से लेकर सचिवों प्रधान सचिव मंत्री तक के विभाग की है।

इंदौर में ही अधीक्षण यंत्री संभाग 1 के साथ, सेतु, परियोजना क्रियान्वयन इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग विद्युत यांत्रिकी उज्जैन भोपाल ग्वालियर जबलपुर और प्रमुख अभियंता कार्यालयों का भी है। यही कहानी जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाएं, मप्र गृह निर्माण मंडल, महिला बाल विकास कृषि उद्यान की वन विभाग मध्यप्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, प्रदूषण मंडल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सभी कंपनियों व्यथा पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकांश संभागों, की भी है और इस प्रकार से प्रदेश भर में प्रतिमाह करोड़ों रुपए का चूना विभाग के कर्मचारी अधिकारी सरकार को लगा रहे हैं

मध्य प्रदेश वाणिज्य कर का मुख्यालय इंदौर में होने के साथ यहां पर भी बैठे अधिकांश कर्मचारी अधिकारी एक पंजीकृत दलाल ठेकेदार के माध्यम से अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। और बदले में मोटी वसूली करते हैं। जब से जीएसटी लगा है इन दोनों भाइयों की कमाई बंद हो जाने के कारण नये नये तरीकों से के अधिकारी कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं। कर्मचारियों की झड़ी लगाने में पेट्रोल डीजल खर्च में से भागीदारी कर लेते हैं। जबकि वाणिज्य कर विभाग में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को गाड़ी देने की आवश्यकता नहीं आखरी हरामखोर लाखों का वेतन ले कर वहां पर कर क्या रहे हैं अब फील्ड में जाने का काम खत्म हो गया दूसरी तरफ माल एवं सेवा कर में सारा कार्य कंप्यूटराइज होने के साथ व्यापारिक दिल बनाते हैं जब टैक्स एसजीएसटी व सीजीएसटी का बिल बनने के साथ सरकार को सीधा ही चला जाता है।तो वृत प्रभारी या वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त को वाहन देने की क्या जरूरत है क्यों इन पर करोड़ों रुपए हर महीने बर्बाद किया जा रहा है। वाहन की आवश्यकता केवल एंटीइवेजन ब्यूरो में होती है। तत्काल पूरे प्रदेश में संयुक्त आयुक्त स्तर तक के सारे किराए के वाहनों पर करो रुपए खर्च करने की अपेक्षा अधिकारियों को 3-4 हजार रुपए महीने का वाहन भत्ता या खर्च देकर सरकार को इससे भी पिंड छुड़ा कर खर्च बचा लेना चाहिए।

यह किराए के वाहनों की कहानी इंदौर नगर निगम के साथ, उज्जैन भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा के साथ सभी नगर पालिकाओं, परिषदों में भी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपने वाहन लगाकर करोड़ों रुपए प्रतिमाह का चंदन लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में तो किराए के वाहनों के साथ में सरकारी वाहनों की भी भरमार है और उनके नाम से चाहे वह वाहन खड़े कर कबाड़ हो जाते हैं। फिर भी वहां पर उनका पेट्रोल डीजल और मरम्मत का खर्चे लगा लगा के सीएमएचओ, वहां का भ्रष्ट स्टाफ अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में पूरे प्रदेश में डीजल पेट्रोल और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रु हजम कर रहा है। वन विभाग में वैसे तो अधिकांश वाहन और वाहन चालक सरकारी ही हैं परंतु किराए के वाहनों का खेल वहां पर भी छोटा-मोटा चलता रहता है क्योंकि भारतीय वन लूटो खाओ सेवा के अधिकारियों को नए किराए के वाहनों में ना केवल कमाई का साधन मिलता है वरन अच्छे नए वाहन भी वनों में घूमने फिरने और जंगल में मंगल करने के अवसर प्रदान करता है।

जिलाधीश कार्यालयों में तो घर भ्रष्ट जालसाज जिलाधीश ना केवल सरकारी वाहन वर्ण किराए के वाहन रखने के साथ-साथ दूसरे विभागों के चलने वाले अच्छे वाहनों को भी अपने यहां कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर संलग्न करके करके संबंधित विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को उनके वाहन सुविधा से वंचित कर परेशान करता है। वर्णन जिलाधीश की शहंशाही और तानाशाही के सामने दूसरे विभाग के लोग बोलते नहीं परंतु परेशान और को गालियां तो समझते ही हैं दूसरी तरफ यही हाल तहसीलदार सहायक जिलाधीश उप जिलाधीश स्तर के अधिकारी भी भारी बदतमीजी पूर्ण तरीके से वाहनों का उपयोग भी करते हैं और संबंध का किराए का भुगतान करने के लिए उन विभागों से भुगतान भी करवाते हैं और तानाशाही के चलते संबंधित अधिकारी को ताकि वह कुछ बोले ना हल्का ते डराते धमकाते रहते हैं और यह वाहन सामान्यता विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रदूषण मंडल गृह निर्माण मंडल लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन विभाग के ही होते हैं वैसे भी राजस्व की अधिकतर भारतीय प्रताड़ना सेवा व राज्य प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों की कौम, आता जाता कुछ नहीं, पद के आधार पर डराना धमकाना कर लूटना और सब का भाग्य विधाता होता है। मजबूरन दूसरे विभागों के अधिकारी जून से ज्यादा शिक्षित और समझदार होते हैं इनकी बदतमीजियों और कुंठाओं के सामने सर झुकाए रहते हैं और जो यह चाहते, वाहन मांगते हैं। चुपचाप देकर अपने यहां उनको अपनी जेब से शासन के पैसे से समायोजित करते रहते हैं।

वैसे यह हाल केवल सरकारी विभागों का नहीं वरन मंत्रालय में बैठे घूर बदतमीज सचिवालय के भारतीय प्रताड़ना सेवाओं के अधिकारी जो मुख्य सचिव की पद तक अपनी जलसा जी पूर्व लूट के लिए प्रताणना व बदतमीजियों से सुशोभित कर रहे हैं क्योंकि स्वयं भ्रष्ट हैं इसलिए सारे प्रदेश के भ्रष्टाचार को पालकर मोटी वसूली कर जनता से पेट्रोल डीजल गैस में दोगुनी लूट मचा आमजन का खून पीकर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं।

म प्र जल भ्रष्टाचार से लूटों का संसाधन

मुख्य मंत्री, मंत्री, से प्र.स.,प्रमुख,मुख्य अभियंता, अधीक्षण, कार्यपालन, सहायक., उपयंत्री तक घोर भ्रष्ट जालसाज

वर्तमान में मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री, पूर्व का कांग्रेस का घोर लालची गद्दार खुद भ्रष्ट और जालसाज

सांवेर का विधायक और वर्तमान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जिसने कांग्रेसमें भी रहते हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार लूट शुद्ध के नाम पर विशुद्ध लूट का युद्ध किया। जल संसाधन विभाग में जिसके लिए शिवराज पर भारी दबाव डाला गया और इसी के लालच के चलते उसने अपने ही मातृदल कांग्रेस की सरकार को गिरा कर भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया। वैसे एक तरफ तो सरकार पेट्रोल डीजल गैस शराब में दुनिया में सबसे ज्यादा कर लूटने के बाद में भी कंगाल होने का नाटक कर रही है। जबकि उसके पास एसजीएसटी से 18 महीने में लगभग 90हजार करोड रुपए की आय होने के साथ उसको केंद्र से भी सीजीएसटी व आयकर का विभिन्न योजनाओं में हिस्सा मिल चुका है। दूसरी तरफ प्रदेश के जल संसाधन विभाग में 80ऋ योजनाएं अब जल उद् वहन की बनाई जा रही है जिसको उसने 1980 में त्याग दिया था क्योंकि अधिकांश जल उद् वहन परियोजनाओं में उसकी आधारभूत आवश्यकता बिजली की होती है। सिंचाई के लिए अत्यधिक महंगी पड़ती है बंद कर दी थी पर भ्रष्टाचार और मोटी कमाई के चलते पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ की योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें 65 70ऋ एकमुश्त पाइप लाइनों, इलेक्ट्रिक मोटर पंपों, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के सामान की खरीदी मैं वैसे अच्छी गुणवत्ता और स्तर की एमएसस्टील स्टील की 6', 1', 50 सेमी, 1मी, 2मी, 2.5मी 3मी, आदि की अच्छी कंपनी की पाइप खरीदी में, यही हाल मोटर पंप पुरानी सामग्री खरीदी में मात्र 3 से 5ऋ तक का ही कमीशन होता है। परंतु अब चारों तरफ चीनी माल और कंपनियों का बोलबाला है। वे अपना माल बेचने के लिए खरीदार की हसरत को पूरा करते हुए मोटा कमीशन और मोटा भी बना कर दे देती हैं जो ना केवल पाइपलाइन मोटर पंप ओं इलेक्ट्रिक सामग्री तार खंभों सब स्टेशन ट्रांसफार्मर तक में सीधा कमीशन मिलता है। और माल की डिलीवरी व गोदाम में दिखाने पर उसका शासन भुगतान कर देता है। इससे सीधी बंदरबांट उपयंत्री सहायक कार्यपालन अधीक्षण यंत्री से लेकर मुख्य प्रमुख प्रमुख सचिव और मंत्री तक पहुंच जाती है बाकी 30ऋ तक का कार्य, बड़ी टंकी, या तालाब बनाने, खुदाई लाइन बिछाने खेतों तक पहुंचाने में मेजर, मीडियम, माइनर स्तर की पाइप लाइनों, वितरणी उपवितरणी आदि के माध्यम से जल संग्रहित कर खेतों तक त्वरणवेग से वितरित किया जाता है। जिसका पैसा किसानों से वसूल किया जाता है। दूसरी तरफ सीधा पर घोर भ्रष्ट जालसाज वर्तमान में बैठा प्रमुख अभियंता एमएस डावर जिसका अधिकांश समय सहा., काय.' अधी. यंत्री, रहते हुए धार में गुजरा उसके वहां पर किए गए कार्यों से उसके भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कि वह किस प्रकार से भ्रष्टाचार ठेकेदारों को सर पर नाच कर भ्रष्टाचार को अंजाम देता रहा। फिर जब वह इंदौर में मुख्य अभियंता रहा तब भी सारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार होने के साथ-साथ बांधों, तालाबों के साथ उनकी नहरों की खुदाई, काक्रीटिंग में भी डीपीआरके अनुसार कम व स्तरहीन काम हुआ। जानबूझकर ओगी फाल बनाकर करोड़ों रुपए हड़पा गया। किसके काल में चंबल बेतवा कछार भोपाल में 17-18 में 26, 18-19 में 21और 19-20 में 15 योजनाएं, केन कछार सागर में 17-18 में 18-19में 16, 19-20में3, गंगा कछार रीवा में 17-18 में1,18-19में0, 19-20में 5, नर्मदा ताप्ती कछार में 17-18में 23, 18-19 में 27, 19-20में 21, बाणगंगा कछार सिवनी में 17-18 में 11, 18-19 में 9, 19-20में 9, उज्जैन में 17-18में 32, 18-19 में 21, 19-20 में 13 योजनाऐं, होशंगाबाद में 19-20 तक 23 यमुना कछार ग्वालियर में 17-18 में 13, 18-19 में3 और 19-20 में 12 योजनाएं पूरी की गई। वैसे भी देश के राज्यों के जल संसाधन विभाग, अपने भारी भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात है। हर राज्य का विधायक जल संसाधन मंत्री बनने के लिए हमेशा लालायित रहता है। भारी लड़ाई झगड़े दबाव सब कुछ होता है क्योंकि यहां पर अरबों रुपए की योजनाएं कागजों पर बनाई जा कर न्यूनतम 20ऋ से लेकर 100ऋ तक फर्जी बिल बनाकर हजम कर ली जाती है। वैसे रखरखाव सुधार कार्य पुनर नवीनीकरण आदि कार्य का पैसा भी मध्य प्रदेश के हर संभाग में कागजों पर ही हजम कर लिया जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार के धन के घमंड में उपयंत्री से लेकर प्रमुख अभियंता मंत्री प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री तक सब रहते हैं।

पुराने बांधों, नहरों, तालाबों में, पुर्ननवीनीकरण पुनः जागृति अर्थात टूटने फूटने, समाप्त होने के बाद में पुनः जीवित करने और सुधार कार्य के नाम पर, नए निर्माण में, काडा में, रखरखाव टूट-फूट इंदौर के 8 संभागों उज्जैन मुख्य अभियंता कार्यालय के 7 संभागों में काम कम है फिर भी हर परियोजना के डिजाइन ड्राइंग और सर्वे से लेकर निर्माण में पिचिंग अर्थ वर्क आरसीसी और पीसीसी और सभी प्रकार की कांक्रीट लाइनिंग में उपयंत्री से लेकर सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण और मुख्य अभियंता तक मोटी कमाई करते हैं इसलिए यह हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जय मुख्य अभियंता कार्यालय इंदौर हो वहां बैठा उनका लोक सूचना अधिकारी कभी भी पिछले 5 सालों से आवेदन को अंतरित नहीं करता। ऐसे हरामखोर उनके पास काम नहीं है और जब काम होता है तो काम न करने के लिए वाहनों की कमी नहीं है। वैसे भी यहां बैठा मुख्य अभियंता गांधी, वह उज्जैन का केके सिंह अर्ध ज्ञानी और भ्रष्ट होने के साथ ठेकेदारों की कठपुतली बनकर मोटी वसूली करने में व्यस्त रहता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है। इंटरेस्ट मकानों को सूचना के अधिकार में जवाब देने में जान पर आती है इसलिए अधिकांश आवेदन किसी ना किसी बहाने उल्टा सीधा जवाब देकर टाल दिए जाते हैं। और अधिकांश में आधार उस भ्रष्ट सूचना आयोग का होता है उसने यह आदेश दिया था उसने भाई आदेश दिया था उन हरामखोरों को बतलाया जाता है। कि कानून नहीं बदला है आयोग का निर्णय कोई कानून नहीं बन गया जिसके आधार पर आप सूचना देने से और आवेदन को अंतरित करने से मना कर देते हैं। फिर उज्जैन में बैठा अधीक्षण यंत्री एसएम चतुर्वेदी भी अपने सभी संभागों से भ्रष्टाचार में से मोटा हिस्सा खाते हैं। तो वह हरामखोर भी चाय पी ले मस्ती बंद कर देता है वही हाल अधीक्षण यंत्री की अपील जब मुख्य अभियंता को दी तो वह भी घोर बदतमीज भ्रष्टाचार से अर्जित धन से अति ज्ञानी ने अपील निरस्त कर दी। यदि हरामखोर जालसाजों, आवेदक ने जानकारी मांगी है अगर नहीं है तो आवेदन अंतरित करने बहाने क्यों बना रहे हो। जब भ्रष्टाचार करते हो तो सब नियम कानून से ही काम करते हो जैसे डीपीआर बनाई, जैसे कानून व मैनुअल है। उसके हिसाब से काम कर रहे हो।?

फिर धारा 4 के अंतर्गत अभी तक किसी भी कछार के मुख्य अभियंता ने किराए पर ली गई टैक्सियों की सारी जानकारी लॉग बुक और डेली डायरी अभी तक अपलोड क्यों नहीं किया अपनी और अपने अधिकारियों इंजीनियरों की जबकि 16 साल गुजर गए सूचना का अधिकार लगे। पर जहां सारा खेल ही पदस्थापना, पदस्थी, प्रभार लेकर प्रभाव से चल रहा हो। वहां समझा जा सकता है की सूचना के अधिकार में जानकारी देने पर क्यों यह हरामखोर नाटक नौटंकी कानूनों का सहारा निर्णय किए गए प्रकरणों का सहारा लेकर टालते हैं।

टाटा देश का घोर धूर्त सबसे पुराना जालसाज औद्योगिक घराना

टाटा देश का घोर धूर्त सबसे पुराना जालसाज औद्योगिक घराना, जिसकी सारी कंपनियां देश की सरकारों को खरीद कर, मनमाने तरीके से कानून बनवा कर जैसा आयोडीन साल्ट एक्ट 1972, मैं टाटा ने हीं 2 करोड रुपए खर्च कर कानून बनवा कर, देश के सारे नमक पर कब्जा कर सैकड़ों करोड़ के घाटे में चलने वाली टाटा केमिकल्स को मात्र 3 साल में सैकड़ों करोड़ के लाभ में पहुंचा दिया था। आज देश में सबसे ज्यादा बीमारियां यह आयोडीन नमक, जिसमें लीवर किडनी हट जाए ब्रेन हेमरेज कैंसर जैसी घातक बीमारियां है। बांट रहा है। और उससे उत्पन्न बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पहला टाटा कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल भी इन्हीं जालसाज चांडाल रतन टाटा ने हीं खोला। उसमें कैंसर के नाम पर पिछले 50 सालों से एक अनुसंधान के नाम पर लोगों पर ड्रग ट्रायल कर कैंसर की दवाई तैयार की जाती हैं और सफल होने पर पूरे देश और दुनिया में बैचकर अरबों रुपए कमाए जाते हैं। यह मोटी कमाई कर रहे हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि वह जनता को कोई फायदा देंगे अपने 150 वी जयंती पर, बिल्कुल असंभव जनता को लूट का एक नया तरीका होगा। इस को समझे। बार-बार इस संदेश को लोगों को ना बांटे। उनकी जालसाजियों को समझें। यह अपना व्यवसाय करने के लिए आतंकियों मुस्लिम गुंडों को पैसा बांटने से लेकर प्रदेश के ऊपर देश के बड़े-बड़े प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को और नेताओं को खरीद कर हर साल हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं। देश में उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है? कि वह जनता के लाभ के लिए कोई काम करेंगे. तत्काल में भेडिया झुंड पार्टी के सामने टुकड़े डालकर आखिर में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कंपनी को पूरा हजम कर ही लिया ना।इससे समझा जा सकता है।अंबानी अडानी से पहले का बड़ा जालसाज टाटा जिसने अपनी मोटी कमाई के लिए पूरे देश में 1970 में अपनी टाटा केमिकल्स को जो सैकड़ों करोड़ के घाटे में थी पूरे नमक पर कब्जा करने और उसको आयोडाइड करने का आयोडीन नमक 1972 का कानून बनवा लिया था। 3 साल के बाद हवाई कंपनी सैकड़ों करोड़ के लाभ में आ गई थी और वह साधारण पांच पैसे किलो का नमक उस समय भी एक रुपए किलो बिकने लगा था।

यही आयोडीन नमक था। जिसके षड्यंत्र के विरुद्ध भाजपा और उसके पहले जनसंघ, जनता पार्टी 1972 से 98 में आने तक आंदोलन करती रही। और जब सत्ता में आने के बाद उसको टाटा से पैसा मिलना शुरू हो गया। तो उसका आंदोलन खत्म हो गया। दूसरी तरफ आयोडीन नमक ने हीं कैंसर, हृदय आघात, लिवर किडनी, से लेकर ब्रेन हेमरेज, नपुंसकता तक बहुत सारे रोग भारत के लोगों में पैदा किए। वर्तमान में भी यह ज्ञान बांटने वाला जो है। पूरे देश में सभी सरकारी ठेकों में मोटा कमीशन बांटकर उल्टे सीधे काम करके जनता के पैसे को 2 गुना 50 गुना तक लूट रहा है। किसी भी भ्रष्ट जालसाज आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कभी ना सराहो। भले ही वह किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही क्यों ना हो। ठीक है कि वह छल कपट से किसी पद पर पहुंच गया तो महान वाह जनता का आदर्श नायक नहीं हो गया। टाटा के लाखों पाप भ्रष्टाचार है। इनके ऊपर हजारों पन्ने की किताब लिखी जा सकती है।इसको समझिए। इस बात से समझ लीजिए की टाटा आयरन व स्टील की फैक्ट्री को चलते हुए सवा 100 साल से ज्यादा हो गया आज तक उसके पास कोई भी बड़ी लौह अयस्क की खदान नहीं है। वह आज भी वैध अवैध लोह अयस्क को टनों में खरीद कर लोहा निकाल कर बेच रहा है। सफाई के नाम पर हजारों करोड़ों की मिनी ट्रक कचरा गाड़ियां पूरे देश में कमीशन पर आपूर्ति दी गई। टाटा ने मप्र में ही सॉफ्टवेयर बनाने में, नगर निगम पालिकाओं की सीवरेज लाइन डालने में पिछले 15 सालों से सैकड़ों करोड़ के घोटाले कर रहा है। टाटा पावर से एक पैसे की बिजली नहीं खरीदी जाती फिर भी प्रदेश सरकार मोटा धन दे रही है। आखिर क्यों और कैसे?

आने वाली पीढ़ी के लिए बचना नहीं चाहिए नदी तालाब पहाड़ और जंगल

खनन से खनका रहे माफिया के साथ मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारी

पूरे प्रदेश में चारों तरफ अवैध खनन को माफियाओं के साथ प्रश्रयदे रहे जिलाधीश एवं सहायक के साथ जिला खनन अधिकारी अकेले इंदौर में ही चारों तरफ इंदौर के बाहर की पहाड़ियों को खोदकर बड़े नेता जिसमें शुक्ला बंधु सबसे आगे हैं रेवती रेंज की पहाड़ियों को खोदकर अधिकांश को साफ कर दिया गया यही हाल जवाहर टेकरी से लेकर धार रोड पर नेमावर रोड पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे की पहाड़ियों पर बस उसे खुदाई करके कई स्थानों पर पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई कई स्थानों पर नेमावर रोड पर सौ 100 फुट ऊंची पहाड़ियों को काटकर आधा कर दिया गया इंदौर के खनिज अधिकारी जो बरसों से यहां जमे हुए हैं बार-बार जांच की बातें कही गई पर पिछले चार-पांच सालों में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आने वाले सभी जिलाधीश हो और उप जिलाधीश का भी उन माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन में भारी मोटी कमाई का हिस्सा रहता है इसलिए पूर्ण सरंक्षण मिला रहता है वहां पर बैठे उसे लेकर बाबू बा कर्मचारी भी क्यों के इशारे पर न केवल नाचते हैं वरन सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वे हर बार टरका देते हैं और अपील लगाने पर वहां बैठे उनके सरंक्षणता हरामखोर जिलाधीश भी उन अपीलों को आसानी से खारीज कर देते हैं बार-बार कहा जाता है सारी जानकारियांसाइट पर अपलोड है परंतु सच तो यह है कि निरीक्षक से लेकर जिला खनन अधिकारी से जिलाधीश तक सभी बड़े खनन माफियाओं जिसमें दोनों ही पार्टियों के नेता शामिल रहते हैं पूरी तरह सही पूर्ण सरंक्षण के साथ जल जंगल जमीन नदी तालाब पहाड़ उजाड़ अपनी मोटी कमाई में लगे हुए हैं यह हाल पूरे मध्यप्रदेश का है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानउनके भाई भतीजे वाह रिश्तेदार के 700ज्यादा डंफरों से लगातार 15 वर्ष तक होशंगाबाद के आसपास नर्मदा से अवैध बालू खनन करने और की राजधानी भोपाल में बैचकर भारी मोटी कमाई कर रहे। जिसे होशंगाबाद कलेक्टर से लेकर भोपाल कलेक्टर रायसेन कलेक्टर विदिशा कलेक्टर तक का पूर्ण सरंक्षण उस अवैध कार्य में मिला हुआ था। क्योंकि वह सब मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों के थे दूसरी तरफरीवा का बड़ा भूमाफिया और खनन माफिया राजेंद्र शुक्ला को का खनिज मंत्री का प्रभार दे रखा था जब डकैत को ही कोठार दे दिया जाए। सुहाग दिखाएं कि वह और उसका ग्रुप पूरे प्रदेश में ना केवल गोड खनिजो वरन मूल्यवान खनिजों में माइका, जिप्सम से लेकर बहुमूल्य खनिजों और रत्नों जो छतरपुर, पन्ना आदि में पाए जाते हैं। की भी भारी अवैध खनन से मोटी कमाई नेता मंत्री अधिकारी आंख मीच कर करने में लगे हुए थे।

रु 2.5 नाली व रु 5 हजार करोड़ सड़कों के नाम किये किये बर्बाद

निगम में वर्षों से जमे भ्रष्ट जालसाज डकैत अधिकारी इंजीनियरों का अड्डा

लूट चलती रहे 20 माह से चुनाव नहीं करवाए, ताकि पार्षद महापौर का हिस्सा ना बंटे

जहां बेलदार भी करोड़पति तो बाबू, अधिकारी, इंजीनियर डॉक्टर, आयुक्तों का अंदाज़ लगाया जा सकता है

इंदौर नगर निगम में जालसाजी लूट भ्रष्टाचार कदम कदम पर है।

जिस का इतिहास आधी शताब्दी से ज्यादा हो चुका है। करोड़ों रुपए खर्च कर यहां पर अधिकारी इंजीनियर डॉक्टर के साथ साथ सहायक उप और आयुक्त आने के लिए बेकरार रहते हैं और जो भी एक बार आ गया फिर वह अजगर की तरह है कुंडली मारकर चारों तरफ कब्जा करके अरबों रुपए की कमाई कर कर लुटा कर जमा रहता है। जबकि तहसीलदार एडीएम एसडीएम जो यहां पर सहायक आयुक्त उपायुक्त और आयुक्त के रूप में पदस्थ रहते हैं इनके पास कोई भी तकनीकी किसी भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता फिर भी सारे टेंडर निकालना आप अकेले ना भुगतान करना में खेल करते रहते हैं संदीप सोनी जो निगम में उपायुक्त है एआईसीटी सीरियल जो डकैती भ्रष्टाचार जालसाजी का बहुत बड़ा अड्डा है वर्षों से उसका भी प्रबंधन संभाल रहा है और उसके साथ ही साथ जिलाधीश कार्यालय में भी भ्रष्टाचार में लगा हुआ है बरसों से यही कुंडली मारे बैठा हुआ वही हाल लता अग्रवाल, ,,,,,,,,,,, व अन्य अधिकारियों इंजीनियरों डॉक्टरों का भी है। इनसे भ्रष्टाचार और लूट की सीधी कमाई शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री तक पहुंची रहे इसलिए जानबूझकर 20 महीने से नगर निगम इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर के साथ प्रदेश के अनेकों निगम व पालिकाओं में चुनाव नहीं करवाई जा रहे हैं बेशक भेड़िया झुंड पार्टी के लूट डकैती भ्रष्टाचार के साथ-साथ जो इन्होंने नोटबंदी तालाबंदी और महंगाई से जनता को अत्यधिक पीड़ित कर रखा है, डर है कि हर जगह वीडियो ढूंढ पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और उनके हाथ से निगमों की सत्ता निकल जाएगी, कांग्रेस व अन्य पार्षद और महापौर कब्जा कर लेंगे जिससे भारी बदनामी होगी इसलिए जानबूझकर नए-नए तरीकों के बहाने उच्च न्यायालय का स्थगन न्यायालय में स्थगन और अन्य बातें और षड्यंत्र बहाने बनाकर चुनाव में को टाला जा रहा है। सच यह भी है कि पूरे प्रदेश के निगम और पालिकाओं में बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज राजस्व के राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के साथ उप, सहायक, कार्यपालन अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता तक, फिल्म स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी जिसमें 25% केवल कागजों पर ही जो नेताओं मंत्रियों विधायकों सांसदों क्या खास काम कर रहे हैं। करुण रुपए महीने में उनका वेतन भोजन किया जा रहा है दूसरी तरफ ऊपर के स्तर पर सभी स्थाई कर्मचारी अधिकारी सैकड़ों करोड़ का हर महीने भ्रष्टाचार करते हैं परंतु 30-30% इस साल से काम कर रहे हजारों सफाई कर्मियों को नियमित करने की बात तो दूर उन सब का शोषण करने के लिए उन्हें ठेकेदारी प्रथा में 5, 6, 7 हजार महीने का वेतन देकर उनका भी भारी शोषण किया जा रहा है। इस बात को कोई भी समाचार पत्र नेता कर्मचारी संगठन उठाने को तैयार नहीं उल्टे ही लूट बनी रहे सब के सब जुटे रहते हैं।

अकेले नगर निगम इंदौर में पिछले 20 सालों में ढाई हजार करोड़ सीवर लाइन बिछाने, बिना टोप्पो और कांटूर मेप के प्लानिंग कर ठाकुर करो के ठेके टीसीएस वाली कंपनी को लेकर मोटा कमीशन हजम कर लिया जाता है। जिसको जो समझ में आता है बिना त्वरण वेग के कहीं 8 फुट कहीं 6 फुट 7 फुट गहरी नालियां कभी एक चुटकी कभी जोड़ दो ढाई 3 फुट से लेकर 1-2मीटर के स्टॉर्म वाटर लाइन पर बिछाने में जे एन एन आर यू एम, एडीबी वर्ल्ड बैंक वह अन्य संस्थाओं से पैसा लेकर बर्बाद किया गया। पिंटू बरसात होने पर चारों तरफ तालाब बनने की छुट्टी पूरे इंदौर टाइम बनी रहे और यही हाल न केवल इंदौर भोपाल से लेकर सभी छोटे शहरों में भी बना रहता है। सीवर लाइन और जलपूर्ति में पिछले 8-9 सालों से बैठा भ्रष्ट और जालसाज संजीव श्रीवास्तव, जो मोटा पैसा कमाता व बांटता है। सर भ्रष्टाचार करने के बाद में भी कोई बात नहीं कोई इंक्वायरी नहीं कोई लोकायुक्त का छापा नहीं, वही हाल जलापूर्ति में भी किया जा रहा है उसी के समय में फेस 2- 3 की पाइप लाइन डाली गई 24 घंटे पेयजल पूरे शहर को मिलेगा। उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए सारा पानी तीसरे चौथे समय का शहर के बाहर की कॉलोनियों उद्योगों को आपूर्ति किया जा रहा है आप शहर वही 2 दिन में आधा घंटे जलापूर्ति होती है कई स्थानों पर तो लोग पानी के बिलों का भुगतान वापस कर रहे हैं रू. 300 महीने का कर वहां पर नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है उसकी शिकायत मैंने अपने घर की तिलक नगर एक्सटेंशन 47 की पिछले अनेकों सालों से की जा रही है पर घर पर पानी नहीं पहुंचा पर बिल अवश्य पहुंच रहा है। और समाज में इज्जत के लिए मेरा भाई उसका भुगतान भी कर रहे हैं। उसमें भी 27 ओवरहेड टैंक बनवाए गए। उस कंपनी का भी ठेका उस जालसाज और राम की कंपनी को दिया गया जो कई जगह से ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। ऐसे अनेकों काम अपने खास ठेकेदारों को देकर कागज पर ही भुगतान हजम किया जाता है। चीनी ठेकेदारों को भी फिल्टर प्लांट सीवर लाइन का कबीट खेड़ी में दिया गया। जबकि सारे शहर में फेस बानू टू की लाइनें लगातार फूटने बनाने मरम्मत करने के नाम पर लगभग 5 करोड रुपए हर महीने आवंटित किया जा कर वह ऐसा ना केवल संजीव श्रीवास्तव निगम आयुक्त कलेक्टर कमिश्नर को भी बंटता है। स्वाभाविक है नियमित रूप से लाइन फूटना भी आवश्यक है ताकि हर माह, बेचारे इन भुखेरे श्वानों का पेट पलता रहे, बदले में जनता पेयजल के लिए भी जो 2 दिन में एक बार आधा घंटा आता है वह भी ना मिले ताकि जनता को मालूम पड़े कि कितना काम चल रहा है। वही हाल जलपूर्ति के जलूद स्थित नर्मदा से जल एकत्रित कर शहर को आपूर्ति करने वाले संभाग क्रमांक एक में बैठा कार्यपालन यंत्री जिसके पास इंदौर संभाग मैकेनिकल विद्युत में भी पता है पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से वह इंदौर में ही बैठा हुआ है और घोर भ्रष्ट और जालसाज होने के कारण उसके ऊपर अनेकों बार छापे पड़ चुके हैं परंतु वहां भी जलूद स्थित पंपू में नियमित मरम्मत, सुधार कार्य में, करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है जिसमें से 40 से 50% तक फर्जी होते हैं।

स्मार्ट, सिटी व स्वच्छता की आड़ में चल रहा लूट का तांडव

भोड़िया झुंड पार्टी के मोदी से लेकर अदने सा नेता भी सत्ता के मद में चूर होकर लूटने के लिए सड़क पर सड़क बनवा रहा है। और बदले में उप जिलाधीश स्तर के अधिकारी से लेकर अन्य अनेकों सरकारी अधिकारियों को परेशान कर रहा है। सोच सकते हैं आमजन के साथ क्या गुजर रही होगी?

दूसरी तरफ नगर निगम पालिकाओं का सारा काम जो जोनल अधिकारी व क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी करते थे। अब वह सारे काम पार्षदों के हाथ में है।

कर्मचारी नगर निगम के होते हैं। हर शिकायत अब उसके व्यक्तिगत कार्यालय में ली जाकर हर काम मोटी वसूली करवाने के बाद पार्षद की इच्छा के अनुरूप और अनुसार किए जाते हैं।यदि उनके वोटर नहीं हैं।या उनके विरुद्ध चलते हैं। तो उन नगर निगम के कर्मचारी जिन के वेतन का धन जनता से वसूल किया जाता है। समस्या दूर करने की अपेक्षा परेशान करते रहते हैं।

आखिर जब मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार है। और सारे नगर निगम पालिकायें सब शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो फिर नेताओं और पार्षदों के इशारे पर नाच कर क्यों जन समस्या को बढ़ा रहे हैं। तत्काल ही मुख्यमंत्री व शहरीय विकास मंत्रालय के अधिकारियों को देखना चाहिए। कि अगर ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। तो उसे तत्काल रद्द करें और नया आदेश देकर पार्षदों नेताओं से काम लेकर पुनः क्षेत्रीय निगम और पालिकाओं के कर्मचारी व अधिकारी समस्याओं को अपने स्तर से दूर करें।। बेशक यह लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ताकि उनका वोट बैंक मजबूत होता रहे। जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। कोई भी निर्माण जो रु 5000 से ज्यादा का हो कार्य विपक्ष के हारे हुए पार्षद व अन्य तीन चार लोगों से मिलकर ही और उनकी सहमति से ही करवाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। वरना तो यह पार्षद भी सत्ताधारी दल की ईवीएम की जालसाजी से जीतकर निगम और पालिकाओं को अपनी लूट का अड्डा बना कर एक तरफ निगम और पालिकाओं को कर्जदार बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्वयं करोड़पति से अरबपति हो चुके हैं। और जनता के लिए समस्याएं दूर करने की अपेक्षा बढ़ाने और परेशान करने पर तुले रहते हैं। इस पर त्वरित और सटीक कार्रवाई कानून रूप से की जानी चाहिए। इंदौर की घोर भ्रष्ट महामक्कार महापौर मालिनी गौड़, को इंदौर के विकास से नहीं अपने और अपनी भेड़िया झुंड पार्टी के भ्रष्टाचार से विकास से मतलब है। ताकि चुनावों के समय पर सैकड़ों भंडारे, पार्टीयां कर, बड़े-बड़े समाचार पत्रों में 5-5 पेज के विज्ञापनों को छपवा जनता को भ्रमित कर सकें। सारी सीमेन्ट कांक्रीट की सड़कें पिछले साढ़े 4 सालों में पहले 1' की, फिर दूसरी बार डेढ़ फुट की फिर तीसरी बार 2' आदि अलग2 सड़कों पर नालीयो की पाईप लाइन बिछाने के नाम पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई है। बनाने बिगाड़ने फिर बनाने के नाम भ्रष्ट भेड़ियों का झुंड जनधन नोंचने खाने में लगा हुआ है। फिर पैसा खत्म हो जाए तो नगर निगम हजारों करोड़ के ऋण एशियन विकास बैंक से विकास बॉन्ड के नाम से इकट्ठा करके हजम कर चुका है।पर अंध भक्तों को समझ आकर भी समझ नहीं आयेगा।

नर्मदा के तीन चरणों में 360 एम एल डी पानी कहाँ जा रहा है।

जबकि पिछले 20 सालों से पूरे इंदौर नगर को 2 दिन में एक बार आधा घंटे पानी की आपूर्ति की जा रही है और बिल बढ़ाकर रू. 60 से रू.300 कर दिया गया है। जबकि दो दिन में एक बार 20-30 f?मनि ट पानी की आर्पूत? की जाती है। इसके बाद में भी पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। क्योंकि रसूखदार बड़े व्यापारी, उद्योगपतियों, नेता, मंत्रीयों, पार्षद, अधिकारीयों, भ्रष्ट कॉलोनाइजरों की कालोनियों में बहुमंजिला इमारतों में इंदौर में बसी हुई 3000 से ज्यादा छोटी-मोटी फैक्ट्रियों 500 से ज्यादा अस्पतालों 300 से ज्यादा होटलों में पानी आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। रसुखदारों के कुत्ते रोज 100 लीटर से ज्यादा नर्मदा जल से नहाते हैं। 100-200लीटर पानी से ज्यादा कारें धुलती हैं। फिर भी 90% बिल नहीं भरते हैं। जनता को पानी नहीं मिल रहा है। फिर भी बिल दिए जा रहे हैं और वसूले भी जा रहे हैं। 500 से ज्यादा टैंकरों से पानी बैच कर पैसा कमाया जा रहा है। हर पार्षद के द्वारा आखिर हर दिन 500 टैंकरों को भरने के लिए पानी कहां से आ रहा है। वहीं नर्मदा की जलापूर्ति की टंकियों से पानी लेकर बेंच कर मोटी कमाई पार्षदों टैंकर चालकों जलापूर्ति करने वालों के माध्यम से की जा रही है। यह सच कोई नहीं बता रहा। स्वच्छता के नाम पर भारी मोटी अरबों रुपए कीमिनी ट्रकों ट्रकों की खरीद की गई बदले में सभी अधिकारियों समितियों के पदाधिकारी पार्षदोंमहापौर निगम आयुक्त उपायुक्तों को कार्य मुफ्त में भेंट की गई स्वच्छता के नाम पर जनता को भी भारी चल तब से लूटा जा रहा है जबकि जनता पूर्व से ही संपत्ति कर और स्वच्छता का कर दे रही थी आखिर इन सब लूट के बाद पहले 200 करोड़ का बाजार से कर्जा लिया गया और बाद में 600 करोड़ का कर्जा लेकर आशीष सिंह ने अपनी पीठ दबाकर पुरस्कार भी लिए आखिर इतना सारा धन जा कहां रहा है या लूट के लिए सभी नेताओं पार्षदों पर ठेकेदारों अधिकारियों को छूट देकरखर्चों की भरपाई के लिए बाजार से ऋण लेकर जनता के माथे पर लादा जा रहा है। साढ़े 4 सालों में घोर भ्रष्ट और लालची महापौर पार्षदों और10-15-20 सालों से जमे हुए अधिकारियों ने लगभग रु 5000 करोड़ से ज्यादा केवल नालियां, सड़के बनाने, सफाई के नाम के ही हजम कर लिये। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर 2000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों के निर्माण, सरकारी बगीचों में 500 से ज्यादा बिना टेंडर और विशेषज्ञों की सलाह व ठोस नियोजन और आधार के कचरे से खाद बनाने, 500 से कचरा निपटान केंद्र के नाम पर, स्वंय नगर निगम ने नालों की खाली पड़ी जमीनों पर, फूटपाथ की जमीनों पर, अपना इंदौर के सेल्फी सेंटरों के नाम पर बिना टेंडरिंग के करोड़ों ? के बिल भुगतान अपने खास पठ्ठों को किया जाकर हजम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी जनता के लाभ के लिए नहीं बनाई जा रही। नगर निगम में सेल्फीप्वाइंट के नाम पर करीबन चार सौ से ज्यादा खाली पड़ी सड़क के किनारे पर की लागत से बिना टेंडर जारी किए और डीपीआर तैयार किए। अपने खास खास लोगों को निर्माण के लिए दे दिए गए जिसमें मात्र 25% का काम हुआ वह 75% पैसा हजम कर लिया गया। इसकी भी कोई जांच नहीं की जा रही और ना ही कोई इसका जवाब देने को तैयार है। यह सब कुछ केवल लूट और भ्रष्टाचार से वसूली का तांडव है। यही हाल सूत्र सेवा की बसों का भी है जहां पर 50% राशि शहरीय विकास के नाम पर केंद्र सरकार से अनुदान पर मिली थी और 50% राशि बैंकों ने वित्तीय सहायता देकर खरीद करवा ली गई अब प्रश्न यह उठता है जब शहर की सड़कें पर्याप्त चौड़ी नहीं तो वहां पर इतनी बड़ी हुई बस चलाकर सैकड़ों लोगों को घायल करके 30 से ज्यादा लोगों की यथार्थ में दुर्घटना के नाम पर हत्या कर दी गई। मात्र अपनी मोटी कमाई के लिए जबकि दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में चलने वाली बसों को इसलिए बंद कर दिया गया कि वह सारे दिन छोटी-छोटी सड़कों पर ठूंस ठूंस के बसों में सवारियां भरकर यहां वहां तांडव करती थी। परंतु इसके विपरीत सूत्र सेवा की और नगर निगम की बसें पूरा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सरवटे बस स्टैंड घेरे रखती हैं। और लोगों को अपने दोपहिया चार पहिया वाहन चलाने में भारी दहशत और परेशानी का सामना करना पड़ता है चूंकि शासकीय अधिकारी हैं।ये हरामखोर, जालसाज जिलाधीश निगमायुक्त, संभागायुक्त, महापौर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सब मिलकर अटल बस सेवा की आड़ में मोटा लूट का तांडव कर रहे हैं। बदले में शहर में उसकी लंबी चौड़ी बड़ी-बड़ी बसें घूमते हुए वह भी ठूंस कर सवारी भरकर छोटी-छोटी गलियों यहां तक कि भागीरथपुरा, एमजी रोड जहां पर्याप्त निकलने के लिए दोपहिया चार पहिया वाहन चालकों को जगह नहीं होती है। वहां पर 15 फुट चौड़ी 35-40 फुट लंबी बसें दौड़ाते हुए आमजन को भारी दहशत और दुर्घटनाओं का तांडव मचाते घूमती रहती है। जिसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि जब उससे निजी आधी मिनी बसें चलाने के लिए तो जगह नहीं थी। तो यह फिर सरकारी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बसें चला कर पिछले 3 सालों में 30 से ज्यादा लोगों को दुर्घटनाओं मार चुकी हैं। और सैकड़ों को घायल कर चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन? उनकी मौत पर शासन बीमा भुगतान करे।

(शेष पेज 11 पर)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय भ्रष्टाचार विभाग

जल जीवन मिशन के नाम चल रहा अरबों का भ्रष्टाचार

प्रमुख अभियंता से कार्यपालन यंत्री तक खरीदी में भारी भ्रष्टाचार

केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रमुख सचिव से लेकर घोर भ्रष्ट जालसाज प्रमुख अभियंता सोनगरिया के साथ-साथ सभी परिक्षेत्रों के प्रभारी मुख्य अभियंताओं ने अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्री के साथ मिलकर अरबों रुपए की पाइपलाइन आतंकियों टोक्यो के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों प्रदेश की लगभग 40000 ग्रामीण आंगनबाड़ियों में, हैंडपंप खुदाई और उसकी स्थापना में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहां तक की जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का स्वयं का विद्युत अभियांत्रिकी का हर संभाग स्तर पर संभागी कार्यालय है जहां पर सभी जिलों में उसके उप संभागीय कार्यालय हैं वहां पर जो ड्रिलिंग मशीन ए है उनसे खुदाई ना करवा कर जिलों के सभी संभागीय मंत्री निजी क्षेत्रों की ड्रिलिंग मशीनों को काम देकर हैंडपंप खुदाई और उसका स्थापना करवाने में लगे हुए हैं। बेशक अधिकांश विद्युत अभियांत्रिकी संभागों में जो कार्यपालन यंत्री बैठा है वह घर भ्रष्ट और बरसों से कुंडली 12 बैठा होने के साथ-साथ खरीदी में मशीनों की रखरखाव सुधार एवं मरम्मत के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है और मोटा कमीशन अपने मुख्य अभियंता अशोक बघेल को भी पहुंचा रहा है इसलिए वहां बैठे कार्यपालन यंत्री भी सप्ताह में एक दो बार ही अपने संभागीय कार्यालयों में पहुंचते हैं जैसा कि उज्जैन में वर्षों से हो रहा है। अधिकांश मुख्य अभियंता वाह अधीक्षण यंत्री कार्यालयों में प्रभार के लिए प्रभार देकर बिठा ले गए अधीक्षण व मुख्य अभियंता क्योंकि पैसा देकर बैठे हैं इसलिए खुलकर भ्रष्टाचार करने में विश्वास करते हैं यह भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो मासिक और रॉयल्टी का अपने प्रमुख अभियंता सॉन्ग रिया और मंत्री को कैसे भुगतान करेंगे। यही कारण है कि जब सूचना के अधिकार में इन हरामखोर से जानकारी मांगी जाती है तो मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठे अधिकांश मक्कार हर बार जानकारी देने के नाम पर सूचना आयोग के निर्णय को जो सन 2008 में दिया गया था कानून बनाकर अपनी खाल बचाने और भ्रष्टाचार छुपाने संदर्भ डालकर जवाब देकर जानकारी देने से बच जाते हैं। जबकि इन हरामखोर जलसा जुने प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंता से लेकर सभी संभागों और उप संभागों की जानकारी धारा 4 के अंतर्गत 16 साल के बाद में भी अभी तक अपनी साइट पर अपलोड नहीं की यही कारण है कि वहां हर संभाग के भंडार ग्रह में करोड़ों रुपए की पाइप लाइन, हैंडपंप केसिंग, ग्राम पंचायतों के नल जल योजना और जल जीवन मिशन में आपूर्ति की जाने वाली मोटर पंप का भंडार बरसों से सड़ रहा है उसका उपयोग तो नहीं किया जाता वरुण हर बार हर साल केंद्र और राज्य के प्लान और नान प्लान के अंतर्गत प्राप्त आवंटन का मोटे कमीशन पर उपयोग करने के लिए खरीदने की जाती है। सूचना के अधिकार में उनके स्टॉक की जानकारी मांगने पर यह सारे के सारे जालसाज भ्रष्ट बहाने बना देते हैं पर जानकारी नहीं देते। लोक निर्माण विभाग के कार्य मैनुअल को ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जल संसाधन नर्मदा घाटी वह सभी कार्य विभागों में कानून के स्तर पर स्वीकार किया जाकर उपयोग किया जाता है इसके विपरीत किराए की टैक्सी वाहन जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता कार्यालय करता है और साथ ही सबकी लॉग बुक और डेली डायरी अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री यों की मुख्य अभियंता कार्यालय में पहुंचती है तब भी सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर इंदौर का मुख्य अभियंता सोलंकी और उनका लोक सूचना अधिकारी के साथ उनका अपीलीय अधिकारी मालवी जिनकी अपनी खुद की कारें एसयूवी टेक्सियां के रूप में विभाग में ही चलती हैं। की हाल इंदौर में बरसों से कुंडली मारे बैठे चेतन रघुवंशी की भी अनेक ऑप्टेक्स या अलग-अलग नामों से ना केवल स्वयं के विभाग में वरन अन्य विभागों में भी चल रही हैं। इसलिए कोई भी टैक्सी के संबंध में उसके टेंडर उसका टैक्सी परमिट आदि की जानकारी देने के नाम पर बदतमीज बहाने तो बनाते हैं पर जानकारी नहीं देते क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार का काफी धन बरस रहा है इसलिए जानकारी कैसे ली जा सकती है दूसरी तरफ इंदौर ग्रामीण संभाग में बैठे सुनील उद्या जो सैकड़ों करोड़ के 1 इंच से लेकर 2 मीटर की प्लास्टिक की पाइप लाइनों से लेकर एमएस स्टील की पाइप लाइनों की खरीदी में सीएसके भ्रष्टाचार के हीरो रहे हैं जिन्होंने 72000 शौचालय योजना घर बनाने का बिल का भुगतान करवाया जबकि वहां 20020 शौचालय स्नानागार नहीं बनाए गए थे वही हाल 5000 हत्या जमीन पर सभी साधनों और रहवासियों के लिए जो प्लॉट काटे गए थे उन में पानी की आपूर्ति करने में भी लगभग दो लाख से ज्यादा 35 40 में खरीदी गई और जिनका उपयोग भी नहीं हुआ वही हाल और करोड़ों रुपए की पाइपलाइन अभी तक उज्जैन के जंतर मंतर के सामने के स्टोरी आड में पड़ी हुई रही है 5 साल के बाद में भी उसका उपयोग मध्यप्रदेश में अन्य संभागों के नल जल योजना जल जीवन मिशन की पाइप लाइन में नहीं किया जा सका इसका मूल कारण भ्रष्टाचार से बरसता हुआ धन और भ्रष्ट अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता का संरक्षण ही है। इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों को कैसे हतोत्साहित कर अपने भ्रष्टाचार जलसा जियों को छुपाना है और किसी भी हाल में जानकारी उपलब्ध नहीं करवानी है के लिए सारे अधिकारी इंजीनियर एकजुट एकमुश्त एक राय रहते हैं।

लोनिवि परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मोटी डीपीआर मोटी कमाई, सारे कार्य ठेके पर

लोनिवि के घोर भ्रष्ट जालसाज और अर्धज्ञानी इंजीनियर सब पीआइयु में

लोनिवि के जितने भी घोर भ्रष्ट जालसाज और अर्धज्ञानी इंजीनियर सबको पीआइयु में भेज दिया गया उसका मूल उद्देश्य ही है। जितने विभाग हैं उनके सबके भवन निर्माण के कार्य वर्तमान में परियोजना क्रियान्वयन इकाई, के अंतर्गत किए जा रहे हैं और स्टाफ आए नहीं स्वामी की बातें ड्राइंग डिजाइन से लेकर डीपीआर बनेगी अब यहां पर कंसल्टेंट से करवाया जाता है। इसका 1.5इ होता है और ज?तनी बड़ी होती है उसका उतना बड़ा कमीशन बनता है। पीआईयू के जितने भी संभागीय यंत्री व परिक्षेत्र स्तर पर बैठा विद्युत एवं यांत्रिकीय का संभागीय यंत्री हैं। सब के सब चुंकि नियमित संभागों में जिलों के कार्यों पर ना केवल राजनीतिक नेताओं की बल्कि जनता की भी नजर रहती है और फिर सूचना का अधिकार के संबंध में पत्रकार भी जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं इसलिए वहां थोड़े से समझदार विशेषज्ञ यंत्री बैठा ले जाते हैं। परंतु पीआईयू में अधिकांश लोक निर्माण विभाग के वह घोर भ्रष्ट जालसाज और अर्धज्ञानी लोगों को ही पदस्थ किया गया है जो ठेकेदार के इशारे पर नाच कर जो अधिकांश मोदी के राज्य के उनके नेताओं के भाई भतीजे गुजरात के हैं। काम कैसा भी हो उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो बस डिजाइन और ड्राइंग दी जैसी बनी हो कैसे भी काम करते हो करवा कर भुगतान करके कमीशन वसूलने में विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण निम्न तथ्य है कि यहां पर सहायक यंत्री जोकि विभाग के उपयंत्री हैं, पदस्थ कर दिए गए हैं जिनका काम भी बिल बनाने और जांच करके उस पर हस्ताक्षर करने से पहले अपना कमीशन वसूलने में विश्वास रखते हैं। सहायक यंत्री के अंतर्गत जो संविदा उपयंत्री है। जो यथार्थ में काम और काम की गुणवत्ता और नाप पुस्तिका भरते हैं। वे एसक्यूसी के माध्यम से सब ठेके पर संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। जिन्हें नियुक्त करते समय जबकि वह तकनीकी सिविल डिप्लोमा या डिग्री धारी हैं। इसके बावजूद उनको 14- 15000 महीने की नौकरी पर रखा जाता है. भोपाल से ठेकेदार के माध्यम से जिसका मोटा कमीशन पीडी नरेंद्र कुमार लेकर पूरे प्रदेश के 50 संभागी यंत्री कार्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। पर यथार्थ में ठेकेदार विभाग से रु 15000 लेकर उनको रु 10-12000 महीने ही तीन चार चार महीने तक लंबित कर भुगतान करता है। बाकी हजम करके उन्हें दूर-दराज के गांव में भेज देता है। तो वह भी उसी तरह से ठेकेदारों के काम पर निगरानी करते हैं। और नाप पुस्तिका भरने के बदले में वह भी मोटा कमीशन हजम करते रहते हैं। बाकी समझा जा सकता है कि किस प्रकार से संविदा कर्मी भी अपने कामों को अंजाम दे रहे होंगे। आपने देखा कई भवन बनते बनते उनकी दीवारों में दरारें आने के साथ-साथ अधिकांश मामलों की छतें टपकने, स्नानागार व शौचालय की टाइल्स उखाड़ने लगती हैं। लोक निर्माण विभाग के पीआईयू के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों यथा स्वास्थ्य, न्याय, आदिम जाति, कृषि, स्कूली व उच्च शिक्षा, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, जिलाधीश कार्यालय, पुलिस, जेल, पंचायत, वाणिज्य कर, आबकारी, खनिज, खेल आदि विभागों का केंद्र व राज्य का पैसा, भवन निर्माण, मरम्मत पुर्ननवीनीकरण के लिए उनको आवंटित धन सीधा विभागों से मिलता है। इसलिए यदि संबंधित विभाग के अधिकारी यदि ज्यादा जागरूक और होशियार नहीं होते व भ्रष्टाचार से बंदरबांट के शौकीन होते हैं तो नक्शे तक बदलकर भवनों के निर्माण के साथ फर्निशिंग खिड़कियां दरवाजे विद्युत आदि की व्यवस्था में स्तरहीन काम कर अधिकांश संभागीय व सहायक यंत्री मोटी वसूली करते रहते हैं और अधिकांश भवन निर्माण विवादास्पद स्थिति तक पहुंचते ही हैं। कहानी बजट के आवंटन से पूर्व आवश्यकता और डिजाइन से शुरू होती है। यहां पर कंसल्टेंट भवन का डिजाइन भूमि के मिट्टी के स्तर, नीचे के स्ट्रेटा की स्थिति से लेकर भवन की दीवारों छत ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और पूरे भवन के भजन के साथ उस भूमि या क्षेत्र की भूकंपरोधिता की स्थिति तक को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है परंतु यहां पर तो मोटे कमीशन के चलते सिस्टमैटिक स्केल और भूकंप की स्थिति को केवल कागजों में दिखाया जाता है डिजाइन उसके हिसाब से की जाती है प्रकार उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरी तरफ सभी डीपीई भवन निर्माण में खोदी जाने वाली फाउंडेशन, लोड फैक्टर में, फाउंडेशन में खोदी गई मिट्टी पत्थर आदि को, सीमेंट, गिट्टी, बजरी, व अन्य सामग्री के लाने ले जाने में भी खुलकर लूटपाट कर मोटे बिल लगाए जाते हैं। जिसमें सारे संभागीय यंत्री इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, जो इंदौर एबीडी के अंतर्गत आते हैं। देवास, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल आदि जो भोपाल के अंतर्गत उसी प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के अंतर्गत आने वाले सभी संभागीय यंत्री कार्यालयों में मोटा धन लेकर लोनिवि मंत्री गोपाल भार्गव ने चुन चुन कर सभी सहायक यंत्री भ्रष्टों को संभागीय यंत्रियों का प्रभार लेकर, प्रभार देकर पदस्थ किया है। बाकी मासिक वसूली पीडी और एपीडी लेकर मंत्री को पहुंचाते हैं। तो स्वाभाविक है, कि पदस्थ किए गए सहायक व संभागीय यंत्री मोटी वसूली भ्रष्टाचार करके ही भुगतान करते हैं। तो भवनों की गुणवत्ता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है।जो नियमित कार्यपालन यंत्री इनके पास बरसों का अनुभव और ज्ञान है। परंतु वे जब भवनों की गुणवत्ता और हेर-फेर में ज्यादा विचलन कर भ्रष्टाचार करने को तैयार नहीं हुए। और मोटी मोटी बसूली है पीडी पीडी का मंत्री को नहीं पहुंचा पाए तो उन सबको एपीडी कार्यालयों में संलग्नक अधिकारी बना कर पदस्थ कर दिया गया या उन्हें पुनः भवन एवं पथ के मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री कार्यालयों में संलग्न कर दिया गया। अर्थात ईमानदारी, गुणवत्ता, भ्रष्टाचार ना करना भी यथार्थ में शासकीय सेवाओं में एक अभिशाप है। सरकारी सेवा के लिए घोर भ्रष्ट, अर्धज्ञानी, गुणवत्ताहीन कार्यों को अंजाम देने वाले, ठेकेदारों के साथ मिलकर दलाली व भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी अधिकारी इंजीनियर सफल प्रशासक और अधिकारी, कर्मचारी माने जाते हैं। उनकी हर जगह पूछ, मन चाही पदस्थी, मनचाहा मोटी कमाई वाला क्रीम का पद, प्राप्त होता है। उसके लिए सारे नियम कानून तोड़े और बनाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग है। जिसके लिए हर विधायक इस विभाग का मंत्री बनना चाहता है।

निगम में वर्षो से जमे भ्रष्ट जालसाज डकैत अधिकारी इंजीनियरों का अड्डा

(पेज 10 का शेष)

बरन कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं, पार्षदों, महापौर, विधायकों, सांसद के मोटे लाभ के लिए मोटे प्लाटों, बड़े बंगलों, बड़ी फैक्टीयों का निर्माण उसमें मोटे कमीशन जो 20 से 40% तक है। हजम करने के लिए सारा षड्यंत्र जिसमें स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन के नाम पर भी किया जा रहा है। वैसे ही जैसे बीआरटीएस के नाम पर 200 करोड़ खर्च करके साडे बारह सौ करोड़ हजम कर लिए गए और परेशान जनता हो रही है। सैकड़ों लोग उस बीआरटीएस के पर पिछले आठ-दस सालों में दम तोड़ चुके हैं। पर इन हरामखोरों को उसे तोड़ने की नहीं उसके ऊपर नए-नए निर्माण करने का बहाना मिल गया। उस पर कहीं फुटओवर ब्रिज कहीं अंडर ब्रिज कहीं फ्लाईओवर बनाने के बहाने मिल चुके हैं इन जाल साज डकैत गिद्धों को। जिस कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बीआरटीएस तोड़ने की बात कही थी। उसको भी अब मोटी कमाई नजर आ रही है। इसलिए बीआरटीएस तोड़ने की अपेक्षा वहां पर फ्लाईओवर मेट्रो ट्रेन फुट ओवर ब्रिज बनाने के नाम पर मोटा धन हड़पने के सपने देख रही है। यह सारे गिद्धों की फौज जनता की सुविधा के नाम पर अपना मोटा धन इकट्ठा करती है। और इंदौर उसके लिए एक बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। यहां कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम, ऐडीएम, तहसीलदार लूटने खाने के लिये आते और आकाश त्रिपाठी की तरह वर्षों अजगर की तरह कुंडली मारे मोटा हिस्सा हजम करने लिपटे रहते हैं। जनता परेशान हो मरे, गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां चांडालों की फौज को बुड्ढा मरे या जवान इन्हें लूटने से काम। और मिडिया के भांड वैसे तो अधिकांश दैनिक भास्कर पत्रिका नई दुनिया राज एक्सप्रेस सभी बड़े भूमाफिया कॉलोनी माफिया हैं जिन्हें जनता से नहीं अपनी अवैध जमीनों पर, अपने मीडिया पावर के दम पर छल, बल से सरकारी जमीन पर कब्जा कर, बड़ी कालोनियां मल्टिया बनाकर बेचने से मतलब रहता है। अपने समाचार पत्रों का उपयोग अवैध रूप से कटी हुई कॉलोनिया बनाई हुई, बहुमंजिला भवनों को बेंचने के लिए विज्ञापनों को भी समाचार बना कर उपयोग करते हैं। रोज उसकी आकर्षक कहानियां चिपका के जनता को बेचते हैं। शासकीय कार्यालयों, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, में जो भ्रष्टाचार चल रहा है। उसकी सत्यता नहीं, वरन् भ्रष्टाचार के कांडों में मोटा हिस्सा डकार कर जनता को यहां वहां की फिल्मों के आपराधिक प्रवृति के राष्ट्र द्रोही खलनायक खानों की, बॉलीवुड की नगर वधुओं की, क्रिकेट की, विदेशों के घूमने फिरने के स्थानों की कहानियां पढ़ा कर भ्रमित कर अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं। सूचना के अधिकार में नगर पालिका निगमो, विकास प्राधिकरणो, सरकारी कार्यालयो, जानकारी मांगने पर, सारे घोर भ्रष्ट, जाल साज अधिकारी-कर्मचारी, अपने भ्रष्टाचार छुपाने जानकारियां देने की अपेक्षा आवेदक को परेशान करने, चाही गई जानकारी के दस्तावेजों को गिने बिना ही हजारों रुपए के मांग पत्र भेज कर उल्टा ही चमकाने की कोशिश करते हैं। अपीलो में जाने पर महीनों तक कोई जवाब नहीं दिया जाता बार बार पूछताछ करने पर बुलाकर किसी भी बहाने बिना प्रकरण को समझे सारे भ्रष्ट जाल साज और मक्कार अपीलीय अधिकारी उसे रद्द कर देते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को लगे 14 साल गुजर जाने के बाद में भी हरामखोर जालसाज प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री, सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्तों, संचालकों, से लेकर नीचे तक ग्राम पंचायत स्तर तक किसी ने भी धारा 4 के अंतर्गत 17 बिंदु की जानकारी अपनी विभागीय साइटों पर अपने भ्रष्टाचार छुपाने और जनधन की लूटपाट के चलते अपलोड नहीं की। और ना ही किसी विपक्षी दल ने गांव शहर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग की। जो खुले में सरकार द्वारा स्वयं सरकारी कानूनों का खुला मजाक है।

साप्ताहिक समय माया

जागो अति ज्ञानी हिंदुओं

बहुराष्ट्रीय कं. व ईसाई संगठनों के इशारे पर हिंदुओं का किया नरसंहार

हिंदुओं के रक्षक नहीं, भक्षक, कोरोना व टीके से 10 करोड़ से ज्यादा की हत्या

गुजराती चांडाल राक्षस, चोर कबाड़ी, खानदान का मोदी सभी शासकीय संस्थानों का निजी करण कर रहा है। तो दूसरी तरफ उस पैसे से अपने लिए 25000 करोड रु का सेंट्रल विस्टा 8.5 हजार करोड़ का हवाई जहाज, करोड़ों रुपए की मिसाइल डिफेंस सिस्टम व अन्य सामग्री की कीमत अलग वह भी सैकड़ों करोड़ में, हर दिन लाखों की 5-6 डिजाइनर नई ड्रेस, जो एक बार पहन ली वह दूसरी बार नहीं पहनता। प्रतिदिन रू. 1लाख का भोजन, अरबों रुपए की डिजाइनर बुलेट प्रूफ कारें, चाहिए यह फकीर है। जो जनता को रू. 35 का पेट्रोल रु 122/- डीजल रु105 प्रति लीटर, रू डेढ़ सौ की गैस रू. 950/- में बेचकर जनता का खून पीता है। उन पूंजी राक्षस सेवा संघ के लोग क्योंकि उनके राजनीतिक मुखोटे भाजपा का शासन है मुंह में टुकड़ा चबाते बैठे हैं। उन हरामखोर खाकी चड्डी वालों का अब राष्ट्रवाद हिंदू वाद खत्म हो गया। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या और अफगानी सबको हिंदुस्तानी बनाकर, मुस्लिमों का भी डीएनए एक बना दिया गया। दूसरी तरफ जिन हिंदुओं कि वोट लेकर वह डकैतों का गिरोह सत्ता में आया। अब उन हिंदुओं को अगड़ा, पिछड़ा, दलित, बनाकर हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाकर आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय और ईसाई संगठनों के इशारे पर उनका महामारी की आड़ में मौतों का महोत्सव मना कर श्मशान में भी लाइन लगवा कर चिताओं को जलाने के लिए भी युद्ध करवा दिया गया। समझो हिंदुओं। तब भी मुसलमानों की पूरे देश में कहीं भी कब्रिस्तान में लाइन लगाकर आम जनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा कब्रें ना तो खोदी ही गई ना लोगों को दफनाया गया। मरने वाले 90% हिंदू ही थे। आखिर क्यों नहीं जन्म मृत्यु के आंकड़ों सच्चाई बता रही सरकार। फिर भी बच गए उनको टीका लगाकर अकाल मौत देने के साथ पूरी कौम को नपुंसक बनाया जा रहा है। इस प्रकार पूरी हिंदू कौम को सफाई की तैयारी की जा रही है और यह सिरफिरे, मक्कार, घोर स्वार्थी, लालची हमारे हिंदू इस सच्चाई को समझने की तो दूर मौतों के तांडव को देख कर भी अनदेखा कर कोई पिछड़ा बनने की होड़ लगा है। तो कोई दलित बनने के लिए जी जान झोंक रहा है। टीके से मौतों का तांडव देख कर भी, हिंदुत्व का चोला ओढ़े नेता, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अपने ही हिंदू भाइयों को डरा धमका कर, घर से निकाल निकाल कर लालच देकर टीका लगाकर बर्बाद करते हुए भी महानता दिखला रहे हैं। इसका परिणाम जनवरी 22 से तत्काल देखने में सामने आ जाएगा जब सरकारी और निजी अस्पतालों में हिंदुओं के 100 बच्चे भी पैदा नहीं होंगे तब मुस्लिमों के हजार से ड़ेढ हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा होंगे। बकते रहो एक दूसरे के देवी देवताओं को, अगड़े पिछड़ों एक दूसरे को गालियां। हर चांडाल जाहिल धूर्त शासक भी यही चाहता है। उनकी षड्यंत्रकारी जालसाजो कि आईटी टीम करवा रही है। आप कर रहे हो। उसकी आड़ में आप से लूटे गए धन से बनाई गई संपत्तियां वह बेच बेच कर खा रहे हैं मौज उड़ा रहे हैं और विदेशों को पहुंचा रहे हैं।

कब जागेंगे अति ज्ञानी हिंदुओं।

दूसरी तरफ जिन मुस्लिमों का भय दिखाया गया था उन मुस्लिमों को एकजुट कर उनको 43 से ज्यादा योजनाओं में न केवल फायदा दिया जा रहा है। वरन आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। यह हमारे हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा। अतिज्ञानी, अंधभक्त व अन्य सभी मुझे गालियां बकने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि मैं अभी केवल तीसरी लहर के पाखंड को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं।अन्यथा प्रदेश का डकैत मुख्यमंत्री और जिलों के कलेक्टर किसी भी दिन किसी भी पल, अभी सारे अस्पताल जो डेंगू, वायरल, फ्लू, मलेरिया, निमोनिया इनफ्लुएंजा मोतीझरा, आदि के मरीजों से भरे पड़े हैं। उनको वो एक झटके में कोरोना घोषित कर पुनः तालाबंदी कर देंगे। तो सारा व्यवसाय बाजार सब चौपट हो जाएगा। और फिर खड़े हो जाना सब एक रु किलो का गेहूं और दो रु किलो चावल खरीदने के लिए। लाइन में। सब के त्यौहार रखे रह जाएंगे जैसा कि उनका सुनियोजित षड्यंत्र तैयार है। मुझ पागल का इस पाखंड के विरुद्ध, युद्ध 18 महीने से चल रहा है। और प्रभु से प्रार्थना है कि मेरी बल बुद्धि बनाए रख ताकि मैं इस तीसरी लहर के पाखंड को टाल सकूं। सब के त्यौहार राजी खुशी मन, बन सकें। फुटपाथ से लेकर बाजारों में बैठे सभी दुकानदारों की रोजी रोटी चल सके। पर आप सबको इन सब से कोई लेना देना नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको लड़ने झगड़ने बदतमीजी दिखाने जातिवाद का जहर फैलाने में तन मन धन से लगे रहना चाहिए। आपको 18 महीने के पाखंड से चेन नहीं मिला। किसी की भूख प्यास शिक्षा रोजगार बीमारी से क्या लेना देना। 7 साल में सारी बर्बादी भेडिया झुंड पार्टी ने जिन डरपोंक, लालची, भिखारी हिंदुओं को छद्म सुरक्षा विकास और अच्छे दिन के वादे पर भ्रमित कर ईवीएम की जालसाजी से बहुमत हथिया कर, सत्ता सुंदरी का अपहरण किया। आते ही साथ 7 साल में उन्हीं का सबसे ज्यादा विनाश नोटबंदी जीएसटी महामारी की तालाबंदी से किया। वैसे वे घोर लालची, मक्कार, मट्ठे, आलसी, पाखंडी, भाग्यवादी भेड़ें, इसी लायक ही हैं। और डरपोक 90% हिंदू जो अभी इस महामारी के पाखंड में अपनी नपुंसकता और सिर झुका कर चलने और अपने बदन की ऊन नुंचवाने, खाल उतरवाने के बाद भी मिमीयाने वाली भेड़ों की भांति भेड़ियों के द्वारा हांकने चलाने डराने के कारण ही कमजोर मानसिकता के कारण घर परिवार के सदस्यों बीवी बच्चों के बार-बार ज्ञान बांटने से अवसाद में जा, बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती होने पर वहां के चांडाल डॉक्टरों ने लूटा भी और लगभग 10 करोड से ज्यादा हिंदुओं का अकाल नरसंहार किया गया। मरने वाले 90% हिंदू थे। बाद में टीका लगवाने वाले भी 90% हिंदू ही हैं उसमें भी करोड़ों टीका लगवाने के बाद मर गए जिनकी आवाज भी बाहर नहीं आने दी जा रही। आखिर क्यों हुआ, और बहुराष्ट्रीय अमेरिकी व चीनी कंपनियां आपके ही देश की सरकार को खरीद कर कैसे अपने ऑनलाइन व्यवसाय को करवाने दहशत फैलाकर निम्न और मध्यम बरगी हिंदुओं की हत्या करवाने में सफल हुए क्योंकि मस्तिष्क व बुद्धिहीन डरपोक भिखारी लालची मानसिकता इतना सब कुछ देखने के बाद में भी मुफ्त की वैक्सिंन लगवाने दौड़ा जा रहा है। जबकि सरकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट ही बता व कह रही है। की टीका लगवाना आवश्यक नहीं उसके कारण आपके कोई भी लाभ से वंचित नहीं कल सकता।

करोड़ों लोग वैक्सीन लगवाने के बाद मरे और बीमार भी हो गए यह सब कुछ देखने के बाद में भी सुधरने समझने को तैयार नहीं। तो फिर हजारों साल की गुलाम और मुफ्त की खाने की मानसिकता के कीड़े मकोड़ों अकाल मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। हिंदुओं, मुसलमानों की आबादी वृध्दि दर सरकार कहती है 10.8ऱ और यह भी मानती है कि हिंदुओं की मात्र 1.8ऱ रह गई है। टीका लगने के बाद 0.8ऱ भी नहीं रह जाएगी। राशन भी, मकान, बिजली, मुफ्त का मिल जाए, शिक्षा भी मुफ्त की मिले, बिना पढ़े पास हो जाएं। नौकरी भी बिना मेहनत की मिले। तो सरकार टीके से मौत भी मुफ्त में दे रही है। वरण करो और स्वर्ग की सैर करो।

देश का इस्लामीकरण और हिंदुओं का खात्मा

मोदी के अंध भक्तों यह मोदी ही है। जो देश का इस्लामीकरण कर देगा और हिंदुओं का खात्मा हरामखोरों। यह समझ में आ रहा है। आज मुस्लिमों को बढ़ाने पढ़ाने लिखाने की 43 योजनाएं हैं। प्रशासनिक सेवाओं पुलिस एवं वन सेवाओं में उर्दू से परीक्षा करवा कर सामान्य हिंदुओं का सभी तरह से खात्मा किया जा रहा है। सूअरों। और हिंदूओं को खत्म करने के लिए, नोटबंदी, जीएसटी करोना और उसका सबसे बड़ा नायाब तोहफा हिंदुओं को जड़ से खत्म करने के लिए टीकाकरण, जिससे करोड़ों हिंदू तो मर ही गए साथ ही जो बचेंगे वह नपुंसक होने के साथ अनेकों बीमारियों का शिकार होकर धीरे-धीरे तिल तिल कर के मरेंगे। चांडाल अंध भक्तों। आईटी सेल के पढ़ाये हुए अंडभक्तों देख लिया अमेरिका में कैसी धज्जियां में बिखेरी गईं। उस सूअर चांडाल जाहिल मोदी की। तुम जैसे नामर्द नपुंसक देश के अंड भक्तों हिंदुओं को, सच्चाई बता कर उन्हें तंत्र मंत्र यंत्र से मन और शरीर से मजबूत करने की अपेक्षा उनको डरा डरा कर कमजोर नामर्द बना दो हरामखोंरों। ताकि आसानी से वह आप पर कब्जा कर ले।

(शेष पेज 7 पर)

FSSAI विश्लेषक प्रयोगशाला वाहन का चमका-धमका कर वसूली करने के लिए

मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग को पूरे प्रदेश में 9 संभागों में नौ चलित प्रयोगशाला वाहन बांटे गए हैं आश्चर्य की बात है कि ना तो उसमें ड्राइवर है, विश्लेषक और ना रसायनज्ञ ना ही उसमें उसके खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो नमूने लिए जाते हैं। उनके विश्लेषण के लिए पर्याप्त अन्य रसायनों की जो उसमें उपयोग में आते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। बेशक प्रयोगशाला वाहन 70लाख रुपए की बनाया जा कर खरीदी गई है। जिसके अंदर अनेकों मशीनें लगी हुई है। उनको चलाने के लिए और प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। उसमें ड्राइवर नहीं है सरकारी, तो निष्कर्ष यह है कि जितने भी अभिहित अधिकारी जो है उन्हें अपना ड्राइवर रखना है वह वेन चलाएगा जो वेन चलाएगा उसका बीमा होना चाहिए उसका लाइसेंस वाणिज्यिक लाइसेंस में जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही उसके अंदर आवश्यक जो रसायन, विश्लेषण में काम आते हैं।उनको भी अभिहित अधिकारी को ही खरीद कर उसमें रखना है। अब आप समझिए कि जब किसी को प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। अधिकारी को हर जिले के और हर जिले में वह महीने में 2 से 3 दिन उस क्षेत्र के जितने भी खाद्य उत्पादक और विक्रेता है उनके नमूने लेकर उसमें विश्लेषण तत्काल करके देना है। परंतु अभिहित अधिकारी को कोई प्रशिक्षण नहीं कोई विश्लेषक नहीं, कोई रसायनज्ञ भी नहीं, तो आखिर प्रयोगशालाओं में जो जन धन से खरीदी गई थी क्या उपयोग है? और मैंने आपको देखा होगा पिछले वीडियो में इंदौर में खड़ी एफएसएसएआई का जो विश्लेषक वाहन जो 15 दिन से ज्यादा समय से खड़ा हुआ है। कुछ महीने धूल खाने के बाद कबाड़ हो जाएगा क्योंकि उसे पर्याप्त सामग्री नहीं चलाने के लिए सरकारी कोई ड्राइवर नहीं वह पर्याप्त स्टाफ नहीं कौन सैंपल लेगा सैंपल ले भी लिए तो विश्लेषण कौन करेगा वह बिना विश्लेषण की उस प्रयोगशाला का उपयोग क्या है? आखिर करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद केवल नौटंकी चमकाने धमकाने व मोटी वसूली कर कमीशन खाने की थी। जिसके लिए वाहन खरीदे गए और नौटंकी की गई अगर कोई उपयोग नहीं है। पर्याप्त नियमित स्टाफ नहीं है तो सरकार यह नौटंकी करती ही क्यों है। और अगर विश्लेषण कर भी लिए गए उसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर भी ली गई अब क्योंकि उस वाहन का राजपत्र में कोई भी प्रकाशन नहीं हुआ है ना ही उसको अधिकृत किया गया है तो उस विश्लेषण रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर उसमें नमूने फेल भी हो जाते हैं, तो भी उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसमें कोई भी न्याया संगत कार्रवाई खाद्य मिलावट के खिलाफ व्यापारी और उत्पादक पर की जा सकती है तो आखिर नौटंकी केवल वसूली की ही आती है चमकाओ और वसूली करो यह उद्देश्य रह गया उस वाहन का। और यही हाल इंदौर में बन रही चंदातालावली में जो इंदौर की खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत बनाने वाली प्रयोगशाला में जो जमीन आवंटन किया गया था उस आवंटित जमीन के ऊपर कॉलोनाइजर ने कब्जा करके प्लॉट काटना शुरू कर दिया है और सरकार को इसके साथ ही अभिहित अधिकारी को इस बात की कोई चिंता नहीं हो रही है और सूत्रों के अनुसार ऐसा भी मालूम पड़ा है कि उस भूमि पर कब्जा करवाने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने ही सहयोग किया है जो वहां प्रयोगशाला निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं उसमें अभी तक भूमि का आबंटन सीमांकन हो जाने के उपरांत भी ना तो वहां पर बाउंड्री वॉल खड़ी की गई है ना ही इसका डिजाइन बना है ना ही नक्शे स्वीकृत हुए टीएनसीपी से और नगर निगम से इसके विपरीत वहां पर एक सुलभ शौचालय जरूर बना दिया गया है। जबकि उसके लिए अभी तक केंद्र व राज्य सरकार से कहीं से भी प्रयोगशाला निर्माण के लिए धन का आवंटन ही नहीं हुआ है जब आवश्यक धन का आवंटन नहीं हुआ तो प्रयोगशाला केंद्र भवन बनने की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखाई देती और दूसरी तरफ चलित वेन जो है क्योंकि यह राजपत्र में इसका प्रकाशन नहीं हुआ है इसलिए अधिकृत नहीं है तो इस प्रयोगशाला खाद्य के नमूने भी अधिकृत नहीं हो सकते और ना ही उनके ऊपर कोई न्यायालयीन प्रकरण कायम किया जा सकता है इस प्रयोगशाला का प्रयोग केवल छोटे व्यावारी को चमका-धमका कर वसूली करने के लिए ही किया जा रहा है पूरे मध्यप्रदेश में उसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है जो कोई कार्यक्रमों की जांच कर उसके परिणाम दे सके।

www.samaymaya.com की साइट से समाचार पत्र की पीडीएफ डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256-37958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 94251-25569, 94795-35569